

रोजगार और निर्माण

टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वर्ष 2022-23 का बजट

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का बजट

सिंचाई क्षमता 65 लाख हेक्टेयर तक
पहुँचाने का लक्ष्य

प्रदेश में शिक्षकों और
आरक्षकों के पदों पर होगी भर्ती

सी.एम. राइज योजना के तहत प्रथम
चरण में 360 स्कूल होंगे प्रारंभ

भोपाल, वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने भोपाल स्थित विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण पर केंद्रित बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट चुनौतियों को विकास के अवसर में बदलने की दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के विकास को नया आयाम देगा। प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 13 हजार शिक्षक और 6 हजार आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। सूचना और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के चार महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्क स्थापित किये गये हैं। वहीं युवाओं को माइनिंग विधा में पारंगत करने के लिए सिंगरौली जिले में माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सिंचाई क्षमता का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए प्रदेश में वर्ष 2025 तक सिंचाई क्षमता 65 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में केन-बेतवा परियोजना के लिए 44 हजार 605 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं सड़क निर्माण के लिए 8 हजार 590 तथा सड़कों के संधारण के लिए 2 हजार 443 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी गांवों के घर घर को नल से जल प्रदाय किया जायेगा। जल जीवन मिशन के लिए 6 हजार 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में सी.एम. राइज योजना के तहत प्रथम चरण में 360 स्कूल प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है। इस योजना के लिए बजट में एक हजार 157 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा 9 मार्च 2022 को प्रस्तुत किए गये बजट भाषण के संपादित अंश यहां प्रकाशित किये जा रहे हैं।

वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह बजट प्रदेश के किसानों, गरीबों, महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों को समर्पित है। यह उन्हें समाज में सकारात्मक वातावरण प्रदान करने और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के अवसर देगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आमजन की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बनाई गई योजनायें सफल होंगी तथा प्रगतिशील प्रदेश की आधारशिला को और मजबूती प्रदान करेंगी। राज्य के सर्वांगीण विकास व नवनिर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारी सरकार समर्पित होकर कार्य कर रही है। हमने पिछले वर्षों में कई पड़ाव हासिल किए हैं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का सपना पूरा होने तक हम न रुकेंगे न थकेंगे।

सभी जिला चिकित्सालयों में गहन चिकित्सा इकाई उपलब्ध

वित्त मंत्री ने कहा कि विगत समय में कोविड का कहर चरम पर रहा है। कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिये प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना का वृहद स्तर पर विस्तार किया गया है। प्रदेश में कोविड से पहले 35 जिला चिकित्सालयों में गहन चिकित्सा इकाई उपलब्ध थी। अब यह सुविधा सभी जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध है। चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला चिकित्सालयों में गहन चिकित्सा इकाई में विस्तरों की संख्या 601 थी, जिसे सात गुना बढ़ाकर 4 हजार 446 किया गया है। इन स्वास्थ्य संस्थाओं में एल.एम.ओ. (Liquid Medical Oxygen) की क्षमता 89 मीट्रिक टन से चार गुना बढ़ाकर 395

मीट्रिक टन की गई है।

श्री देवड़ा ने कहा कि स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के साथ-साथ सुरक्षात्मक उपाय के रूप में टीकाकरण आवश्यक था। माननीय प्रधानमंत्री जी के “सबको वैक्सीन-मुफ्त वैक्सीन” लगवाने के अभूतपूर्व निर्णय को प्रदेश में पूरी प्रतिवद्धता से क्रियान्वित किया गया है।



अब तक 18 वर्ष की आयु से अधिक वर्ग के नागरिकों को 11 करोड़ 28 लाख 77 हजार से अधिक डोज लगाये जा चुके हैं। टीकाकरण का पहला डोज 98.03 प्रतिशत तथा दूसरा डोज 95.4 प्रतिशत लोगों को लगाया जा चुका है। 15 से 18 आयु वर्ग में प्रथम डोज कुल 85.56 प्रतिशत युवाओं को लगा दिया गया है, दूसरा डोज लगना प्रारंभ है। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर तथा पात्र व्यक्तियों को प्रीकोशन डोज लगाया जा रहा है।

श्री देवड़ा ने कहा कि पूंजीगत कार्यों में निवेश से अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को और सक्रियता, मजबूती व स्थिरता मिलती है। हमारी सरकार ने निरंतर पूंजीगत निवेश बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूंजीगत परिव्यय 30 हजार 2286 करोड़ रुपये था। कोविड की प्रथम लहर की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूंजीगत परिव्यय को बढ़ाकर 31 हजार 586 करोड़ रुपये किया। कोविड की द्वितीय एवं तृतीय लहर के बावजूद वित्तीय वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित अनुमान विगत वर्ष से लगभग 8 हजार 829 करोड़ अधिक होकर 40 हजार 415 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो कि एक कीर्तिमान है।

वर्ष 2022-23 के पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान को पुनः लगभग 21 प्रतिशत बढ़ाकर कुल 48 हजार 800 करोड़ रुपये

का प्रावधान प्रस्तावित है। यह निवेश, प्रदेश के विकास को नये आयाम देगा, साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

तीन हजार किलोमीटर नई सड़कों का किया जायेगा निर्माण

श्री देवड़ा ने कहा कि सड़कें मात्र आवागमन का माध्यम ही नहीं, अपितु प्रदेश के आर्थिक विकास, औद्योगिक उन्नति एवं रोजगार निर्माण का इंजन हैं। यातायात के नवीन मार्गों का निर्माण तथा सभी मार्गों को यातायात योग्य बनाये रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग द्वारा अब तक लगभग 2 हजार 200 किलोमीटर का सड़क निर्माण तथा उन्नयन और 1 हजार 150 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण कार्य किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 21 वृहद पुल तथा रेल्वे ओव्हर ब्रिज भी पूर्ण किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव में लगभग 3 हजार किलोमीटर के नवीन सड़क कार्य, लगभग 1 हजार 250 किलोमीटर का सड़क नवीनीकरण कार्य तथा 88 नवीन पुल निर्माण सम्मिलित हैं।

वित्त मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनवरी 2022 तक 3 हजार 48 किलोमीटर सड़कें एवं 140 पुलों का निर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अंतर्गत 4 हजार 584 किलोमीटर सड़कें एवं 180 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह जनवरी 2022 तक 618 किलोमीटर सड़कों के कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अंतर्गत 1 हजार 200 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2003 में लगभग 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। हमारी सरकार द्वारा विगत वर्षों में किये गये प्रयासों से आज कुल सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना लक्षित है।

उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लगभग 23 लाख 21 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 27 वृहद, 46

वित्तीय प्रबंधन का उत्तम उदाहरण है बजट - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्ष 2022-23 का बजट सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, के भाव से बनाया गया है। यह वित्तीय प्रबंधन का उत्तम उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य बनाते हुए बेहतर वित्तीय प्रबंधन से ऐसा बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा बधाई के पात्र हैं, यह बजट स्वागत योग्य है।



गौरवशाली, सम्पन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के स्वप्न और संकल्प को पूर्ण करने का बजट है।

श्री चौहान ने कहा कि यह बजट केवल अर्थशास्त्रियों और अधिकारियों ने ही नहीं बनाया अपितु यह जनता के सुझावों के आधार पर भी बनाया गया है। जनसामान्य से आमंत्रित कई सुझावों को बजट में सम्मिलित किया गया है।

मध्यम, एवं 288 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत लगभग 20 लाख 50 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 37 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

श्री देवड़ा ने कहा कि पानी की एक-एक बूंद का मोल क्या होता है, ये सब हमारी माताओं-बहनों और बेटियों से बेहतर कोई नहीं जानता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ कर देश में एक नई जल-क्रांति को जनम दिया है। पहले के समय में लोगों को पानी तक पहुंचना पड़ता था, लेकिन हमारी सरकार पानी को घर-घर लोगों तक पहुंचा रही है। जल-जीवन मिशन केवल घरों तक पानी पहुंचाने का अभियान नहीं, बल्कि विकेन्द्रीकरण और जन-भागीदारी का एक बड़ा आंदोलन है।

जल जीवन मिशन से सभी गांव को मिलेगा पेयजल

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के सभी ग्रामों के घर घर को नल से जल प्रदाय किये जाने के कार्य तीव्र गति से कराये जा रहे हैं। प्रदेश के 4 हजार से अधिक ग्रामों के शत-प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। वर्तमान में 47 लाख से अधिक परिवारों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। इस वर्ष कुल 11 हजार 190 करोड़ रुपये की 17 हजार 318 ग्रामों की एकल ग्राम नल-जल योजनाएं तथा 18 हजार 454 करोड़ रुपये की 16 हजार 853 ग्रामों की 75 समूह नल-जल योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों सहित सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि

उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने के साथ-साथ घरेलू एवं कृषि कार्य के लिये इस वित्तीय वर्ष में लगभग 21 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि प्रदेश के नागरिकों को बिजली सस्ती दर पर निरंतर मिल सके। प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2021 की स्थिति में विद्युत क्षमता बढ़कर 21 हजार 451 मेगावॉट हो गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि किसान प्रदेश के अन्नदाता हैं, भाग्य-विधाता हैं। किसानों का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकाओं में से एक है तथा खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना सरकार का ध्येय है। इतना ही नहीं, जब भी प्रदेश के किसानों पर कोई संकट आया है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी ताकत से किसानों के साथ खड़ी रही है।

हमारी सरकार के इस कार्यकाल में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 17 हजार करोड़ रुपये फसल उपार्जन में लगभग 66 हजार 684 करोड़ रुपये, शून्य प्रतिशत दर पर फसल ऋण लगभग 30 हजार करोड़ रुपये बिजली विलों पर सब्सिडी लगभग 30 हजार करोड़ रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10 हजार 337 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में लगभग 4 हजार 569 करोड़ रुपये आदि अनेक योजनाओं में लगभग एक लाख 72 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदेश के किसान भाई-बहनों को दी गई है।

(शेष पृष्ठ 14 पर)

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

अंदर के पृष्ठों पर

- **खेल चर्चा-** प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी-** देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं
- **चर्चा में-** प्रमुख चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **पिछला सप्ताह-** देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण



5 मार्च

भारतीय रेलवे ने किया

कवच तकनीक का सफल परीक्षण

● भारतीय रेलवे ने सुरक्षा तकनीकी कवच का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण



के दौरान दो ट्रेनों एक ही ट्रैक पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आमने-सामने आ गईं। दोनों ट्रेनों आपसी टक्कर से महज 380 मीटर पहले स्वतः रुक गईं। रेलवे ने बताया कि कवच तकनीक की मदद से ओवर स्प्रीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। इस तकनीक में किसी भी खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। इस तकनीक का उद्देश्य है कि ट्रेनों की स्पीड भले ही कितनी भी हो, लेकिन कवच तकनीक के चलते ट्रेनों टकराएंगी नहीं। रेलवे ने कहा कि कवच तकनीक हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। इस परीक्षण के दौरान रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एक ट्रेन के इंजन में सवार थे।

● नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने विदेश से एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। एनएमसी ने कहा कि विदेश से एमबीबीएस करने के बाद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (एफएमजीई) पास करने वाले विद्यार्थियों को देश में इंटरशिप करने के लिये इंटरशिप फीस नहीं देनी होगी। इन विद्यार्थियों को भी इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के समय स्टापेंड मिलेगा। कमीशन ने कहा कि कुछ विदेशी छात्र ऐसे भी हैं, जिनकी कोरोना महामारी अथवा यूक्रेन में युद्ध जैसी विपम परिस्थितियों के कारण इंटरशिप पूरी नहीं हो सकी है, वे बाकी इंटरशिप को भारत में पूरा करने के लिये आवेदन कर सकते हैं।

6 मार्च

नौसेना ने किया ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण

● भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी तक हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस



के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण आईएनएस चेन्नई से किया गया है। नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल ने एक विस्तारित रेंज को पार करने और जटिल युद्धाभ्यास करने के बाद सटीकता से अपने लक्ष्य को नष्ट किया। इस मिसाइल में कई एडवांस फीचर लाए गए हैं, जिससे मिसाइल की मारक क्षमता कहीं अधिक बढ़ गई है।

उल्लेखनीय है कि समुद्र से दागने के लिये ब्रह्मोस के चार वैरिएंट्स हैं। इनमें से युद्धपोत से दागे जाने वाला एंटीशिप वैरिएंट है और युद्धपोत से दागे जाने वाला लैंड अटैक वैरिएंट भारतीय नौसेना में ऑपरेशनल है।

● ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के समाधान के लिये छह सूत्री योजना पेश की है। जॉनसन ने इस संघर्ष को समाप्त करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नये सिरे से प्रयास करने की अपील की है। जॉनसन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सेना के बल पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों को फिरे से लिखने में किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देना चाहिये। जॉनसन ने कहा कि युद्ध का कूटनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिये।

7 मार्च

रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे खनिज समृद्ध क्षेत्र

● भारतीय रेलवे ने माल भाड़े से होने वाली आय को बढ़ाने के मद्देनजर खनिजों की बहुतायत वाले इलाकों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना बनाई है। रेलवे ने इसे मिशन हंगरी फॉर कार्गो नाम दिया है। इस मिशन के तहत रेलवे ने माल ढुलाई में हिस्सेदारी को 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम के तहत खनिज की बहुतायत वाले जिलों की पहचान करने के साथ ही खान से उत्पादित होने वाले खनिजों का विवरण तैयार किया जायेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मंत्रालय ने देशभर में 100 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाली खदानों के सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई है। माल ढुलाई के मामले में रेलवे ने जिन उत्पादों को प्राथमिकता दी है, उनमें कोयला, लोह अयस्क, बॉक्साइट और चूना पत्थर शामिल हैं।

● भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को कोरोना महामारी के दौरान ई-कॉमर्स की भूमिका पर चर्चा करने के लिये बैठक बुलाने का सुझाव दिया है। डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत श्री ब्रजेंद्र नवनीत ने पिछले महीने आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान दिये गये अपने वयान में इसका उल्लेख किया था। श्री नवनीत ने बताया कि डब्ल्यूटीओ के कई सदस्यों ने इस बारे में बात की कि कैसे ई-कॉमर्स ने कोरोना महामारी के चलते लगाये गये लॉकडाउन के दौरान उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मदद पहुंचाई है।

8 मार्च

एनडीए में महिलाओं को शामिल करना एक बड़ा नीतिगत फैसला

● केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिला कैडेट को शामिल करना एक बड़ा नीतिगत फैसला रहा है। सरकार ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों में पूर्व एनडीए महिला कैडेट को शामिल करने और तैनाती के लिये दीर्घावधि में जटिलताओं पर अध्ययन करने के लिये उसे कम से कम तीन महीने चाहिये। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एनडीए द्वितीय 2021 और एनडीए प्रथम 2022 के लिये शामिल की जाने वाली महिलाओं की संख्या के संबंध में एक हलफनामा भी दाखिल किया। हलफनामे के अनुसार, एनडीए के प्रत्येक पाठ्यक्रम में तीनों सेवाओं के लिये 370 रिक्तियां हैं, जिनमें से 208 को थलसेना में कमीशन मिलेगा, वहीं 120 को वायुसेना तथा 42 कैडेट को नौसेना में कमीशन मिलेगा।

● केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (एसएसएसवाई) को जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने इस योजना को जारी रखने के लिये 3274.87 करोड़

रुपये के आवंटन को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ दिये जायेंगे। इस योजना के तहत देशभर में 23 हजार 566 लाभार्थियों को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने एसएसएसवाई को जारी रखने का प्रस्ताव तैयार किया था।

9 मार्च

भारत में दो वर्ष बाद फिर शुरू होंगी नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

● भारत में लगभग दो वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय नियमित उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। केंद्र



सरकार ने 27 मार्च, 2022 से नियमित व्यावसायिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को शुरू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संबंधित पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श और कोरोना संक्रमण के मामलों में तीव्र गिरावट को ध्यान में रखते हुये हमने देश में 27 मार्च, 2022 से अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं फिर से शुरू करने का फैसला किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि इस फैसले के बाद एयर बवल व्यवस्था खत्म हो जायेगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान कोरोना महामारी से बचाव के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 23 मार्च, 2020 को कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं निलंबित करने का फैसला किया था।

● ईरान के अर्धसैनिक बल रिवाव्यूशनरी गार्ड ने एक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। यह ईरान का दूसरा सैन्य उपग्रह है, जिसे सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचाया गया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन आईआरएनए ने बताया कि यह उपग्रह शाहरुद रेगिस्तान से प्रक्षेपित किया गया है। हालांकि यह परीक्षण कब किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। यह प्रक्षेपण ऐसे समय में हुआ है, जब ईरान की वैश्विक शक्तियों के साथ परमाणु समझौते को लेकर वियना में चर्चा चल रही है।

10 मार्च

नीट-यूजी परीक्षा के लिये अधिकतम आयु सीमा हटाई गई

● भारत में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने की अब कोई आयु सीमा नहीं रहेगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आयोजित होने वाली नीट-यूजी परीक्षा के लिये अधिकतम आयु सीमा हटा दी है। एनएमसी ने कहा कि नीट-यूजी परीक्षा में न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष ही रहेगी। लेकिन अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। एनएमसी ने कहा कि वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा से यह नियम लागू होगा। उल्लेखनीय है कि पहले नीट यूजी परीक्षा के लिये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष तथा आरक्षित वर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष थी।

● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन (एनएलएमसी) के गठन की मंजूरी प्रदान की है। एनएलएमसी सार्वजनिक कंपनियों के साथ केंद्रीय विभागों की अतिरिक्त जमीन और संपदा के मुद्रीकरण

का काम करेगी। एनएलएमसी के गठन का प्रावधान मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में किया गया था। माना जा रहा है कि एनएलएमसी के गठन से सरकारी कंपनियों की बेकार पड़ी जमीन और भवन संपदा मुद्रीकरण के काम में तेजी आयेगी। इसके अलावा एनएलएमसी सरकारी कंपनियों की अतिरिक्त जमीन और संपदा के प्रबंधन का काम भी करेगी।

11 मार्च

रेलवे ग्रुप-डी कर्मचारियों की भर्ती के लिये अब होगी एक ही परीक्षा

● भारतीय रेलवे ने ग्रुप-डी कर्मचारियों की भर्ती के लिये होने वाली लेवल-1 की एक ही परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। पहले लेवल-1 में दो कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित की जाती थीं। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने लेवल-1 और एनटीपीसी (नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी) परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में

प्रदर्शनकारियों की सभी मांगें मानते हुये यह फैसला लिया है। बोर्ड ने इस मामले की जांच के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी।

समिति की सिफारिश और छात्रों की मांग के आधार पर आरआरबी ने कहा कि अब भर्ती में तय सीटों के 20 गुना अनुमात में उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा। आरआरबी ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को पहले ही योग्य घोषित किया जा चुका है, वे योग्य बने रहेंगे।

● केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री श्री नारायण राणे ने एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2022 के साथ एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एमएसएमई महत्वपूर्ण भूमिका है। एमएसएमई की योजनाओं से उद्यमियों को नये उद्यम स्थापित करने में मदद मिलेगी।

राज्य स्तर पर होगा कॅरियर मेले का आयोजन - उच्च शिक्षा मंत्री

भोपाल, पढ़ाई के साथ ही रोजगार का लाभ देने के लिए कॅरियर मेले का आयोजन सराहनीय कदम है। कॅरियर मेले में विद्यार्थियों के लिये एक सुनहरा अवसर है। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय में जिला स्तरीय 'कॅरियर अवसर मेले' का शुभारंभ करते हुये कही।

डॉ. यादव ने कहा कि पूर्व में कॅरियर मेले में तकनीकी क्षेत्र के बच्चों को प्राथमिकता मिलती थी। अब यह व्यवस्था बदल रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में भी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से युवाओं को अपने कॅरियर में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरोजिनी नायडू महाविद्यालय को नैक से एक ग्रेड प्राप्त है। ए++ ग्रेड पाने के लिए

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित फोटो : गुगल से साभार)

साप्ताहिक रोजगार और निर्माण

मैं विज्ञापन के लिए दरें

टैरिफ

क्रमांक	ब्लैक एंड व्हाइट रेट प्रति वर्ग सेंमी (sq Per cm)	रंगीन रेट प्रति वर्ग सेंमी (sq Per cm)
1. डीएवीपी (DAVP) रेट	17.76	24.86
2. कॉन्टैक्ट रेट	70.00	98.00
3. कमाशियल रेट	80.00	112.00

फुल पेज का आकार

चौड़ाई	-	25 सेंटीमीटर
लंबाई	-	37 सेंटीमीटर
कुल वर्ग सेंटीमीटर	-	925 वर्ग सेंटीमीटर



संपर्क करें:

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011

फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006

ईमेल : madhyam.rojgar@gmail.com Website : www.mpmadhyam.in

नोट : 1. 5% जीएसटी (GST) शुल्क अलग से देय होगा।

2. 4.5x5 सेंमी (cm) से कम का विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वर्ष 39, अंक 11

14.03.2022 से 20.03.2022

रोजगार और निर्माण



www.rojgaraurnirman.in

● प्रबंध संचालक

● सम्पादक

● कार्यकारी सम्पादक

● प्रभारी अधिकारी

● प्रबंधक

● आकल्पन

● वेबसाइट

- राघवेंद्र कुमार सिंह

- पुष्पेन्द्र पाल सिंह

- राजीव तिवारी

- नरेन्द्र कुमार बनवट (प्रसार एवं विज्ञापन)

- वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)

- हेमंत वायंगणकर, आशा रोमन,

- अरविन्द टोप्पो, सुशील लोंडगे

- आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोजगार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-

रोजगार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011

फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com

रोजगार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोजगार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्ति विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोजगार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण हो निराकरण - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आमजन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को आवेदक की बिना संतुष्टि के फोर्स क्लोज नहीं किया जाये। मुख्यमंत्री भोपाल स्थित मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने हरदा जिले के श्री अर्जुन सूरमा के प्रकरण में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मलय श्रीवास्तव से नल-जल योजना के कार्य में विलंब होने की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रकरण में तत्कालीन सब इंजीनियर ज्योति महोबिया और कार्यपालन यंत्री एस.के. पंवार को सस्पेंड करने के निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बिना सोर्स के कोई भी नल-जल योजना स्वीकृत नहीं की जाये। मुख्यमंत्री ने खंडवा जिले के श्री गंगाप्रसाद यादव के प्रकरण में विलंब होने का कारण जाना। उन्होंने कहा कि बच्ची को ढूँढ़ने में एक साल से अधिक समय क्यों लगा। इस पर एस.पी. खंडवा ने जायज कारण की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम् के श्री घनश्याम जमनानी के प्रकरण में भी विलंब का कारण जाना। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से अभी आवेदक को मार्कशीट नहीं मिली है। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को ऐसे प्रकरणों में समय पर मार्कशीट प्रदान करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसे 335 मामले लंबित हैं, जिनका समाधान एक सप्ताह में करें। मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले की सुश्री मालती कुशवाह के प्रकरण में राशि भुगतान में विलंब होने पर कहा कि पति की मृत्यु होने पर आवेदिका को समय पर राशि दी जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे जितने भी प्रकरण हैं उनमें शीघ्रता से कार्यवाही कर समय पर राशि दी जाये। प्रमुख सचिव, श्रम को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी कल्याणी बहन को पैसों के लिये भटकना नहीं पड़े। उन्होंने आवेदिका को 2 लाख रुपये की सहायता राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने एवं मानवीय दृष्टिकोण रखते हुये कलेक्टर को पूरी सहायता करने के निर्देश दिये। उन्होंने नगर परिषद में कार्य दिलाने के लिये भी कहा। मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले के श्री बंसीलाल के प्रकरण में लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा फोर्स क्लोज करने का कारण जाना। उन्होंने कहा कि बिना संतुष्टिपूर्ण समाधान के शिकायत फोर्स क्लोज नहीं हो। अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान को प्रकरण में संबंधित संयुक्त संचालक की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने रीवा के श्री अजय मिश्रा के प्रकरण में कलेक्टर से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकरण को फोर्स क्लोज क्यों किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रकरण से संबंधित प्रमुख अभियंता पीएचई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने खरगोन के श्री दीपक सिंह राजपूत के प्रकरण में प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा को लंबित प्रकरणों का निराकरण समय पर कराने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने मंदसौर के श्री राधेश्याम बंजारा के प्रकरण में विलंब होने का कारण पूछा। उन्होंने सेंट्रल बैंक के अधिकारी को पीएम स्वनिधि योजना सहित अन्य योजनाओं के लंबित प्रकरणों में शीघ्रता से कार्यवाही करने के निर्देश दिये। अन्य बैंकों के अधिकारियों को भी लंबित मामलों का निराकरण शीघ्रता से कराने के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिये प्रदेश के आम नागरिकों के कामों का त्वरित निराकरण कर निर्णय लिया जाता है। इससे प्रदेश के नागरिकों को अपने काम को करवाने में बेहद सुविधा होती है।

मशरूम कम कर सकता है अवसाद का जोखिम

अवसाद एक ऐसी तकलीफ है, जिससे पीड़ित होने पर व्यक्ति अपना सामान्य जीवन यापन नहीं कर पाता। इससे ग्रसित व्यक्ति पूरे समय एक ऐसी समस्या से तकलीफ में होता है, जिसमें व्यक्ति शरीर से तो स्वस्थ दिखता है, लेकिन वह मानसिक तौर पर बीमार होता है। अभी हाल ही में एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि अवसाद से बचने के लिये मशरूम कारगर तरीका साबित हो सकता है। मशरूम खाने वाले लोगों की एक व्यापक संख्या के विश्लेषण से पता चला है कि इसके सेवन से अवसाद का जोखिम कम होता है। हालांकि अवसाद और मशरूम के बीच इस संबंध पर अभी और अध्ययन किया जाना बाकी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अभी डेटा की सावधानी से व्याख्या की जानी चाहिये। शोधकर्ताओं का कहना है कि मशरूम के सेवन और अवसाद पर यह पहले बड़े अवलोकन संबंधी अध्ययनों में से एक है। इसमें 2005 से 2016 तक की अवधि के 24,000 से अधिक अमेरिकी वयस्कों के आहार और मानसिक स्वास्थ्य डेटा को शामिल किया गया। निष्कर्ष विभिन्न प्रकार के मशरूम के बीच अंतर नहीं करते हैं। लेकिन वे हेरिनियम एरीनेसियस प्रजाति के मशरूम पर हुये कई छोटे नैदानिक परीक्षणों के आधार पर हैं। यह मशरूम अवसाद और चिन्ता को कम करने में मदद कर सकते हैं। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के सार्वजनिक स्वास्थ्य वैज्ञानिक जोशुआ मस्कट का कहना है- 'यह अध्ययन मशरूम खाने के संभावित स्वास्थ्य लाभों की बढ़ती सूची में इजाफा करना है। हालांकि मशरूम में ऐसा क्या है, जो हमारी सेहत के लिये यह इतना अच्छा साबित होता है, यह बात अभी भी एक पहेली है।' सफेद बटन मशरूम को अमेरिका में सबसे ज्यादा खाया जाता है। मशरूम में विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह अवसाद को दूर रखने में मददगार साबित हो सकते हैं, हालांकि यह पता लगाने और साबित करने के लिये अभी कई नैदानिक परीक्षण और अध्ययनों की जरूरत है।

- देवेश तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस 15 मार्च

उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण विधिक और नैतिक दायित्व है



योजना आयोग इसके लिए पर्याप्त बजट अनुमोदित न कर दे। इसलिए उपभोक्ता मामले के विभाग ने देश में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने और और उसको मजबूत बनाने के लिए दसवीं योजना अवधि के दौरान दो सौ करोड़ रुपये का आवंटन किया और आज यह उपभोक्ता जागरूकता अभियान अत्यंत कारगर साबित हो रहा है।

इस योजना अवधि के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के परामर्श से दो सौ करोड़ रुपये का एक मीडिया प्लान भी बनाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण की इस कार्ययोजना के अन्तर्गत ही उपभोक्ता जागरूकता के लिए आकाशवाणी पर पन्द्रह मिनट का एक नियमित साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम और दूरदर्शन पर हाल ही में शुरू किया गया तीस मिनट का एक वीडियो कार्यक्रम प्रसारित रहा है। इसके अलावा, स्कूली बच्चों के लिए सीडी पर एक शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम भी तैयार किया गया है और समय समय पर मुद्रित प्रचार भी प्रचार पुस्तिकाओं के माध्यम से किया जाता है।

अधिकारों के संरक्षण में सहायक होगी हेल्पलाइन

उपभोक्ता कल्याण कोष की निधियों का उपयोग कर आईआईटी, दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थानों की सहायता से एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इससे उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता पैदा होगी। उपभोक्ताओं को टेलीफोन और व्यक्तिगत रूप से परामर्श प्रदान किया जा रहा और उपभोक्ता विवादों को कोर्ट से बाहर निपटाने में यह हेल्पलाइन सहायक हो रही है। हेल्पलाइन के लिए अपनाई जाने वाली क्रिया विधि में, प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से नियमित अन्तराल पर परामर्श और सहायता देने के लिए निःशुल्क टेलीफोन लाइनें और प्रशिक्षित जनशक्ति को भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण नीति विकसित की है, उसमें भी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से काफी मदद मिल रही है। इससे उपभोक्ताओं के प्राथमिकता वाले सरोकारों को भी सभी पक्षों द्वारा व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा रहा है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय और विभाग भी उपभोक्ताओं के हितों के प्रति अधिक जिम्मेदार हो गये।

उपभोक्ता के इन अधिकारों का संरक्षण जरूरी है

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस पर जो उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाये जाते हैं उन सभी में मुख्य रूप से उपभोक्ता के उन सभी अधिकारों की बात की जाती है, जिनका संरक्षण किया जाना है। उपभोक्ता के जीवन एवं सम्पत्ति के लिए हानिकारक सामान और सेवाओं की विक्री के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार इनमें सबसे अहम् है। उपभोक्ता जो वस्तु खरीदता है उस खरीदी गई वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और मूल्य के बारे में पूरी-पूरी जानकारी पाने का अधिकार दूसरा प्रमुख अधिकार है। इस अधिकार की जानकारी होने से उपभोक्ताओं को गलत व्यापार पद्धतियों से

बचाया जा सकेगा। जहां तक सम्भव हो विभिन्न प्रकार के सामान तथा सेवाएं उचित मूल्य पर सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचे इसका आश्वासन तीसरा प्रमुख अधिकार है। उपभोक्ताओं के हितों पर विचार करने के लिए बनाए गए विभिन्न मंचों पर उपभोक्ताओं का भी यथेष्ट प्रतिनिधित्व हो यह चौथा प्रमुख अधिकार है। अनुचित व्यापार पद्धतियों से यदि उपभोक्ताओं का शोषण होता है, तो ऐसे शोषण के खिलाफ निपटान का अधिकार उपभोक्ता का पांचवां अधिकार है। उपभोक्ता उपभोग करने वाली सभी प्रमुख वस्तुओं की सूचनाओं से अवगत हो अर्थात् वह एक सूचना सम्पन्न उपभोक्ता हो और इसके लिए जिस ज्ञान और कौशल की जरूरत होती है उसे प्राप्त करने का अधिकार उपभोक्ता का छठा अधिकार है। अपने उपभोक्ता अधिकार के लिए आवाज उठाने का अधिकार, उपभोक्ता का सातवां प्रमुख अधिकार है। उपभोक्ता के अन्य अधिकारों में से यह सात अधिकार उपभोक्ता के बुनियादी अधिकार कहे जा सकते हैं।

संरक्षण कानूनों में बदलाव से अब उपभोक्ता ज्यादा ताकतवर

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के कानूनों में केंद्र सरकार की ओर से किए गए बदलावों से आज उपभोक्ता पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ है। अब वह खरीदी गई वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य और उपयोग के बाद परिणामों को लेकर सतर्क रहता है। नतीजतन जिला उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग में औसतन हर साल एक हजार से ज्यादा शिकायतें पहुंच रही हैं। हर साल 15 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य भी उसे जागरूक करना है। केंद्र सरकार के 20 जुलाई, 2020 को कानून में किए गए संशोधन से उपभोक्ताओं के अधिकार बढ़े हैं। देश के प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता फोरम जिसे अब जिला उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग के नाम से जानते हैं उसके माध्यम से ग्राहक के अधिकारों की पूरी रक्षा की जाती है। फेसलों में भी उनके हर पहलू का ध्यान रखा जाता है। इस आयोग में जिले में बीमा के मामलों, मेडिकलेम, ओडी क्लेम, फाइनेंस कम्पनियों के मामले, मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट से जुड़े मामले, हाउसिंग बोर्ड, डॉक्टर्स, बैंकों और विल्डर्स द्वारा वादे के अनुरूप सुविधाएं नहीं देने आदि की शिकायतें ज्यादा आती हैं।

प्रत्येक जिले में दो जिला उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग हैं। एक में नगर निगम सीमा और दूसरे में नगर निगम सीमा से बाहर के उपभोक्ता संबंधित व्यक्ति या कम्पनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। जानकारों के अनुसार अब उपभोक्ता अपने गृह नगर में स्थित फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहले 20 लाख रुपये तक के मामले की सुनवाई जिला स्तर पर होती थी। एक करोड़ तक के मामले की सुनवाई राज्य स्तर और इससे अधिक की राशि के मामले की सुनवाई राष्ट्रीय स्तर पर होती थी। अब एक करोड़ रुपये तक के मामले जिला स्तर पर सुने जा सकेंगे। उपभोक्ता मामलों के जानकार यह मानते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण कानून में हुए बदलाव से ग्राहक की ताकत बढ़ी है। वह अपने वैधानिक अधिकार के लिए खुलकर सामने आने लगा है। उनकी सजगता के कारण ही कम्पनियां अपने उत्पाद के प्रति पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो रही हैं। ग्राहकों को न्याय भी त्वरित गति से मिल रहा है। कोरोना काल में प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, अब स्थिति सामान्य हो रही है।

राजा दुवे

(लेखक, जनसम्पर्क विभाग से सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं)

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास, जबलपुर संभाग
मकान नं. 46 शरद पुंज, गोरखपुर थाने के सामने
नर्मदा रोड गोरखपुर जबलपुर-482003 मध्यप्रदेश
आवेदन आमंत्रण की सूचना

जबलपुर संभाग के जिलों में 79 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, 200 आंगनवाड़ी सहायिकाओं तथा 06 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पूर्णतः अस्थाई एवं मानदेय आधारित पदों के लिए पात्र महिला अभ्यर्थियों से निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद संख्या	आंगनवाड़ी सहायिका पद संख्या	मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद संख्या	जिला कार्यालय का दूरभाष क्रमांक
1.	डिंडोरी	डिंडोरी	1	2	1	7644-234965
2.		अमरपुर	2	6	1	
3.		समनापुर	3	8	0	
4.		करंजिया	2	5	0	
5.		बजाग	1	8	0	
6.		मेहंदवानी	3	0	0	
7.		शहपुरा	0	4	0	
8.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	1	1	0	7792230512
9.		गोटेगांव	1	1	0	
10.		करेली	2	2	0	
11.		चांवरपाठा	1	6	0	
12.		चीचली	3	6	0	
13.		साईखेड़ा	0	1	0	
14.	मंडला	बिछिया	1	4	0	7642252373
15.		बीजाडांडी	2	6	0	
16.		घुघरी	2	5	1	
17.		मंडला	1	1	0	
18.		मवई	1	4	0	
19.		मोहगांव	3	5	0	
20.		नैनपुर	2	1	0	
21.		नारायणगंज	0	1	0	
22.		निवास	0	1	0	
23.	कटनी	कटनी शहरी	0	4	0	7622221232
24.		विजयराघवगढ़	0	4	1	
25.		रीठी	0	1	0	
26.		बहोरीबंद	0	1	0	
27.	बालाघाट	बैहर	0	2	1	07632241637
28.		विरसा	0	0	1	
29.		परसवाड़ा	1	9	0	
30.		बालाघाट	1	3	0	
31.		किरनापुर	0	3	0	
32.		लांजी	2	3	0	
33.		वारासिवनी	0	3	0	
34.		लालबर्वा	0	1	0	
35.		कटंगी	0	1	0	
36.		खैरलांजी	1	1	0	
37.		बालाघाट नवीन	1	0	0	
38.	सिवनी	सिवनी ग्रामीण-02	0	2	0	77692228191
39.		केवलारी	1	0	0	
40.		वरघाट	1	1	0	
41.		घंसौर	4	3	0	
42.		छपारा	0	2	0	
43.		धूमा	1	1	0	
44.	छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	2	2	0	7162243421
45.		चौरई	1	4	0	
46.		छिंदवाड़ा शहरी	0	4	0	
47.		परासिया-1	4	4	0	
48.		परासिया-2	1	5	0	
49.		पांडुर्णा	0	2	0	
50.		जुन्नारदेव-1	1	2	0	
51.		जामई-2	2	1	0	
52.		मोहखेड़	1	7	0	
53.		तामिया	1	0	0	
54.		सौंसर	0	3	0	
55.		हरई	5	13	0	
56.	जबलपुर	जबलपुर शहरी-01	2	0	0	7612623810
57.		जबलपुर शहरी-03	0	1	0	
58.		जबलपुर शहरी-04	1	2	0	
59.		जबलपुर शहरी-05	0	1	0	
60.		पाटन	1	2	0	
61.		कुण्डम	4	3	0	
62.		शहपुरा	2	5	0	
63.		वरगी	0	4	0	
64.		मझौली	1	3	0	
65.		पनागर	3	5	0	
66.		सिहोरा	2	4	0	
योग			79	200	06	

उपरोक्त चार्ट अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों की नामवार सूची एवं नियम निर्देश, शर्तें आवेदन का प्रारूप एवं अन्य अर्हताएं संबंधित जिला कार्यालय एवं संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। जिस ग्राम/वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी की गयी है, आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम, शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना चाहिये। संबंधित महिला आवेदक अपने पूर्णतः भरे आवेदन पत्र मय आवश्यक सहपत्रों सहित संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पूर्वान्ह 10.00 बजे से सायं

कार्यालय अधीक्षण यंत्री

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नर्मदापुरम मण्डल नर्मदापुरम

Office Email ID - seresnarmda@mp.gov.in, Office Phone No. 07574-250166
 क्र. 234/निविदा/ग्रायांसे/2022 नर्मदापुरम, दिनांक : 04.03.2022

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 06/2021-22 (प्रथम आमंत्रण)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से ऑनलाइन मोहरबंद प्रतिशत दर पर निविदायें फार्म “ए” (Appendix 2.10) पर ग्रायांसे संभाग नर्मदापुरम की म.प्र. लोक निर्माण विभाग के केंद्रीयकृत प्रणाली में समतुल्य/सक्षम श्रेणी में पंजीकृत सी श्रेणी ठेकेदारों से 2 कवर पद्धति में ग्रायांसे में प्रचलित एस.ओ.आर. दिनांक 04.01.2015 से एवं विद्युतीकरण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग में प्रचलित एस.ओ.आर. दर दिनांक 01.12.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) के आधार पर अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नर्मदापुरम मंडल नर्मदापुरम के कार्यालय में ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सिस्टम टेंडर नं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	निविदा की अनु. लागत (रु. लाख में)	अमानत राशि (रुपये में)	कार्य अवधि वर्षाकाल सहित (माह में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1.	2022_ RES_ 184577	स्व-सहायता समूह हेतु आजीविका भवन निर्माण कार्य ग्राम टेकापार (विद्युतीकरण सहित)	सोहागपुर	2794300/-	50000/-	09 माह	5000/-
2.	2022_ RES_ 184578	हाट बाजार निर्माण कार्य ग्राम- टिगरिया ग्राम पंचायत-खरखेड़ी (विद्युतीकरण सहित)	नर्मदापुरम	2821400/-	50000/-	09 माह	5000/-
3.	2022_ RES_ 184579	पिचिंग एवं गैवियन निर्माण कार्य ग्राम-गोरा ग्राम पंचायत-गोरा ज.पं.-माखननगर	माखननगर	3276600/-	50000/-	09 माह	5000/-
योग -				8892300/-	शब्दों में - अट्ठासी लाख बानवे हजार तीन सौ रुपए मात्र।		

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रण की निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती हैं :-

क्र.	विवरण	तिथि	समय
1.	निविदा ऑनलाइन प्रकाशित होने की तिथि	10.03.2022	17.30
2.	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की प्रारंभिक तिथि	11.03.2022	17.30
3.	ऑनलाइन विड प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	12.03.2022	17.30
4.	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि	24.03.2022	13.30
5.	ऑनलाइन विड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	24.03.2022	13.30
6.	ऑनलाइन निविदा खुलने की तिथि	25.03.2022	13.30

निविदा प्रपत्र (Tender Document) वेबसाइट <http://mptenders.gov.in> पर ऑनलाइन प्रकाशित एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे। निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किए जाएंगे। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

अधीक्षण यंत्री
 जी-23576/46736/2022 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नर्मदापुरम् मण्डल नर्मदापुरम्

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री

लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई

पांडवनगर जिला-शहडोल (म.प्र.)

E-mail : piushahdol@gmail.com

एनआईटी नं. - 06/2022/केन्द्रीयकृत निविदा/एपीडी/पी.आई.यू./248 रीवा, दिनांक : 25.02.2022
 निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. ब्यौहारी जिला शहडोल सिविल अस्पताल के द्वितीय तल में पी.आई.सी.यू. वार्ड का निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)

पोर्टल टेंडर आई.डी.	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (पीएसी रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	90 प्रतिशत अविवादित भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित
2022_PWPIU_ 187631_1	शहडोल	142.79	1,42,790/-	12500/-	09 माह (वर्षाकाल सहित)	भूमि उपलब्ध

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 2. ब्यौहारी जिला शहडोल के सिविल अस्पताल में 12 विस्तरीय हाईव्रिड आईसीयू/एचडीयू की स्थापना का कार्य (प्रथम तल पर)। (प्रथम आमंत्रण)

2022_PWPIU_ 187634_1	शहडोल	65.58	65580/-	10000/-	03 माह (वर्षाकाल सहित)	भूमि उपलब्ध
----------------------	-------	-------	---------	---------	------------------------	-------------

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 3. 06 विस्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतपुर ब्लॉक बुढ़ार जिला शहडोल का 30 विस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य (भूतल एवं प्रथम तल पर)। (प्रथम आमंत्रण)

2022_PWPIU_ 187635_1	शहडोल	483.14	4,83,140/-	15000/-	12 माह (वर्षाकाल सहित)	भूमि उपलब्ध
----------------------	-------	--------	------------	---------	------------------------	-------------

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 4. 06 विस्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निपनिया जिला शहडोल का 30 विस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य (भूतल एवं प्रथम तल पर)। (प्रथम आमंत्रण)

2022_PWPIU_ 187636_1	शहडोल	483.14	4,83,140/-	15000/-	12 माह (वर्षाकाल सहित)	भूमि उपलब्ध
----------------------	-------	--------	------------	---------	------------------------	-------------

- निविदा में संबंधित विड डॉक्यूमेंट वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
- निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निवदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
- निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 28.02.2022 समय 09.00 AM से दिनांक 14.03.2022 समय 6.00 PM तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
- निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

संभागीय परियोजना यंत्री
 लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू.,
 जिला-शहडोल (म.प्र.)
 जी-23397/46735/2022

06.00 बजे तक में विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि से 15 दिवस तक जमा कराकर निर्धारित प्रारूप में प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। संभागीय कार्यालय महिला एवं बाल विकास, जबलपुर संभाग में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

संभागीय संयुक्त संचालक
 महिला एवं बाल विकास जबलपुर संभाग
 जी-23346/46734/2022

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़ (म.प्र.)

Phone No. 07683-242321, E-mail : eepwdtikam@mp.nic.in

एनआईटी नं. - 17/2021-22/केन्द्रीयकृत

दिनांक : 04.03.2022

(द्वितीय निविदा आमंत्रण)

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-

क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. जतारा से पथरीगढ़ बहारूताल तक लंबाई 5.30 कि.मी.

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनुमा. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
2022_PWDRB_188678_1	टीकमगढ़	440.45	440450/-	15000/-	08 माह वर्षाकाल सहित
योग -		440.45	440450/-	15000/-	

1. निविदा से संबंधित विड डॉक्यूमेंट वेबसाइट <http://mptenders.gov.in/> पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।

2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।

3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 08.03.2022 समय 10.30 से दिनांक 22.03.2022 समय 05.30 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री

जी-23671/46750/2022

लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल : dme12001@yahoo.com, वेबसाइट : www.medicaleducation.mp.gov.in

दूरभाष क्र. : 0755-2557855

क्रमांक 320/4/प्रवेश/संघिशि/2022

भोपाल, दिनांक : 25.02.2022

विज्ञप्ति

समस्त नीट यू.जी. 2021 में पात्र (क्वालिफाईड) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि GOVERNMENT OF INDIA, DIRECTORATE GENRAL OF HEALTH SERVICES, NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI, F. No. U-11011/11/2021-MEC, Dated 22.02.2022 को जारी सूचना के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो "Covid warriors" जिनकी मृत्यु (Deceased) हो गई है के पुत्र अथवा पुत्री है के लिए देश के 05 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की 01-01 सीट रखी गई है।

पात्र अभ्यर्थी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश को इस संबंध में आवेदन कर सकते हैं आवेदन का प्रारूप एवं योजना की जानकारी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट medicaleducation.mp.gov.in एवं पोर्टल dme.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन मय आवश्यक अभिलेखों के साथ संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छठवीं मंजिल, सतपुड़ा भवन भोपाल में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17.03.2022 है।

जी-23374/46733/2022

संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय अतिरिक्त परियोजना संचालक

लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई

निर्माण भवन, प्लाट नं. - 27-28 अरेरा हिल्स, भोपाल

एनआईटी नं. -44/2021/निविदा/सा/एपीडी/

भोपाल, दिनांक : 28.02.2022

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. बैतूल जिले के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा छोड़े गये, छोटे-छोटे स्वीकृत कार्य, शेष कार्य एवं पी.जी. अंतर्गत कार्य की निविदा।

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
2022_PWPIU_187941_1	बैतूल	144.54	114549	12500	12 माह वर्षाकाल सहित
स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 2. भोपाल, जिले में रेड-क्रॉस अस्पताल भवन का पुनरू निर्माण कार्य।					
2022_PWPIU_188365_1	भोपाल	144.04	144040	12500	06 माह वर्षाकाल सहित
स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 3. सेंट्रल जेल भोपाल, में कोरोना वार्ड और लॉन्ड्री रूम का निर्माण कार्य।					
2022_PWPIU_188367_1	भोपाल	40.06	50000	5000	05 माह वर्षाकाल सहित
स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 4. शासकीय महाविद्यालय टिमरनी में 06 नग कक्षों का निर्माण कार्य।					
2022_PWPIU_182245_2	हरदा	327.85	327850	15000	12 माह वर्षाकाल सहित
स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 5. रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ रविशंकर वी.आई.पी. गेस्ट हाउस एट पचमढ़ी जिला नर्मदापुरम।					
2022_PWPIU_187981_1	नर्मदापुरम	513.88	513880	20000	03 माह वर्षाकाल सहित
स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 6. कंस्ट्रक्शन ऑफ 50 सीटर सीनियर बालक छात्रावास भवन पिपरिया-1 एवं पिपरिया-2 जिला होशंगाबाद।					
2022_PWPIU_187984_1	नर्मदापुरम	649.98	649980	20000	12 माह वर्षाकाल सहित
स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 7. लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. रायसेन में वर्ष 2022-23 हेतु निर्माणाधीन/नवीन स्वीकृत कार्यों हेतु डिजाईन ड्राईंग एवं डीपीआर कंसल्टेन्सी हेतु निविदा।					
2022_PWPIU_188421_1	रायसेन	5000	100000	12500	12 माह वर्षाकाल सहित
स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 8. विदिशा जिले अंतर्गत तहसील सिरोंज में शेष कार्य पी.जी. अंतर्गत सुधार कार्य एवं अन्य कार्य हेतु जोनल निविदा।					
2022_PWPIU_184645_1	विदिशा	105.03	105030	12500	12 माह वर्षाकाल सहित

1. निविदा से संबंधित विड डॉक्यूमेंट वेबसाइट <http://mptenders.gov.in> पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।

2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।

3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 28.02.2022 समय 10.30 से दिनांक 15.03.2022 समय 05.30 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

अतिरिक्त परियोजना संचालक

जी-23634/46738/2022

(मुख्य अभियंता) लो.नि.वि. पी.आई.यू. भोपाल

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास

जिला-बैतूल मध्यप्रदेश

E-mail : wcdbetu@nic.in, Phone No. - 07141-230305

क्रमांक-मबावि/OSC/2022/1098

बैतूल, दिनांक : 03.03.2022

आउटसोर्स एजेंसी चयन हेतु निविदा सूचना

महिला एवं बाल विकास विभाग बैतूल के अधीन संचालित योजना “बन स्टॉप सेंटर” बैतूल में आउटसोर्स के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने आउटसोर्स एजेंसियों के चयन हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

ई-निविदा प्रक्रिया की तिथियों का विवरण निम्नानुसार है -

1. आवेदन ऑनलाइन करने का दिनांक	05.03.2022
2. आवेदन ऑनलाइन जमा करने का दिनांक	15.03.2022 से 21.03.2022
3. ऑनलाइन जमा आवेदन की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने का दिनांक	23.03.2022
4. निविदा खोलने का दिनांक	25.03.2022

ई-निविदा दस्तावेज (मय आवेदन एवं शर्तें सहित) राशि रु. 500/- जमा कर शासकीय निविदा की वेबसाइट www.mptender.gov.in से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा की विस्तृत जानकारी/निविदा शर्तें निविदा प्रपत्र में दर्शित है, निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर बैतूल को होगा।

ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने के उपरांत हार्डकॉपी (निविदा की मूल प्रति) कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास बैतूल पुराना कलेक्टोरेट परिसर बैतूल में नियत तिथि को कार्यालयीन समय में जमा करना अनिवार्य होगा।

यह निविदा ई-प्रणाली के तहत एन.आई.सी. जिला-बैतूल के पोर्टल पर भी प्रकाशित की जावेगी जो एन.आई.सी. बैतूल की वेबसाइट <https://betul.nic.in> पर देखी जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी

जी-23581/46737/2022

महिला एवं बाल विकास, बैतूल (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग संभाग (भ/प) उज्जैन संभाग उज्जैन

website : www.mp.gov.in/pwdmp, email : eepwdujn@mp.nic.in, Phone -0734-2557725

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 22/व.ले.लि./2021-22

उज्जैन, दिनांक : 03.03.2022

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. उपसंभाग महिदपुर अंतर्गत महिदपुर से नागेश्वर तीर्थ मार्ग का मजबूतीकरण का कार्य।

टेण्डर आई.डी. क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्रमांक	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	ई.एम.डी. की राशि (राशि रुपयों में)	कार्य पूर्ण करने की समयावधि
2022_PWDRB_184291_1	उज्जैन	सिविल कार्य	द्वितीय आमंत्रण	111.95	111950	06 माह वर्षाकाल सहित
क्र. एवं कार्य का नाम :- 2. उपसंभाग खाचरौद अंतर्गत नागदा खाचरौद चिनौदा मार्ग का बी.टी. रिनीवल का कार्य।						
2022_PWDRB_184292_1	उज्जैन	सिविल कार्य	द्वितीय आमंत्रण	438.11	438110	04 माह वर्षाकाल सहित
योग -				550.06		

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 14.03.2022 सायं 16.30 बजे निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही किया जायेगा। पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा। अर्नेस्ट मनी एवं अन्य दस्तावेज केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किए जावेंगे।

कार्यपालन यंत्री

जी-23627/46739/2022

लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग उज्जैन

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड सिंगरौली (म.प्र.)

नि.आ.सू.क्र. 28 से 37/व.ले.लि./का.यं./लो.स्वा.यां./खण्ड/सिंगरौली/2022

दिनांक : 07.03.2022

पता - विजय बंधु पेट्रोल पम्प के पास, ई-मेल - eephedsin@rediffmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्न कार्यों हेतु निविदा का ऑनलाइन वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> पर आमंत्रित की गई है। ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21.03.2022 सायं 17.30 बजे तथा निविदा खुलने की तिथि 22.03.2022 सायं 17.30 बजे है। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

Name of Work :- Drilling of 10 Nos. 350/150/150 Dia 60 Meter deep Semi Gravel pack (Combind) Tubewells in various Block of District Singrauli (M.P.)

S. N.	NIT No.	Tender ID	PAC (Rs. In Lakhs)	E-EMD in Rs.	Cost of Tender in Rs.	No. of Calls
1.	28/2021-22	2022_PHED_188649_1	7.60	15200/-	2000/-	1st Call
2.	29/2021-22	2022_PHED_188651_1	7.60	15200/-	2000/-	1st Call
3.	30/2021-22	2022_PHED_188652_1	7.60	15200/-	2000/-	1st Call
4.	31/2021-22	2022_PHED_188653_1	7.60	15200/-	2000/-	1st Call
5.	32/2021-22	2022_PHED_188655_1	7.60	15200/-	2000/-	1st Call
6.	33/2021-22	2022_PHED_188657_1	7.60	15200/-	2000/-	1st Call
7.	34/2021-22	2022_PHED_188658_1	7.60	15200/-	2000/-	1st Call
8.	35/2021-22	2022_PHED_188660_1	7.60	15200/-	2000/-	1st Call
9.	36/2021-22	2022_PHED_188661_1	7.60	15200/-	2000/-	1st Call
10.	37/2021-22	2022_PHED_188659_1	7.60	15200/-	2000/-	1st Call

कार्यपालन यंत्री

जी-23676/46751/2022

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सिंगरौली (म.प्र.)

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री

लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

PHONE No. 07162-243214, E-mail : pwpdiu12cwa@gmail.com

एनआईटी नं.-07/2022/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण/पी.आई.यू./व.ले.लि. छिन्दवाड़ा, दिनांक : 04.03.2022
निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 1. तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा में आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

पोर्टल टेण्डर क्रमांक	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह वर्षाकाल सहित)	कार्यालय का नाम जहां ईएमडी एवं तकनीकी विड़ भौतिक रूप से प्राप्त की जावेगी।	90 प्रतिशत अविवादित एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित
2022_ PWPIU_ 188913_1	छिन्दवाड़ा	303.98	303980/-	15000/-	14 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 2. जिला छिन्दवाड़ा में आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188914_1	छिन्दवाड़ा	273.98	273340/-	15000/-	12 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	--------	----------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 3. ग्राम-मुजावरमाल (मोरडोंगरी) जिला छिन्दवाड़ा में आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188915_1	छिन्दवाड़ा	314.41	314410/-	15000/-	14 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	--------	----------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 4. परासिया, जिला छिन्दवाड़ा में शासकीय महाविद्यालय भवन हेतु वाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188917_1	छिन्दवाड़ा	62.46	62460/-	10000/-	06 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	-------	---------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 5. कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. छिन्दवाड़ा के अंतर्गत परफॉर्मस गारंटी के अंतर्गत जोनल निविदा बाबत (पांचवा आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188918_1	छिन्दवाड़ा	90.00	90000/-	10000/-	12 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	-------	---------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 6. ग्राम चांवलपानी/झिरपा, जिला छिन्दवाड़ा में आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास भवन का निर्माण कार्य (द्वितीय आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188919_1	छिन्दवाड़ा	597.59	597590/-	20000/-	16 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	--------	----------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 7. छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों हेतु सुपरविजन एवं क्वालिटी कंट्रोल (एस.क्यू.सी.) (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188920_1	छिन्दवाड़ा	231.09	231090/-	15000/-	24 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	--------	----------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 8. ग्राम-झिरना जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188921_1	छिन्दवाड़ा	349.44	349440/-	15000/-	14 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	--------	----------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 9. ग्राम-टुमरागढ़ी जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188922_1	छिन्दवाड़ा	343.02	343020/-	15000/-	14 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	--------	----------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 10. ग्राम-खुलसान जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188924_1	छिन्दवाड़ा	349.44	349440/-	15000/-	14 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	--------	----------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 11. ग्राम-हिनोतिया जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188925_1	छिन्दवाड़ा	370.99	370990/-	15000/-	14 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	--------	----------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 12. ग्राम-निमोटी जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188926_1	छिन्दवाड़ा	361.12	361120/-	15000/-	14 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	--------	----------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 13. तहसील-बिष्टुआकला जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188927_1	छिन्दवाड़ा	354.02	354020/-	15000/-	14 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	--------	----------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 14. ग्राम-इटवा जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188929_1	छिन्दवाड़ा	347.90	347920/-	15000/-	14 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	--------	----------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 15. ग्राम-बाम्हनवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

खण्ड छिन्दवाड़ा, चतुर्थ निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा जारी करने का दिनांक : 09.03.2022

निम्नलिखित कार्य की निविदा प्रक्रिया ई-प्रोक्योरमेंट ई-टेंडरिंग पद्धति से पोर्टल <https://www.mptenders.gov.in> पर आमंत्रित है निविदाओं हेतु निविदा प्रपत्र डाउनलोड/क्रय करने की दिनांक 09 मार्च 2022 समय 10.30 बजे से प्रारंभ है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का नाम :- छिंदवाड़ा जिले के खण्ड छिंदवाड़ा अधीनस्थ विकासखण्ड चौरई के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत विद्यमान (स्थापित) नलजल योजनाओं में प्रावधान अनुसार 50, 75, 100 कि.ली. जल क्षमता एवं 12 मीटर ऊंचाई युक्त आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी 20 कि.ली. जल क्षमता सम्पवैल निर्माण कार्य विभिन्न प्रकार एवं व्यास के पाईप लाईन बिछाने एवं जोड़ने रेडीमेट मिनी पंप हाउस विक्री मेसोनरी वाल्व चेम्बर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण पावर पंप स्थापना विद्युतीकरण तथा रेट्रोफिटिंग कर शत प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम शुद्ध पेयजल व्यवस्था समस्त आवश्यक सामग्री सहित कार्य पूर्ण होने के पश्चात 90 दिन ट्रायल-रन कमिश्निंग कार्य। (As per BOQ)

ई- टेंडरिंग क्रमांक	निविदा क्रमांक दिनांक	विकास खंड	अनु. लागत (रु. लाख में)	अमानत राशि रुपये	निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि समय	निविदा खोलने की नियत दिनांक	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की समय अवधि
2022- PHED- 189262-1	98/ 2021-22 Dt. 09.03.22	चौरई	342.97	342970	15000/-	23.03.22 5.30 PM	25.03.22 2.00 PM	नवीन केन्द्रीकृत पद्धति पर सक्षम श्रेणी में पंजीकृत	9 माह वर्षाकाल सहित

निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क, केश-कार्ड, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड अथवा इन्टरनेट बैंकिंग एकाउंट के माध्यम से उपरोक्त वेबसाइट पर भुगतान कर केवल ऑनलाईन पर ही क्रय किए जा सकते हैं।

विस्तृत निविदा एवं अन्य जानकारी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

सदस्य सचिव

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन तथा

जी-23692/46754/2022

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, छिंदवाड़ा, म.प्र.

कार्यालय प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल - ceproc.encwrdbpl@nic.in

फोन - 0755-2767635, फैक्स - 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 885/2021-22/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ भोपाल, दिनांक : 09.03.2022

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र दिनांक 06.04.2022 को 17:30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

सं. क्र.	निविदा क्रमांक	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2022_WRD _189542	टर्न की पद्धति पर :- रोशिया लघु तालाब मिट्टी बांध एवं नहर का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परंतु उस तक सीमित नहीं।	खरगोन	1442.23

जी-23686/46755/2022

अधीक्षण यंत्री (प्रोक्योरमेंट)

का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188930_1	छिन्दवाड़ा	370.65	370650/-	15000/-	14 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	--------	----------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 16. ग्राम-कुकरपानी जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188932_1	छिन्दवाड़ा	354.02	354020/-	15000/-	14 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	--------	----------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 17. ग्राम-बिजोरी पठार जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188934_1	छिन्दवाड़ा	349.44	349440/-	15000/-	14 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	--------	----------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 18. तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा में नवीन शास. कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188935_1	छिन्दवाड़ा	369.86	369860/-	15000/-	14 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	--------	----------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 19. ग्राम-मोया जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188936_1	छिन्दवाड़ा	358.94	358940/-	15000/-	14 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	--------	----------	---------	-----------------------------	---	---

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 20. राजस्व विभाग के अंतर्गत नवीन कार्यालय भवनों में फर्नीचर लगाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने बाबत। (1) (जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत 05 उपतहसील भवन-नांदनवाड़ी, नवेगांव, बटकाखापा, पांजरा एवं दमुआ) (2) (जिला सिवनी के अंतर्गत 02 उपतहसील भवन-उगली एवं चमारीखुर्द) (प्रथम आमंत्रण)

2022_ PWPIU_ 188937_1	छिन्दवाड़ा	21.43	50000/-	5000/-	02 माह वर्षाकृतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
-----------------------------	------------	-------	---------	--------	-----------------------------	---	---

- निविदा से संबंधित विड़ वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
- निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/केशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
- निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 07.03.2022 एवं समय 09:00 से दिनांक 21.03.2022 समय 18:00 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
- निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

संभागीय परियोजना यंत्री

लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. छिन्दवाड़ा

जी-23714/46752/2022

समूह -1 उपसमूह -1 के अंतर्गत जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रक)(कार्यपालिक) पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा -2022 एवं
समूह -2 उपसमूह -1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी एवं सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के (कार्यपालिक) पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा -2022 के संबंध में सूचना

आवेदन पत्र भरने की तिथि :
16 मार्च से 30 मार्च 2022 तक

ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी

आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि:
16 मार्च से 04 अप्रैल 2022 तक

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
26 व 27 अप्रैल 2022 मंगलवार व बुधवार	प्रथम	प्रातः 07:00 से प्रातः 08:00 बजे तक	प्रातः 08:50 से प्रातः 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से दोपहर 12:00 बजे तक (3 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:30 से दोपहर 01:30 बजे तक	दोपहर 02:20 से दोपहर 02:30 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:30 से शाम 05:30 बजे तक (3 घंटे)

परीक्षा शहर :- भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना, रतलाम

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. परीक्षा की विस्तृत नियमपुस्तिका बोर्ड की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध है, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों / जानकारी का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे।
2. वेबसाइट www.peb.mponline.gov.in के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है।
3. परीक्षा शुल्क:

अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए	रु 500/- प्रति प्रश्न पत्र
अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए)	रु 250/- प्रति प्रश्न पत्र
सीधी भर्ती - बैकलॉग	कोई शुल्क नहीं
कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क	रु 60/-
रजिस्टर्ड सिटिजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क	रु 20/-

विशेष निर्देश :

1. दो पृथक- पृथक परीक्षाओं हेतु एक आवेदन पत्र पर आमंत्रित किया जा रहा है। अतः आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपनी योग्यतानुसार दोनों परीक्षाओं हेतु विकल्प भर सकता है। जिसके लिए प्रति प्रश्न पत्र (परीक्षा) अनुसार परीक्षा शुल्क देय होगा।
2. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
3. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यू.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित(verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
4. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड की छायाप्रति / आधार नंबर/ आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
5. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार वेबड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अतः अभ्यर्थी परीक्षा के समय आधार सत्यापन आनलॉक कर ही उपस्थित होवे।
6. परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने पर अभ्यर्थियों की प्रवेश पात्रता नहीं होगी।
7. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
8. परीक्षा केंद्र पर आवेदक को कला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पी.ई.बी. द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्त प्रक्रिया के दौरान सम्बंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित Online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।
11. उपरोक्त सभी पदों के लिये अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
12. विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया/सहारिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करे (ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बैगा, सहारिया एवं भारिया से सम्बंधित सभी कण्डिकाये विलोपित मान्य होगी)।
13. कोविड -19 महामारी के परिपेक्ष्य में शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

विशेष नोट : बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा तिथि / परीक्षा पाली / शहरों / केंद्रों एवं अन्य विन्दुओं में परिवर्तन कर सकता है।

विज्ञापन क्र. 05 / 2022



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

"चयन भवन " मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011 फोन नं. : +91-0755-2578801-02, FAX : +91-0755-2550498, website : www.peb.mp.gov.in

R-46749/2022

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
Block-II, 5th Floor, Paryawas Bhawan, Bhopal M.P. 462011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER EL-57

No./3539/22/D-12/MPPRDA/2022 Bhopal, Dated : 09.03.2022
Online Percentage rate Tenders are invited for "Shifting/Raising of High Voltage (HV)/Medium Voltage (MV)/Low Voltage (LV) lines and poles from alignment of PMGSY/CMGSY Road from contractors having 'A' class valid license issued by Madhya Pradesh Licensing Board (Electrical) and registered with MPPWD in appropriate class of contractors on e-procurement portal <https://www.mptenders.gov.in>.
Contractors are to quote rate in percentage below/above or at par of the estimated rates given in BOQ including all Taxes except GST.

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1.	Dhar	4	18385335.00

1. Tender document can be purchased and submitted only online from the above website from **10.03.2022 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed NIT and tender document on the above mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. Madhyam/103955/46745/2022 (TENDER)



मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-1, भदभदा रोड, भोपाल
क्र./274/तशा/प.यं./2022 दिनांक 09.03.2022

प्रेस विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा भोपाल जिले में विभिन्न मरम्मत/उन्नयन कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदा क्रमांक (1) 2022_MPPHC_189457_1, (2) 2022_MPPHC_189458_1 हेतु निविदा प्रपत्र दिनांक **21.03.2022 समय 17.00 बजे तक** खरीदे जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal : www.mptenders.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
म.प्र. माध्यम/103962/46746/2022 परियोजना यंत्री



म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-02, डी-16, कचनार सिटी, विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.) 482002
Email : mpphcjabalpur2@gmail.com

निविदा विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र.-02 के अंतर्गत निविदा क्रमांक 31/2021-22 कोतवाली परिसर (डबल स्टोरी) के ब्लॉक क्र.-01 से 06 के आवास क्र. ए-01 से एफ-04 में मरम्मत का कार्य जिला-शहडोल (ऑनलाइन निविदा क्र. 2022_MPPHC_189595) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक **21.03.2022 तक खरीद कर दोपहर 12:00 बजे तक** स्विट किये जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal : <https://www.mptenders.gov.in> पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
म.प्र. माध्यम/103974/46748/2022 परियोजना यंत्री



मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, भदभदा रोड संभाग क्रमांक-03 भोपाल
Mobile No. 9425601545, ई-मेल : mpphidcbpl3@gmail.com
क्र.-मप्रपुआअविनि/199/पयं/तशा/2022 भोपाल, दि. : 08.03.2022

निविदा आमंत्रण सूचना

वाह्य विद्युतीकरण कार्य अर्द्धशहरी पुलिस थाना मोहदा जिला बैतूल में 11/0.4 KV, 1x25 KVA, 11 KV शिरोपरी लाइन कार्य के लिए निविदा क्रमांक-17/2021-22 (टेण्डर क्र.-189117) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक **15.03.2022 समय 5.00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं दस्तावेज अपलोड किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal : <https://www.mptenders.gov.in> पर देखे जा सकते हैं।
म.प्र. माध्यम/103933/46741/2022 परियोजना यंत्री



म.प्र. पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

कार्यालय परियोजना यंत्री, डी-5/2, एम.आय.जी., महाश्वेता नगर, इस्कॉन मंदिर के सामने, उज्जैन (म.प्र.), Email : mpphcl_ujjain@yahoo.in
फोन नं. 0734-2527715, मोबा. 9406808103
क्र. 285/पय/मप्रपुहाइडेकालि/22/उज्जैन दिनांक 09.03.2022

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 28 एवं 29/2021-22

मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, संभाग उज्जैन के अंतर्गत निविदा क्रमांक 28/2021-22 दिनांक 09.03.2022 के अंतर्गत 400 मीटर सिंथेटिक एथेलेटिक ट्रेक, नानाखेड़ा स्टेडियम, उज्जैन (टॉप लेयर्स ओव्हर सबग्रेड) कार्य एवं निविदा क्रमांक 29/2021-22 दिनांक 09.03.2022 के अंतर्गत शामगढ़ जिला मंदसौर में सिविल अस्पताल के उन्नयन कार्य की ऑनलाइन निविदा आईडी क्र. 2022_MPPHC_189312, 2022_MPPHC_189313 कुल 2 निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन दिनांक **09.03.2022 17.00 बजे से** क्रय किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal: <https://www.mptenders.gov.in> पर देखे जा सकते हैं।
म.प्र. माध्यम/103947/46742/2022 परियोजना यंत्री

OFFICE OF THE, KRISHI UPAJ MANDI SAMITI DEVENDRA NAGAR, DISTT PANNA (M.P.)

No./Mandi/Nirman/21-22/265 Devendra Nagar, Dated : 09.03.2022

NOTICE INVITING TENDER (Second Call)

Online Percentage Rate E-Tenders are invited from contractors registered with the Office of the Engineer in Chief, M.P. Public Works Department, Government of Madhya Pradesh (Centralized Registration Cell) for System Tender Number 189386, Construction of 33 Nos Sundry Shop at Mandi yard Devendra Nagar Distt. Panna (M.P.), IInd Call. Hard copies of technical bid documents with EMD & Financial offer as per Detailed NIT to be received online 30.03.2022 up to 17.30 Hrs. and Only online Portal and It is to be Submitted physically at the time of Agreement in original. Bidders are required to offer their bids exclusive of applicable GST. the GST shall be paid by the department, to contractor separately.
The tender documents can be obtained online on the <http://mptenders.gov.in> as per the Notice Published on the above Portal and detailed information can also be seen on website www.mpmmandiboard.gov.in
Note : Any corrigendum in this NIT, if required, shall be displayed only in our above portal regarding any matter included in this NIT or otherwise. Other details of Construction/Development works and locations & key dates can also be seen on our website www.mpmmandiboard.gov.in
M.P. Madhyam/103954/46744/2022 SECRETARY

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryawas Bhawan, Bhopal M.P.-462011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

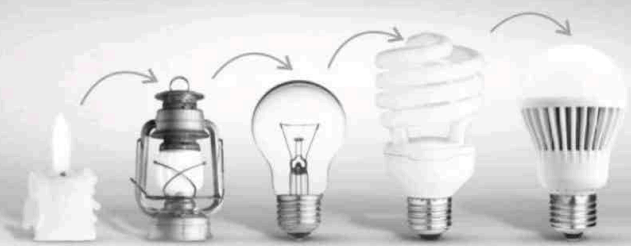
NOTICE INVITING TENDER No. 979 DEPOSIT WORK (DW-JP)

No./3595/22/D-12/MPPRDA/2022 Bhopal, Dated : 10.03.2022
Online Tenders for Construction of Rural Roads/CDs with two years maintenance are invited on the E-Procurement System portal <https://www.mptenders.gov.in> as detailed below :
● Name of work : Deposit Work (DW-JP)

S. No.	Name of District	No. of Package	Total PAC (In Rs.)
1	Rewa	1	1668000.00

1. Tender document can be purchased and submitted only online from the above website from **11.03.2022 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document for construction & maintenance of rural roads/Bridges Sept. 2017 on the above-mentioned portal and concerned PIU.

Madhyam/103963/46747/2022 CHIEF GENERAL MANAGER



Dear Educators

Unleash your untapped potential & evolve to greater heights of your career
@ All NEW IIST, IIP & IIMR

INVITING APPLICATIONS



**Indore Institute of
Science & Technology**

(Principal & Professor / Associate Professor / Assistant Professor)

Engineering : CSE, AI & ML, IT, ECE(Embedded System/Communication), Civil, Mechanical(Machine Design), Chemical,
Mathematics, Physics, Chemistry & English

Technical Trainers:

Civil: (Primavera, MS Project, E-Tabs, WaterGEMS, MX ROAD) | Mechanical: (Solidworks, CATIA, ANSYS)

Chemical: (Process Safety & Hazards Management, Membrane Separation Techniques, Fuel Cell, Nano Technology, Catalysis & Reaction,
Heterogeneous Reactions) | ECE: (MATLAB/PYTHON, ARM Controller / Raspberry / Arduino-Embedded System, Humanoid Robot, Analog
Circuit Design) | CSE, AI & ML, IT: (iOS 12 & Swift 4 or higher, Android App Development-REST API, JSON, XML, Node.js, ReactJS, AngularJS,
Python-Web Development Framework, Django, Flask, Machine Learning Libraries) | Soft Skill Trainer

Eligibility & Qualifications as per AICTE / UGC / Code 30 of RGPV norms.



**Indore Institute of
Pharmacy**

(Principal & Professor / Associate Professor / Assistant Professor)

Pharmaceutical-Chemistry, Pharmaceutics, Pharmacology, Pharmacognosy, Quality Assurance, Pharmaceutical Bio-Technology

Technical Trainers: Clinical Research, Pharmacovigilance, Patent, Drug Regulatory Affairs, Sophisticated Instruments Handling

Eligibility & Qualifications as per AICTE / UGC / Code 30 of RGPV / PCI norms.



**Indore Institute of
Management & Research**

(Principal & Professor / Associate Professor / Assistant Professor)

M.B.A. : HR, Marketing, Finance, Production, IT, Business Analytics

UG Courses : B.B.A., B.B.A.(Foreign Trade), B.Sc. (Stat, Math, Comp. Science), B.Com.(Hons.)

Technical Trainers: M.B.A.: (Digital Marketing, Financial Modeling, MS Office & Database Management System, Six Sigma
& lean Project Management, Logistics & Documentation for Foreign Trade, Retail Management

Eligibility & Qualifications as per AICTE / UGC / Code 28 of DAVV norms.

Non Teaching Positions

GM-Finance/Accounts, Administrative Officer, Placement Officer, Senior Marketing Officer, Purchas Officer, Sr. Marketing Executive,
Office Superintendent, Graphic Designer, Lab Technician, Store-in charge, Computer asst, Lab assistant, Office Asst, Transport Manager,
Electrical Supervisor, Bus Mechanic, Bus Driver, Bus Maintenance Supervisor (Mechanical & Electrical), Electrician, Gardener.

(Apply Within 10 days)

Affiliated to - RGPV(Bhopal) | DAVV(Indore) & Approved by - UGC | AICTE(New Delhi) | PCI(New Delhi) | DTE(MP)

IIST Campus, Opp IIM, Rau Pithampur Road, Indore - 453331

registrat@indoreinstitute.com

R-46740/2022

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Govt. of M.P. Panchayat & Rural Development Department)
Block-2, Vth Floor, Paryawas Bhawan, Arera Hills, Jail Road, Bhopal-462011

Selection of Campaign Agents (CAs) for Implementing Road Safety Awareness Campaign in Madhya Pradesh under Community Participatory Road Safety Program (CPRSP)

RFP No. : 3537/WB/MPRRDA/

Date : 09.03.2022

The Government of Madhya Pradesh (hereinafter called "Borrower") has received financing from the World Bank (the "Bank") in the form of a "loan" (hereinafter called "loan" toward the cost of Madhya Pradesh Rural Connectivity Project.

The Client now invites proposals for Selection of Campaign Agents (CAs) for Implementing Road Safety Awareness Campaign in following districts of Madhya Pradesh under Community Participatory Road Safety Program (CPRSP) on e-procurement portal <https://mptenders.gov.in> from 01.04.2022 after 11:00 Hrs. in the following lots :

S.No.	District	Lot No.	Blocks included in the Lot	Contract Period
1	Dhar	1	Gandhwani, Manawar, Umarban & Dharampuri, Nalchha	9 Months
		2	Khuski, Nisarpur, Bagh & Dahi	9 Months
		3	Tirla, Dhar, Sardarpur & Badnawar	9 Months
2	Indore	4	Depalpur, Sawer & Mhow	9 Months
		5	Indore	9 Months
3	Datia	6	Bhander, Seondha & Datia	9 Months

The RFP may be viewed, downloaded and submitted up to 12.04.2022, 15:00 Hrs. from the e-procurement portal.

M.P. Madhyam/103949/46743/2022

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)



INDORE MAHAVIDYALAYA

Approved by Higher Education, Bhopal (M.P.) & Affiliated by Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.)

Courses Offered • B.Com (Plain) • B.Com (Computer Application) • B.B.A. • B.C.A. • B.Sc. (Computer Science) • B.Sc. (Electronics) • B.S.W. • M.S.W. • B.A.

FACULTY REQUIRED

• Principal • H.O.D. • Associate Professor • Assistant Professor • Professor
• Administrative Officer • Librarian • Computer Operator • Lab Operator
• Health and Physical Education / Sports Teacher • Arts / Music Teacher

Qualification for all above shall be strictly as per Higher Education Department Bhopal, UGC & Devi Ahilya Vishwavidyalaya norms under college code 28.

To apply send your CV to college email or visit campus within 7 days.

Address : Jambudi Hapsi, Indore (M.P.) Contact : 9522187222, 8103034534

Email ID : hrimv2000@gmail.com

R-46756/2022



**कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति
जिला-बैतूल (म.प्र.)**

क्र./मंडी/निर्माण/21-22/1305

बैतूल, दिनांक : 08.03.2022

निविदा आमंत्रण सूचना

प्रमुख अभियंता म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त (केंद्रीयकृत पंजीयन प्रणाली) पंजीकृत निविदाकारों से प्रतिशत दर आधार पर सिस्टम निविदा क्रमांक 2022_MPSAM_189657_1, 2022_MPSAM_189659_1, 2022_MPSAM_189660_1, 2022_MPSAM_189663_1, 2022_MPSAM_189664_1 के अंतर्गत ऑनलाइन निविदाएं दिनांक 12.04.2022 को शाम 5.30 बजे तक एवं भौतिक रूप से दिनांक 19.04.2022 को शाम 5.30 बजे तक जरिये स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से (वित्तीय ऑफर को छोड़कर) आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल <https://mptenders.gov.in> पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmmandiboard.co.in पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट :- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/103982/46757/2022

सचिव

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
Block-IIInd, 5th Floor, Paryawas Bhavan
Arera Hills, Bhopal (M.P.)-462011

NOTICE INVITING BIDS FOR DPR PREPARATION (E-PROCUREMENT NOTICE)

No./3668/22/D-12/DPR-Cons./PMGSY-III/MPRRDA/22
Bhopal, Date : 11.03.2022

Online Bids are invited from the reputed Consultants for preparation of DPR of rural roads/Bridge under PMGSY-III as per details given below :-

- District - 1 Narsinghpur
- District - Damoh
- Total - Length - 20.00 km.

1. Last date for Bid Submission is 14.03.2022 upto 17:30 hrs.
2. Other details & Conditions may be seen in the detailed NIT, Tender Document for preparation of DPR of Roads/Bridges under PMGSY-III Sep. 2019 amended upto date available on E-Procurement System portal <https://www.mptenders.gov.in>.

CHIEF GENERAL MANAGER

M.P. Madhyam/103990/46759/2022

(TENDER)

**कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति खरगोन
जिला- खरगोन (म.प्र.)**

क्र./मंडी/नि./2021-22/2316

खरगोन, दिनांक 09.03.2022

निविदा आमंत्रण सूचना

प्रमुख अभियंता म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त (एकीकृत पंजीयन प्रणाली) पंजीकृत निविदाकारों से प्रतिशत दर आधार पर निविदा क्रमांक 2022_MPSAM_189330, निविदा क्रमांक 2022_MPSAM_189331, निविदा क्रमांक 2022_MPSAM_189333 एवं निविदा क्रमांक 2022_MPSAM_189334 के अंतर्गत ऑनलाइन निविदाएं दिनांक 31.03.2022 को शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल <http://www.mptenders.gov.in> पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट :- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/103983/46758/2022

सचिव

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryawas Bhawan, Bhopal M.P.-462 011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 980 UPG & DMF

No./3694/22/D-12/MPRRDA/2022

Bhopal, Dated : 11.03.2022

Online Tenders for Construction of Rural Roads/CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal <https://www.mptenders.gov.in> as detailed below.

- Table No. 1 : Name of Work : Up-gradation (UPG)

S. No.	Name of District	No. of Package	Total PAC (In Rs.)
1.	Datia	1	2963000.00
2.	Damoh	1	11976000.00
3.	Dewas	1	6450000.00
4.	Jabalpur	1	17154000.00

- Table No. 2 :- Name of Work : District Mining Funds (DMF)

S. No.	Name of District	No. of Package	Total PAC (In Rs.)
1.	Singrauli	3	119907000.00

1. Tender document can be purchased and submitted only online from the above website from 15.03.2022 from 17:30 hrs.
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document for construction & maintenance of rural roads/Bridges Sept. 2017 on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER

M.P. Madhyam/104002/46762/2022

(TENDER)



**मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं
अधोसंरचना विकास निगम**

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-01, 1558 ऋषि कॉटेज,
रतन कालोनी, जबलपुर (म.प्र.) 482003

Ph. : 0761-4927201, Email : mpphcejabalpur@gmail.com

म.प्र. पुलिस आ.अधो.वि.नि. जबलपुर क्र.-01 के अंतर्गत बाह्य विद्युतीकरण कार्य:- निर्माण कार्य 112 आरक्षक आवास गृह (तृतीय चरण) सिविल लाइन जबलपुर में 2x200 एवं 1x100 KVA/11/0.4 में उच्च दाब एवं निम्न दाब सहित कार्य सम्पन्न करना। हेतु (ऑनलाइन निविदा क्र. 2022_MPPHC_190208) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 25.03.2022 समय 17:00 बजे तक ऑनलाइन खरीदे एवं सबमिट (प्रस्तुत) किये जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal : <https://www.mptenders.gov.in> पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/104001/46761/2022

परियोजना यंत्री

**कोरोना को मारने के तीन हथियार
हाथ धुलायी, मास्क और वैक्सीन का वार।**

स्कूल और कॉलेजों में लगाएं सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग के शिविर

भोपाल, सिकल रोग की स्क्रीनिंग के लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों में सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग शिविर लगाकर जांच करें। जांच के परिणामों में रोग प्रभावित बच्चों के पालकों की जांच भी की जाए। गर्भवती माताओं की जांच कार्य में आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए। इससे कार्य की गति बढ़ेगी और समय की बचत भी होगी। साथ ही उपचार और प्रबंधन कार्य बेहतर होगा। मानवता की सेवा का सौभाग्य ईश्वरीय कृपा से मिलता है। इसे संवेदनशीलता के साथ करने वालों पर ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। ये बातें राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने भोपाल में सिकल सेल एनीमिया रोग के उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए रोडमैप के संबंध में केंद्रीय संयुक्त सचिव जनजाति कार्य डॉ. नवलजीत कपूर और विषय-विशेषज्ञों से आभासी माध्यम से चर्चा करते हुये कहीं।

केंद्रीय संयुक्त सचिव डॉ. नवलजीत कपूर ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया रोग नियंत्रण तात्कालिक प्रयासों में प्री-नेटल टेस्टिंग जरूरी है। दीर्घकालिक प्रयासों में लक्षित आबादी में रोग चिन्हांकन कार्य को प्रभावी बनाने के लिए सिकल सेल एनीमिया रोग के साथ जन्म लेने वाले बच्चों

की निओ-नेटल स्क्रीनिंग कर वैक्सीनेशन, इंफेक्शन और कॉम्प्लिकेशन को रोकने के प्रयासों की कार्य-योजना बनाई गई है। रोग उपचार प्रबंधन के लिए दर्द एवं अन्य जटिलताओं के प्रबंधन और स्थायी उपचार के प्रयास जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के उपयोग, आवश्यक संसाधन, अन्य व्यवस्थाओं की प्रमाणिकता और शोध संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

लक्षित आबादी की स्क्रीनिंग का डाटाबेस बनाने, जन-जागरण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शोध अनुसंधान संबंधी व्यवस्थाओं की रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि जांच कार्य की विभिन्न विधियों प्वाइंट ऑफ केयर टेस्ट, पीओसी रेपिड टेस्ट और पीओसी विथ पोर्टेबल मशीन की उपयोगिता और व्यावहारिकता का परीक्षण कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

गर्भवती माता की पहले त्रैमास में जांच, रोग कैरियर होने पर पति की जांच और दोनों के कैरियर पाए जाने पर सी.वी.एस. सिक्वेसिंग और बच्चे के सिकल सेल रोग पीड़ित होने पर काउंसलिंग की व्यवस्थाओं के साथ लक्षित आबादी के 10 से 25 वर्ष के किशोर और अविवाहित युवाओं की स्क्रीनिंग के कार्य किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश में तेज औद्योगिकीकरण के लिये विकसित हो रहा ईको सिस्टम

इंदौर, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी है कि उत्पाद गुणवत्ता, आज की जरूरत और नई तकनीक अनुरूप तैयार हो। उत्पादों की लागत में कमी पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य शासन तकनीकी और अन्य जरूरी सुविधाएं देने के लिए हमेशा तत्पर है। ये बातें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने इंदौर में फर्नीचर मेन्युफैक्चर्स एवं इंदौर टॉयज मेन्युफैक्चर्स एसोसिएशन द्वारा क्लस्टर विकास, प्रगति एवं प्रयास विषय पर परिचर्चा को संबोधित करते हुये कहीं।

श्री सखलेचा ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये अनुकूल वातावरण है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये

ईको सिस्टम विकसित किया जा रहा है। उन्होंने उद्योगपतियों का आह्वान किया कि वे आगे आकर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करें। राज्य सरकार द्वारा उन्हें हर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जायेंगी। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को ऐसी व्यवस्था दी जा रही है, जिससे कि उन्हें एक ही जगह सभी सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त हों।

सांसद श्री शंकर लालवानी ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा तेजी से औद्योगिक विकास किया जा रहा है। प्रदेश में स्टार्टअप को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप नीति भी तैयार हो गई है। इंदौर को स्टार्टअप की राजधानी बनाने की दिशा में तेजी से प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्लस्टर विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ड्रोन के इस्तेमाल में बनायेंगे मध्यप्रदेश को नम्बर वन - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का किया उद्घाटन



मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुये।

ग्वालियर, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिये सरकार सभी दिशाओं में काम कर रही है। इस दिशा में प्रदेश में ड्रोन तकनीक को भी प्रमुखता से अपनाया गया है। हम मध्यप्रदेश को ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल में नम्बर वन राज्य बनायेंगे। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कही। मुख्यमंत्री ने एमआईटीएस मैदान में रिमोट के जरिए ड्रोन उड़ाकर प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया।

श्री चौहान ने कहा कि खुशी की बात है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर प्रदेश में पांच ड्रोन स्कूल खुलने जा रहे हैं। इनमें से पहले स्कूल का शुभारंभ ग्वालियर में हो गया है। राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप नीति बनाई है, जिसमें युवाओं के नवाचारों को धरातल पर लाने में सरकार भरपूर आर्थिक और तकनीकी मदद मुहैया करायेगी। उन्होंने कहा कि इंदौर के विद्यार्थियों ने नए स्टार्टअप शुरू कर 800 से 1000 करोड़ रुपये तक की कंपनियां विकसित कर ली हैं। सरकार की स्टार्टअप नीति का लाभ उठाकर ग्वालियर के युवा भी नए

नए स्टार्टअप खड़े कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि हमारा संकल्प है कि प्रदेश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनें।

ड्रोन कृषि नीति का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनें युवा

केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में कृषि के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। निकट भविष्य में इस तकनीक के इस्तेमाल से क्रांतिकारी प्रगति सामने आयेगी। उन्होंने कहा भारत सरकार के कृषि विभाग ने ड्रोन नीति जारी कर दी है, जिसमें 12वीं पास बच्चे 4 लाख रुपये तक का अनुदान प्राप्त कर ड्रोन पायलट के रूप में अच्छा रोजगार पा सकते हैं। इसी तरह यदि कृषि स्नातक ड्रोन तकनीक की कोई इकाई स्थापित करना चाहते हैं तो वह 5 लाख रुपये तक का अनुदान पा सकते हैं। इसके अलावा संस्थान भी कृषि ड्रोन नीति में 100 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। श्री तोमर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मकान का मालिकाना हक दिलाने में ड्रोन तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी तरह टिड्डी दल के आक्रमण को असफल करने

में ड्रोन तकनीक क्रांतिकारी साबित हुई है।

ड्रोन स्कूलों के जरिए साल भर में ढाई हजार ड्रोन पायलट होंगे तैयार

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि भारत किसी भी देश का फालोअर नहीं लीडर बने। इसी संकल्पना को साकार करने के लिये ड्रोन को गांव-गांव और घर-घर में पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 11 दिसम्बर 2021 को प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी। खुशी की बात है कि मात्र 90 दिन के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरा करने के बाद ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल शुरू हो गया है। श्री सिंधिया ने बताया कि इस ड्रोन स्कूल में हर माह 40 से 50 बच्चों को ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित किया जायेगा। इस प्रकार साल भर में लगभग 500 युवा ड्रोन पायलट के रूप में तैयार होंगे। ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त युवा हर महीने औसतन 30 हजार रुपये की आय आसानी से अर्जित कर पायेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के पांचों ड्रोन स्कूल शुरू होने पर साल भर में लगभग ढाई हजार ड्रोन पायलट तैयार होंगे।

स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा सभी शासकीय कैंटीन का संचालन



मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में निर्मित 'दीदी कैफे' का शुभारंभ करते हुये।

भोपाल, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश की सभी शासकीय कैंटीन का संचालन स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जायेगा। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रदेश में 127 दीदी कैफे का शुभारंभ किया गया है। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में निर्मित 'दीदी कैफे' का शुभारंभ करते हुये कही। उन्होंने दीदी कैफे का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आनंद और

गौरव का क्षण है कि हमारी बहनें स्वयं आत्मनिर्भर बनने के साथ आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दे रही हैं। स्व-सहायता समूह की बहनों की सफलता में मध्यप्रदेश की भी उन्नति और प्रगति निहित है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, सरकार सदैव हर संभव मदद के लिए तैयार है।

श्री चौहान ने स्व-सहायता समूह की बहनों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि बहनें इतनी आत्मीयता और प्रेम से

चाय और नाश्ता बनाती हैं कि इसका स्वाद स्वमेव ही बढ़ जाता है। इस कैफे के साथ हमारी बहनें भी सफलता के नये शिखर पर पहुंचें, यही कामना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हर स्व-सहायता समूह की बहन की मासिक आमदनी कम से कम 10 हजार रुपये हो। उन्होंने कहा कि आनंद की बात है कि 127 दीदी कैफे खुलने से एक ही दिन में हमारी हजारों बहनें रोजगार से जुड़ गई हैं।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल उन्नयन के साथ खुलेगी स्व-रोज़गार की राह

भोपाल, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल उन्नयन के साथ स्व-रोज़गार की राह प्रशस्त करने में मददगार साबित होगा।

श्रीमती सिंधिया ने कहा कि तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के बजट में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष 1538 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान स्वागत योग्य है। इस वर्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए बजट में 453 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एडीवी परियोजना के लिए 263 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

श्रीमती सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में कई क्षेत्रों और विधाओं में कुशल जन-शक्ति को तैयार करने के उद्देश्य से भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल्स पार्क तैयार किया जा रहा है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में कौशल विकास एवं रोजगार के उद्देश्य से प्रदेश के ऐसे 46 विकासखण्ड जहां वर्तमान में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित नहीं हैं, वहां आईटीआई संस्थाएं चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि

उच्च ग्रेडिंग प्राप्त समस्त शासकीय आईटीआई संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में है।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि बजट में पॉलीटेक्निक संस्थाओं के लिए 226 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता के लिए 122 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए 118 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सिंगरौली जिले में माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ होगा।

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य खेल अकादमी के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। हर वर्ष खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खिलाड़ियों को हरसंभव अत्याधुनिक सुविधा दी जा रही है। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि आगामी वर्ष में खेलों इंडिया यूथ गेम का प्रदेश में आयोजन किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि



मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते हुये।

भोपाल, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का स्वर्णिम काल है। हम प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ परिवार की भावना और टीम भावना से कार्य करते हुए प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। अधिकारी एवं कर्मचारियों के सहयोग से ही स्वास्थ्य और शिक्षा सहित प्रदेश की प्रगति तथा बेहतर के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश कई योजनाओं में देश में प्रथम है। आप सबके सहयोग से हम अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्धियां अर्जित करेंगे। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अधिकारी एवं कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुये कहीं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार व्यक्त करने प्रदेश के विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी संगठनों तथा निगम, मंडल आदि के 57 कर्मचारी संघों के पदाधिकारी मुख्यमंत्री निवास पर एकत्र हुए थे।

किसानों और युवाओं को रोज़गार के नए अवसर प्रदान करेगा बजट

भोपाल, जल-संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार के नए बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। खासकर मध्यवर्ग और छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए उन्हें विशेष लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। यह किसानों और युवाओं को रोज़गार के नए अवसर प्रदान करेगा।

श्री सिलावट ने कहा कि बजट में मछली पालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सिंचाई का लक्ष्य बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश में वर्ष 2003 में लगभग 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। हमारी सरकार द्वारा विगत वर्षों में किये गये प्रयासों से कुल सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। सिंचाई क्षेत्र के लिये वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान 9 हजार 267 करोड़ रुपये का है। कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना लक्षित है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना न केवल

सभी समस्याओं का किया जाएगा समाधान मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी एवं कर्मचारियों की सभी समस्याओं का समाधान व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए संवेदनशीलता, प्रेम भाव तथा वार्तालाप से किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के कठिन समय में वित्तीय चुनौतियां थीं। साथ ही कोरोना संक्रमण के भय के बीच कार्य करना भी एक बड़ी चुनौती थी। स्वास्थ्य सेवाएं हों या कानून-व्यवस्था की स्थिति या फिर गेहूं खरीदी की व्यवस्था, सभी मोर्चे पर अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अपना दायित्व निभाया और पूर्ण समर्पण और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया। कई अधिकारी और कर्मचारियों ने कोरोना से लड़ते-लड़ते अपनी जान तक दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता की ओर से मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। राज्य सरकार द्वारा कोविड योद्धा योजना में ऐसे परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट

के कारण निर्मित राज्य की आर्थिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके जायज अधिकार समय रहते नहीं दे पायी। परिस्थितियां सामान्य होते ही राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। आगामी माहों में उनकी अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सम्पूर्ण दायित्व-बोध से करें। उनकी मानवीय गरिमा और सम्मान राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है।

अध्यक्ष राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग श्री शिव चौबे ने भी संबोधित किया। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री सुधीर नायक ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा एक साथ 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाना अभूतपूर्व है। इससे कर्मचारी जगत में व्याप्त प्रसन्नता के भाव को व्यक्त करने के लिए ही अधिकारी एवं कर्मचारी एकत्र हुए हैं।

बुधनी को छोटे शहरों में देश का पहला वाटर प्लस शहर बनायेंगे

सीहोर, सभी के सहयोग से बुधनी को देश का पहला वाटर प्लस और अद्भुत शहर बनाया जाएगा। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ यहां स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य किये जाएंगे। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले में बुधनी के गौरव दिवस पर 44 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत से बने सीवरेज सिस्टम का लोकार्पण और 59 करोड़ के निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन करते हुये कहीं। मुख्यमंत्री ने नगर भ्रमण कर नागरिकों को गौरव दिवस कार्यक्रम के लिए आमंत्रण भी दिया।

सीहोर जिले के प्रभारी और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, सांसद श्री रमाकांत भार्गव सहित जनप्रतिनिधि तथा नगरवासियों ने गौरव दिवस में शामिल होकर खुले संवाद में बुधनी के विकास की चर्चा की। सभी ने नगर विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का संकल्प भी लिया।

श्री चौहान ने कहा कि इंदौर देश का पहला वाटर प्लस महानगर बन चुका है।

अब हम सबके सहयोग से बुधनी को भी देश के छोटे शहरों की श्रेणी में पहला वाटर प्लस शहर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक माह में सभी घरों के निस्तारी पानी को सीवरेज प्लांट से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि खुले में शौच, सड़क पर कचरा फेंकने और पॉलीथिन के उपयोग आदि को छोड़ने का संकल्प लें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष से बुधनी के गौरव दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। इस वर्ष मई में भी ये कार्यक्रम किये जायेंगे। बुधनी में शिक्षा की उत्कृष्ट व्यवस्था की जाएगी, जिससे कोई भी गरीब प्रतिभाशाली बच्चा उच्च शिक्षा के लिए भटके नहीं। मुख्यमंत्री ने बुधनी में सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं की परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान के साथ आईटीआई में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाकर युवाओं और समूहों को जोड़ा जाएगा। युवाओं को स्व-रोज़गार से जोड़ने के लिये प्रदेश में हर माह रोज़गार दिवस मनाया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के 24 ईको पर्यटन क्षेत्र निजी क्षेत्र को सौंपे जायेंगे

भोपाल, मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा ईको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी इकाइयों और व्यवसायियों को चिन्हांकित कर 24 स्थलों को 10 साल तक के लिए सौंपा जा रहा है।

बोर्ड के सीईओ श्री सत्यानंद ने बताया कि चिन्हांकित ईको पर्यटन स्थलों को निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अवधि 15 मार्च, 2022 तक

बढ़ा दी गई है।

उल्लेखनीय है कि ईको पर्यटन स्थल केरवा (भोपाल) को निविदा की कार्यवाही प्रशासनिक कारण से पिछले माह निरस्त कर दी गई है। शेष 24 ईको पर्यटन स्थल खण्डवा, श्योपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर और सिवनी जिले में स्थापित हैं।

विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट www.mpccotourism.org पर उपलब्ध है।

महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता - मुख्यमंत्री



मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दूरस्थ अंचलों के थानों की ऊर्जा महिला डेस्क के कार्यक्रम को संबोधित करते हुये।

भोपाल, मां-बेटी और बहनों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक अभियान संचालित किए जा रहे हैं। महिला अपराधों के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। बेटियों के साथ अभद्रता करने वालों को सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाने का कानून प्रदेश की विधानसभा ने देश में सबसे पहले बनाया था। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश के दूरस्थ अंचलों के थानों की ऊर्जा महिला डेस्क को 100 दोपहिया वाहन वितरण समारोह को संबोधित करते हुये कहीं। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट उद्यान से ऊर्जा महिला डेस्क की दोपहिया वाहनों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री चौहान ने महिला सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे 'असली हीरो अभियान' से समाज को जोड़ने के लिए सत्य घटनाओं पर आधारित तीन लघु वृत्त चित्र का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा यह फैसला था कि पुलिस फोर्स में 30 प्रतिशत भर्तियां महिलाओं की होंगी। यह गर्व का विषय है कि बेटियां पूरी क्षमता के साथ सुरक्षा के इस दायित्व को पूर्ण गंभीरता और वीरता के साथ निभा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण के सशक्त पक्षधर रहे हैं। उनके द्वारा इस दिशा में अनेकों योजनाएं संचालित की गई हैं।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में महिला थाने स्थापित किए गए हैं। महिला हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। साथ ही ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। थानों में महिलाएं बिना किसी झिझक के एफआईआर लिखवा सकें, इस उद्देश्य से महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। महिला पुलिस कर्मियों द्वारा अपना यह दायित्व निभाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला अपराध

से संबंधित कोई सूचना मिले तो घटना स्थल पर पहुंचने में देरी न हो, इस उद्देश्य से ही ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क को दोपहिया वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है। उनमें से 100 डेस्क को दोपहिया वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना ने कहा कि महिला सुरक्षा मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। श्री चौहान के निर्देशन और मार्गदर्शन में प्रदेश में कई नवाचार हुए हैं, जिनमें प्रत्येक जिले में महिला थाने की स्थापना, 700 थानों में ऊर्जा महिला डेस्क की स्थापना, पुलिस इकाइयों में झूलाघर की स्थापना, 1090 महिला हेल्पलाइन स्थापित करना, गुम नाबालिग बालक-बालिकाओं को खोजने के लिए ऑपरेशन मुस्कान तथा ऑपरेशन हेलिंग हंड आरंभ करना सम्मिलित है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

क्रियान्वयन समय-सीमा में सुनिश्चित हो नर्मदा जल उपयोग की परियोजनाओं का

भोपाल, उद्यानिक एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) और नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने नर्मदा घाटी विकास विभाग की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि नर्मदा जल विकास न्यायाधिकरण द्वारा तय समय-सीमा में दिसम्बर 2024 तक नर्मदा जल उपयोग की सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को

सुनिश्चित करें। श्री कुशवाह ने कहा कि वर्तमान में निर्मित और निर्माणाधीन योजनाएं 15.23 एमएएफ नर्मदा जल के लिये हैं। इनसे लगभग 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। आगामी कार्य-योजना में आवंटित जल के शेष उपयोग की प्राधिकरण की 9 एवं जल संसाधन विभाग की 3 परियोजनाओं के लिये निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।

जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी अर्थव्यवस्था में हो रहा तेजी से सुधार

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कोविड-19 की चुनौतियों को परास्त करते हुए मध्यप्रदेश ने स्थिर भावों पर सकल घरेलू उत्पाद में 2021-22 में 10.12 प्रतिशत की वृद्धि हासिल कर ली है। यह बात विधानसभा में वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 जारी करते हुये कही।

श्री देवड़ा ने कहा कि स्थिर भावों पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में बढ़कर 5 करोड़ 64 लाख 514 करोड़ रुपये हो गया है। इसके 6 करोड़ 21 लाख 653 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर सकल घरेलू उत्पाद 3 करोड़ 15 लाख 562 रुपये था।

किसान हितैषी नीतियों और किसानों को संकट में मदद देने वाली योजनाओं से बढ़ी हुई जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक 37.43 प्रतिशत योगदान है। वर्ष 2021-22 अग्रिम के दौरान वित्त वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में 10.32 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 10.59 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र में 9.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी अनुमानित है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 63 हजार 345 रुपये हो गई है, जो 2020-21 में 58 हजार 334 रुपये थी। इस प्रकार पिछले साल की तुलना में 8.59 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 1 लाख 4 हजार 894 रुपये थी, जो 2021-22 में बढ़कर 1 लाख 24 हजार 685 हो गई है। इस प्रकार 18.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

लोक वित्त में भी निरंतर सुधार हो रहा है। वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्ति 164677 करोड़ 45 लाख रुपये अनुमानित है, जो गत वर्ष से 20.05 प्रतिशत ज्यादा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नया जीवन मिला है। विकास

के प्रमुख क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी, ग्रामीण अधोसंरचना, उद्योग में निरंतर प्रगति हो रही है।

सुनियोजित नीतियों और रणनीतियों से कृषि क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है और निरंतर करता रहेगा। वर्ष 2021-22 के दौरान हर क्षेत्र में 10.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दलहन, तिलहन के क्षेत्रफल एवं और उत्पादन में वृद्धि हुई है। नए 1130 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना को मिलाकर कुल 10 हजार रुपये हर साल प्रत्येक किसान को मिल रहे हैं।

कृषि उपज को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक भंडारण की क्षमता बढ़ाते हुए 203 लाख 39 हजार मीट्रिक टन हो गई है। गेहूं उपार्जन 128 लाख 16 हजार मीट्रिक टन और धान का उपार्जन 45 लाख 86 हजार मीट्रिक टन रहा है।

दुग्ध उत्पादन बढ़कर 17 हजार 999 मीट्रिक टन हो गया है। पंजीकृत दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 10 हजार 205 है। इनमें से 7205 कार्यरत हैं। ये समितियां प्रतिदिन औसतन 5.60 किलोग्राम दूध का संकलन कर रही हैं। कोरोना संक्रमण काल में भी यह सिलसिला जारी रहा।

अधोसंरचना के निर्माण में तेजी आई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। सड़क और सिंचाई क्षेत्र में प्रगति हुई है। वर्ष 2020-21 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में 5178 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ।

विद्युत क्षेत्र में प्रदेश पूरी तरह आत्म-निर्भर हो गया है। कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता 21 हजार 401 मेगावाट है। विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। विद्युत विक्रय में भी 5.37 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। नवकरणीय ऊर्जा बढ़कर 5100 मेगावाट हो गई है। विगत 5 वर्षों में लगभग 10 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है।

मध्यप्रदेश में स्थापित होगा मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष

महिला सशक्तिकरण में मध्यप्रदेश ने रचा नया इतिहास - मुख्यमंत्री



मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान देवास में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेते हुये।

देवास, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने महिला सशक्तिकरण में नया इतिहास रचा है। मध्यप्रदेश में आजीविका मिशन में महिलाओं के स्व-सहायता समूहों ने महिलाओं के सशक्तिकरण में क्रांति की है। महिला स्व-सहायता समूह पोषण आहार निर्माण, गणवेश निर्माण, फ्लाई एश से ईट निर्माण, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी, राशन दुकानों का संचालन आदि अनेक कार्य कर रहे हैं। देवास में पोषण आहार संयंत्र में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा पोषण आहार बनाया जायेगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं सांसद श्री जे.पी. नड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला स्व-सहायता समूहों को पोषण आहार संयंत्र की चावी सौंपी। उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम

से 300 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया। जल जीवन मिशन में कार्य करने के लिये महिलाओं को टूल किट प्रदाय किये गये।

श्री चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिये 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। प्रदेश में महिला वित्त विकास निगम का सुदृढीकरण किया जायेगा, दूसरा- प्रदेश में 100 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष स्थापित होगा, तीसरा-मुख्यमंत्री महिला उद्यम शक्ति योजना प्रारंभ होगी और चौथा-इंदौर एवं भोपाल में महिला उद्यम प्रोत्साहन के लिये इंडस्ट्रियल पार्क बनाये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश में अद्भुत कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री आवास की महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री, उज्ज्वला

कनेक्शन, राशन प्रदाय, आजीविका मिशन आदि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश आगे है। मध्यप्रदेश में पैदा होने से अंतिम सांस लेने तक बहन-बेटियों का पूरा ध्यान सरकार रखती है। प्रदेश में 41 लाख से अधिक लाइली लक्ष्मी हैं, जो पैदा होते ही लखपति हो जाती हैं। बेटियों के कॉलेज में प्रवेश पर उन्हें 25 हजार रुपये तथा प्रतिवर्ष 5 हजार रुपये अध्ययन के लिए दिये जा रहे हैं। साथ ही मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि पाठ्यक्रमों की फीस भी सरकार भरती है।

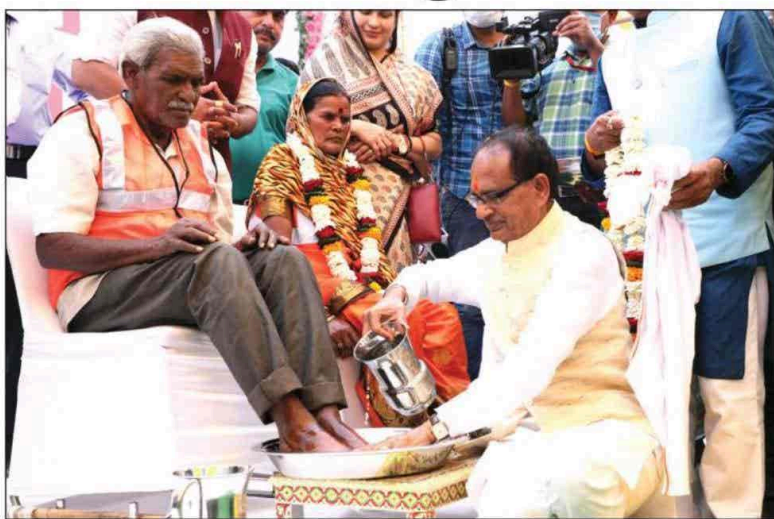
श्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। पहले ठेकेदारों के माध्यम से पोषण आहार बनता था। अब प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूह यह कार्य करेंगे। यह महिला सशक्तिकरण को नई दृष्टि एवं दिशा देगा। महिलाएं यहां प्रतिवर्ष लगभग 800 करोड़ रुपये का कार्य करेंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान इसके लिये बधाई के पात्र हैं।

सफाई मित्रों को मिलेगा 150 रुपये मासिक जोखिम भत्ता - मुख्यमंत्री

भोपाल, शहरों, कस्बों और ग्रामों को स्वच्छ रखने वाले सफाई मित्र मेरे लिए पूजनीय हैं। सफाई मित्रों के पसीना बहाने के फलस्वरूप ही स्वच्छता बनी रहती है। यह सबसे बड़ा काम है। यदि सफाई मित्र यह काम न करें, तो शहर बीमार हो जाएंगे। इनका सेवा भाव प्रशंसनीय है। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मोतीलाल नेहरू विज्ञान महाविद्यालय खेल मैदान में एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने इस अवसर पर सफाई मित्रों को भोजन परोसा, उनका सम्मान किया, सार्वजनिक कार्यक्रम में दो सफाई मित्रों श्री छोटेलाल और श्रीमती निर्मलाबाई के पैर धोकर (पाद प्रक्षालन कर) उनके साथ बैठकर भोजन भी किया।

श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में कचरा मुक्त शहर के लिए स्टार रेटिंग के आधार पर सफाई मित्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए चार पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही सफाई मित्र को प्रतिमाह 150 रुपये का जोखिम भत्ता भी दिया जाएगा। पुरस्कारों के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान होगा। श्री चौहान ने कहा कि सभी सफाई मित्रों का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। आज का कार्यक्रम सिर्फ कर्मकाण्ड नहीं है। सफाई मित्रों ने अपनी मेहनत से प्रदेश के ग्रामों, नगरों और कस्बों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में पूरा सहयोग दिया है। इसलिए आज सफाई मित्रों को सेवा सम्मान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छता के मामले में हम सभी



मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में सफाई मित्रों का सम्मान करते हुये।

के प्रेरक हैं। शहरों के साथ ही सभी स्थानों में स्वच्छता और सुंदरता का महत्व है। वापू ने भी कहा था कि जहां स्वच्छता होती है वहीं भगवान रहते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया है। उनके आह्वान पर देशवासी सार्वजनिक स्वच्छता के महत्व को समझकर अपने आस-पास और अपने ग्राम, नगर को स्वच्छ बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करते हैं। श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे स्वच्छता के मामले में अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई मित्रों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई सहित अन्य कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छता

सर्वेक्षण-2022 में कचरा मुक्त शहर के सफाई मित्रों को स्टार रेटिंग के आधार पर पुरस्कार राशि दी जाएगी। इन पुरस्कारों में एक स्टार प्राप्त करने वाले शहरों के प्रत्येक सफाई मित्र को एक हजार रुपये, तीन स्टार प्राप्त करने वाले शहरों के प्रत्येक सफाई मित्र को तीन हजार, पांच स्टार प्राप्त करने वाले शहरों के प्रत्येक सफाई मित्र को पांच हजार रुपये और सात स्टार प्राप्त करने वाले शहरों के प्रत्येक सफाई मित्र को सात हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सफाई मित्रों के लिए प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपये की राशि जोखिम भत्ते पर व्यय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक सफाई मित्र अपने शहर को 5 स्टार या 7 स्टार दिलवाने का प्रयास करें।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

एजेंसी देना है

मध्यप्रदेश का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला साप्ताहिक समाचार पत्र

रोज़गार और निर्माण

प्रदेश में
**खंडवा, धार, खरगोन,
बुरहानपुर, झाबुआ, बड़वानी
तथा अलीराजपुर जिलों में
एजेंसी नियुक्त करना है।**

संपर्क करें

9425625746, 9424442725

प्रमुख आकर्षण

- कैरियर की खबरें
- सप्ताह की प्रमुख घटनाएं
- सम-सामाजिक विषयों पर विशेषज्ञों की टिप्पणियां
- मध्यप्रदेश सरकार के निर्णयों और योजनाओं की जानकारी
- खेल जगत की उल्लेखनीय खबरें
- विज्ञान की बातें

मध्यप्रदेश माध्यम

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011

फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006

www.mpmadhyam.in

madhyam.rojgar@gmail.com

आज ही खरीदें
प्रमुख बुक-स्टॉलों
पर उपलब्ध



माधवी पुरी बुच

सेबी की नई चेयरपर्सन नियुक्त

माधवी पुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। उन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। जिनका पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। यह पहली बार है जब किसी महिला की नियुक्ति सेबी प्रमुख के पद पर की गई है। वे आईसीआईसीआई सिक्स्योरिटीज में एमडी और सीईओ के पद पर भी रही हैं। 2011 में वे ग्रेटर पेसिफिक कैपिटल एलएलपी में शामिल होने सिंगापुर चली गई थीं।

हरियाणा में

भैंस रेश्मा ने 33.8 लीटर

दूध देकर बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

हरियाणा के कैथल में बूढ़ाखेड़ा गांव के किसान नरेश की मुरा नस्ल की भैंस रेश्मा ने 33.8 लीटर दूध देकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अब वह पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस बन गई है। रेश्मा ने पहली बार जब बच्चे को जन्म दिया तो 19-20 लीटर दूध दिया। दूसरी बार 30 लीटर और तीसरी बार 33.8 लीटर दूध देकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) ने रेश्मा को उन्नत नस्ल का दर्जा दिया है।

अमेरिका

पिच्यसी साल पुरानी टालबोट लेगो

75 करोड़ रुपये में बिकेगी

अमेरिका के फ्लोरिडा में रखी 1937 में निर्मित टालबोट लेगो टी 150-सीएसएस नामक रियर ड्रॉप कूपे कार फ्रेंच डिजाइन और कारीगरी का शानदार नमूना है। इस 85 साल पुरानी कार के फ्लोरिडा के नीलामी घर में 10 लाख डॉलर (75 करोड़ रुपये) में बिकने की संभावना है। इस कार में 4 लीटर का इन लाइन सिक्स इंजन लगा है। जिसकी इंजीनियर डिजाइन वाल्टर बेचिया ने की थी।

धान एक्सप्रेस

ऑस्ट्रेलिया के एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर करती है तय

दुनिया की सबसे शानदार और सबसे लंबी रोमांचक रेल



यात्रा के लिये धान एक्सप्रेस में बुकिंग शुरू हो गई है। यह ट्रेन ऑस्ट्रेलिया के एक छोर से दूसरे छोर तक 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करती है। इस दौरान यात्रियों को शानदार नजारों के अलावा लज्जती लुत्फ भी मिलता है। 40 डिब्बों वाली इस एक्सप्रेस का नाम धान इसके पुराने नाम अफगान एक्सप्रेस का संक्षिप्त रूप है। इसका एडिलेड से डार्विन तक गोल्ड सर्विस किराया लगभग 5 लाख रुपये प्रति दिन है।

लॉरी मॉर्गन

सबसे बड़ा झंडा

फहराकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

वेल्स के एक टेलीविजन चैनल की होस्ट लॉरी मॉर्गन ने हिरवान में जिप वर्ल्ड टॉवर पर जिप वायर की सवारी करके अपने राष्ट्र वेल्स का विशाल झंडा फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस झंडे का आकार 1,091.46 वर्ग फीट था। सेंट डेविड्स डे के मौके पर चैनल की ओर से इस रिकॉर्ड प्रयास का आयोजन किया गया था। सेंट डेविड वेल्स के संरक्षक संत माने जाते हैं। लॉरी ने 10 सेकंड तक झंडे को फहराये रखा था।

वैन शहर

माइनस तापमान में इंजीनियर ने तकनीकी खराबी को किया दूर

तुर्की के जीवा जिले के बर्फ की वादियों से घिरे वैन शहर में 210 फीट ऊंचे विंड एनर्जी (पवन ऊर्जा) प्लांट के एक टर्बाइन में आई खराबी को दूर करने के लिये माइनस 6 डिग्री में इंजीनियर गये। इस तापमान और बेहद कठिन मौसम में टर्बाइन तक इंजीनियर को हेलीकॉप्टर के नीचे एक बास्केट में बैठकर पहुंचाया गया। अगर टर्बाइन की बजाय तारों में खराबी आ जाये तो हेलीकॉप्टर की बास्केट में बैठकर हवा में ही लाइन ठीक की जाती है।

केटनजी ब्राउन

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज नियुक्त

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में केटनजी ब्राउन को जज नियुक्त किया है। ब्राउन यह पद पाने वाली अमेरिका की पहली अश्वेत महिला हैं। बाइडेन ने उनके नाम पर मुहर रियायत होने वाले जज स्टीफन ब्रेयर की सलाह पर लगाई है। ज्ञात रहे कि केटनजी ब्राउन बहुत समय पहले जस्टिस ब्रेयर के पास क्लर्क थीं। अब वे उनकी ही जगह पर नियुक्त हुई हैं।

कैलाश कुमार

पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त

पाकिस्तान में पहली बार किसी हिंदू को लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेजर कैलाश कुमार इस पद पर नियुक्त किये गये हैं। वह सिंध प्रांत के थार जिले के रहने वाले हैं, वे मेडिकल कोर में हैं। उनकी रैंक मेजर से अपग्रेड की गई है।

अनास्तासिया लेना

पूर्व मिस ग्रैंड यूक्रेन सेना में शामिल

पूर्व मिस ग्रैंड यूक्रेन अनास्तासिया लेना रूस के खिलाफ अपने देश की ओर से यूक्रेनी सेना में शामिल हो गई हैं। लेना ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है, जो हमले की नीयत से यूक्रेन की सीमा पार करेगा, मार दिया जावेगा। उन्होंने अपने देश की महिलाओं को भी सेना में शामिल होकर देश को बचाने का आह्वान किया है।

जुनैद कमाल अहमद

MIGA के उपाध्यक्ष नियुक्त

विश्व बैंक के भारत प्रमुख जुनैद कमाल अहमद को संस्था का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अहमद उपाध्यक्ष (ऑपरेशंस) के तौर पर बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) का नेतृत्व करेंगे। वह दूसरे बांग्लादेशी नागरिक हैं,

जिन्हें विश्व बैंक के इतिहास में इतने बड़े पद पर नियुक्त किया गया है।

सर्गेई स्ताखोव्सकी

टेनिस स्टार यूक्रेनी सेना में शामिल

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद टेनिस खिलाड़ी सर्गेई स्ताखोव्सकी आर्मी रिजर्व में शामिल हो गये हैं। 36 वर्षीय टेनिस स्टार 2013 में विंबलडन में रोजर फेडरर को हरा चुके हैं। सर्गेई ने अपने साथ मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर ऑलेक्जेंडर जिनचेंको को भी सेना में शामिल करवाया है।

फेलिसिटी एस

हजारों लज्जरी कारों

के साथ समुद्र में डूबा जहाज

हजारों लज्जरी कारों और अन्य वाहन लेकर जर्मनी से अमेरिका जा रहा मालवाहक जहाज मध्य अटलांटिक महासागर में डूब गया। पनामा के फेलिसिटी एस नाम के इस जहाज में 16 फरवरी को आग लग गई थी, तभी से यह लगातार जल रहा था। आग के कारण इंजन बंद हो गया था। इसके 22 सदस्यों को रेस्क्यू कर लिया गया था। 650 फीट लंबा यह जहाज 4 हजार कारों को ले जाने में सक्षम था। इस हादसे से करीब 3332 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, इस जहाज में 2200 टन ईंधन था।

अमेरिका में

दुनिया के सबसे पतले स्काईस्क्रैपर से गिर रहीं बर्फ की सिल्लियां

अमेरिका की वेस्ट 57 स्ट्रीट की स्टेनवे टॉवर नामक इमारत आजकल सुर्खियों में है। मैनहट्टन के मिडटाउन इलाके में बनी यह इमारत दुनिया की सबसे पतली स्काईस्क्रैपर कही जाती है। मूल रूप से 1925 में स्टेनवे हॉल के रूप में डिजाइन की गई इस इमारत का रिसिडेंसियल टॉवर 2021 में लगभग 15 हजार करोड़ रुपये में तैयार हुआ था। 1427 फीट ऊंची इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर सर्द मौसम में बर्फ जम जाती है और यही बर्फ सिल्लियों के रूप में सड़क पर गिरकर लोगों को घायल कर रही है। इस कारण ट्रैफिक बाधित हो रहा है।

संजीव कपूर

जेट एयरवेज के नये सीईओ नियुक्त

संजीव कपूर को जेट एयरवेज का सीईओ नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 4 अप्रैल से प्रभावी होगी। 1997 में अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस से एयरलाइन कैरियर शुरू करने वाले कपूर फिलहाल ओवेरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के प्रेसिडेंट हैं। वह नवंबर 13 से अक्टूबर 15 तक स्पाइसजेट के सीईओ रहे थे।

अमन लेखी

एसएसजी पद से इस्तीफा दिया

सीनियर एडवोकेट अमन लेखी ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें 5 मार्च 2018 में एसएसजी नियुक्त किया गया था। केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को उन्हें तीन साल के दूसरे कार्यकाल के लिये नियुक्त किया था, जो 30 जून, 2023 तक था, लेकिन उन्होंने पहले ही अपने पद से त्याग पत्र दे दिया।

भारत में

सफल रहा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का परीक्षण

भारत में पहली बार 'क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम ने उत्तरप्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100



किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच क्वांटम की (कुंजी) डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इस बारे में जानकारी दी है। यह तकनीकी सफलता वाणिज्यिक ग्रेड पर हासिल की गई जो ऑप्टिकल फाइबर क्षेत्र में पहले से ही उपलब्ध है। इस सफलता से देश ने बूटस्ट्रैनिंग के लिए सुरक्षित कुंजी हस्तांतरण की स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन किया। यह भी बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान मापदण्डों को मापा गया और रिपोर्ट किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के भीतर 10 किलोहर्ट्ज तक की प्रमुख दरों पर दोहराया पाया गया। यह तकनीक सुरक्षा एजेंसियों को स्वदेशी प्रौद्योगिकी के बलबूते एक उपयुक्त क्वांटम संचार नेटवर्क की योजना बनाने में सक्षम बनाएगी।

शंघाई टॉवर के रेस्तरां को

सबसे ऊंचा होने का खिताब मिला

दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग के रेस्तरां को सबसे ऊंचा होने का खिताब मिला है। चीन के शंघाई टॉवर की 120वीं मंजिल पर हेवनली जिन रेस्तरां बनाया गया है। जमीन से इसकी ऊंचाई 1825 फीट है। इसे किसी बिल्डिंग में सर्वाधिक ऊंचाई पर बने रेस्तरां के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स में जगह दी गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड दुबई के बुर्ज खलीफा में बने एटमॉस्फियर रेस्तरां के नाम था। एटमॉस्फियर रेस्तरां 1448 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।

बाइक-बोट

सड़क और पानी में चलेगी

सड़क और पानी में चलने वाली बाइक-बोट जेड-ट्रिटॉन में दो इलेक्ट्रिक मोटर हैं, जो लिथियम-आयन बैटरी से चलती हैं। बैटरी चार्ज करने के लिए सोलर पैनल लगे हैं। इसे लाताविया के एगर्स लाउजिस ने डिजाइन किया है। यह इसी साल से 12 लाख रुपये में बाजार में मिलने लगेगी।



स्मृति शोष

फिल्म समीक्षक और लेखक जयप्रकाश चौकसे का निधन

फिल्म समीक्षक और लेखक जयप्रकाश चौकसे का इंदौर में दिल का दौरा पड़ने से 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फिल्मी लेखन के चिंतक जानकार चौकसे ने 1979 में फिल्म 'शायद', 1986 में 'कत्ला', 2011 में 'बांड़ीगाई' सरीखी हिन्दी फिल्मों की पटकथा तथा संवाद लिखे थे। उन्होंने महाभारत पर आधारित एक टेलीविजन धारावाहिक के लेखन विभाग के प्रमुख का जिम्मा भी संभाला था।

पूर्व सेना प्रमुख जनरल रोड्रिग्स का निधन

पूर्व सेना प्रमुख जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1990 से 1993 तक भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। उन्हें 2004 से 2010 तक पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया था। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद से सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों में अपना अमूल्य योगदान दिया। वे दो बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में भी शामिल रहे थे।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

आप प्यार करते हो परिवार से, कोरोना डरता वैक्सीन की मार से।



M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
(Formerly M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (I) Ltd.)
REGIONAL OFFICE, 101, First Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road, Indore – 452001 (M.P.), Phone : (O) 0731-2970611, 2974363, 2971311, Fax No. : 0731-2972629
Website : invest.mp.gov.in, E-mail : ed.roind@mpidc.co.in, CIN : U51102MP1977SGC001392
No. MPIDC/ROIND/TECH/22/18620
Date : 11.03.2022

NOTICE INVITING TENDER (II-Call)
Online tenders are invited on behalf of the Executive Director, MPIDC RO Indore, from registered contractors in any State/Central Government/any Government undertaking or reputed firms for the following work. The Tenders would be made available on the e-portal <https://www.mptenders.gov.in>.

Name of Work	Probable Amount of Contract (in Lakh)	EMD (in Rs.)	Cost of Tender Form (in Rs.)	Last Date of Submission of Tender
Shifting of 33KV/11KV electric Line at I/A Pithampur II	09.82	19640/-	2360/-	28.03.2022
Supply of Bleaching Powder, Ferric alum & Poly aluminium chloride solution at I/A Meghnagar	29.12	29125/-	5900/-	28.03.2022

Detailed NIT along with other details can be viewed on above mentioned portal.
M.P. Madhyam/103992/2022
EXECUTIVE ENGINEER
R-46760/2022

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई
तहसील कैम्पस सागर म.प्र.

एनआईटी नं. – 07/2022/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण/सा/एपीडी/..... सागर, दिनांक : 04.03.2021
निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-
कार्य का नाम :- केन्द्रीय जेल सागर में 4 (2 डबल स्टोरी) बैरक निर्माण कार्य। (प्रथम आमंत्रण)

सं. क्र.	पोर्टल टेंडर क्रमांक	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	कार्यालय का नाम जहां तकनीकी बिड भौतिक रूप से सत्यापित की जावेगी
1.	2022_PWPIU_188744_1	सागर	164.98	164979	12500/-	12 माह	अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. जबलपुर

कार्य का नाम :-	फर्नीचर कार्य देवरी जिला सागर में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)
1.	2022_PWPIU_188745_1

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर विना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 07.03.2022 समय 10:30 से दिनांक 21.03.2022 समय 17:30 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

संभागीय परियोजना यंत्री
जी-23719/46753/2022
लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू., सागर

कौशल विकास, सीमेन्स इंडिया और जीआईजेड
इंडिया के मध्य हुआ त्रिपक्षीय एम.ओ.यू.

भोपाल, औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण योजना (स्ट्राइव) में इन्डो-जर्मन इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम (IGNITE) के लिए मध्यप्रदेश कौशल विकास, सीमेन्स इंडिया एवं जीआईजेड इंडिया के मध्य त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. संपादित किया गया। संचालक कौशल विकास श्री जितेन्द्र सिंह राजे, सीमेन्स इंडिया के श्री धर्मवीर सिंह एवं जीआईजेड इंडिया की श्रीमती उषा गणेश ने एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये।
संचालक श्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि इन्डो-जर्मन इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य जर्मन डूअल व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण मॉडल के आधार पर भारत में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण के लिए रूपरेखा की स्थिति निर्मित करना है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश के चार इंडस्ट्री क्लस्टर एवं संबंधित 34 शासकीय आईटीआई को आईजीएनआईटीई प्रोग्राम के लिए चयन किया गया है। इसमें ग्वालियर-शिवपुरी इंडस्ट्री क्लस्टर में 7 शासकीय आईटीआई जबलपुर-कटनी 9, सागर-दमोह 9 तथा रीवा-सतना इंडस्ट्री क्लस्टर में 9 शासकीय आईटीआई का चयन किया गया है।

सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान, जिलों में भेजे गये 10 मल्टी मीडिया वाहन
भोपाल, सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान में मल्टीमीडिया वाहन से प्रचार-प्रसार किया जाएगा। अभियान में 10 जिले में मल्टी मीडिया वाहन भेजे गए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने वाहनों को हरी झंडी दिखा कर जिलों के लिए रवाना किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकाकरण के लिए बच्चों के अभिभावकों और गर्भवती माताओं के लिए मल्टी मीडिया वाहन और वाहन के साथ रहने वाले दल की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यूनिसेफ द्वारा उपलब्ध कराये गए मल्टी मीडिया वाहन दृश्य, श्रव्य मीडिया उपकरणों से सुसज्जित हैं। उन्होंने कहा कि अपेक्षाकृत कम टीकाकरण वाले प्रदेश के 10 जिले ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, मुरैना, दतिया, छिंदवाड़ा, दमोह, सिवनी और मण्डला में इंद्रधनुष अभियान संचालित किया जायेगा। अभियान 7 मार्च, 4 अप्रैल और 7 मई को होगा।

बच्चों ने सिद्ध कर दिया, कोशिश करो तो
कोई भी काम असंभव नहीं - मुख्यमंत्री

भोपाल, एसओएस बालग्राम निकेतन के बच्चों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोशिश करो तो दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। यहां के सभी बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों में अद्भुत प्रतिभा है, वे बड़े-बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्म दिवस पर एसओएस बालग्राम निकेतन के बच्चों से भेंट के दौरान कहीं। उन्होंने बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग और अन्य कलाकृतियों की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने बच्चों से चर्चा के दौरान उनके प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तब मजदूरों के हित में कुछ करने का विचार आया। लोगों के लिए मेहनत करने और उनके हित में काम करने के लिए जुटे रहे। उन्होंने कहा कि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। आप भी खूब मेहनत करो तो सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करने एवं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
बच्चों ने किए मुख्यमंत्री से सवाल
छात्रा गीता पाराशर ने पूछा आप अपना बर्थ-डे कैसे मनाते हैं। उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने आज सुबह पौधा लगाया। साथ ही प्रतिदिन पौधे लगाने का प्रण भी लिया है। उन्होंने बच्चों से कहा कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, बल्कि पेड़ लगाना चाहिए। यह हमें ऑक्सीजन देते हैं। पशु-पक्षी और जीव-जंतुओं को भी पेड़ कुछ न कुछ देते हैं।
छात्र युवराज ने पूछा कि मामा जी आपकी रुचि कौन-कौन से खेलों में रही है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने गांव में खेले गए खेलों के बारे में बताते हुए कहा कि कबड्डी, गिल्ली-डंडा, लुका-छिपी का खेल खेला करते थे। वॉलीबाल, क्रिकेट भी खेला है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत जरूरी है। उन्होंने बच्चों को समय पर उठने और सोने की सीख दी।
कु. नंदनी ने पूछा आपके आदर्श कौन हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि स्वामीजी के शब्द मुझे हमेशा उत्साह से भरते हैं। मुख्यमंत्री ने बच्चों को स्वामी विवेकानन्द की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करें और कभी अपने आपको अकेला नहीं समझें।
मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाया। श्री चौहान को बच्चों ने स्वयं निर्मित पेंटिंग, फोटो और अन्य वस्तुएं भेंट कीं।

मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण का
कार्य निरंतर जारी रहेगा - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्मार्ट उद्यान में स्वयंसेवी संस्था नारी शक्ति की सदस्यों, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला सुरक्षा श्रीमती प्रज्ञा रिचा श्रीवास्तव तथा महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ पौध-रोपण किया।
महिला सशक्तिकरण के बिना समाज सबल नहीं बन सकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना महिला सशक्तिकरण के कोई राष्ट्र या समाज सबल नहीं बन सकता है। भारत में अत्यंत प्राचीन काल से ही मां, बहन और बेटी का स्थान सबसे ऊपर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास के मकान महिलाओं के नाम, निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, निःशुल्क राशन, हर घर में शौचालय तथा बेटियों की पढ़ाई के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है। इन योजनाओं से महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित हुई है।
श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, बेटियों को पढ़ाई के लिए निःशुल्क साइकिल एवं पाठ्यपुस्तकों का वितरण, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कई अभियान संचालित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मध्यप्रदेश पहला राज्य था, जिसने राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बहनों को चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। परिणामस्वरूप महिलाएं चुनकर आईं और उन्होंने स्थानीय निकायों में सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। महिला जनप्रतिनिधियों ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षकों की भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। राज्य सरकार के क्रांतिकारी फैसले से पुलिस फोर्स में 30 प्रतिशत भर्ती महिलाओं की होगी। यह प्रसन्नता का विषय है कि आज मेरी सुरक्षा का दायित्व बेटियां ही संभाल रही हैं। बेटियां कानून व्यवस्था को ठीक करने में पूरी क्षमता के साथ जुटी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सामान्य शासकीय भर्तियों में भी 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने महिला स्व-सहायता समूह को सशक्त बनाने का फैसला किया है। आजीविका मिशन से 40 लाख बहनें स्व-सहायता समूहों से जुड़कर अलग-अलग व्यापार और विभिन्न कार्य कर रही हैं। संपत्तियों की खरीद में महिला के नाम संपत्ति होने की स्थिति में स्टॉप शुल्क पर 1 प्रतिशत छूट का विशेष प्रावधान है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

उन्होंने कहा कि कृषि अधोसंरचना निधि से सहकारी क्षेत्र में संस्थाओं का उन्नयन करने तथा कृषि अधोसंरचना निर्माण के लिए कार्ययोजना तैयार की गयी है। इस कार्ययोजना अंतर्गत पैक्स तथा मार्केटिंग सहकारी समितियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। हमारी सरकार नये क्षेत्रों में जैसे जैविक कृषि, उद्यानिकी, पर्यटन, ऊर्जा इत्यादि में सहकारी आंदोलन का विस्तार कर रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों से उनकी उपज का समर्थन मूल्य पर उपार्जन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा वादा रहा है कि हम किसानों की फसल की पूरी खरीदी करेंगे, जो हमने निभाया है। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद विगत दो वर्षों में हमने बम्पर खरीदी की है। खरीदी में उपार्जन संस्थाओं को हानि होती है। जिसकी भरपाई कर उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करना आवश्यक है। अतः वर्ष 2021-22 में मार्कफेड तथा नागरिक आपूर्ति निगत की अंशपूजी में राज्य शासन ने लगभग एक हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति के लिये रुपये 3 हजार करोड़ उपलब्ध कराये गये हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में भी हानि की प्रतिपूर्ति के लिये 1 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री पशुपालन विकास

योजना होगी शुरू

श्री देवड़ा ने कहा कि पशुपालन क्षेत्र में विशेषकर दूध के उत्पादन में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कुल दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश अब देश में तृतीय स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक हो गई है। दुग्ध उत्पादों से आम जनता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, साथ ही रोजगार के नये अवसर निर्मित होंगे। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है। योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध जलक्षेत्र का लगभग 99 प्रतिशत जलक्षेत्र मछली पालन से आच्छादित करते हुए मछली उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किए गये हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के क्रियान्वयन में हमारे प्रदेश ने उत्कृष्ट कार्य किया है।

श्री देवड़ा ने कहा कि मत्स्यपालन में रोजगार की अपार संभावनाओं के दोहन के लिए मुख्यमंत्री मत्स्यपालन विकास योजना प्रारंभ की जायेगी। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का विजन विल्कुल स्पष्ट है - प्रदेश के हर नागरिक को उनकी क्षमताओं के अनुरूप अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए सहज, सुलभ अवसर उपलब्ध कराना। रोजगार एवं स्व-रोजगार उपलब्ध कराना आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप का प्रमुख स्तंभ है। रोजगार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासकीय संस्थाओं में पदपूर्ति की जा रही है। जनजातीय विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में वित्तीय वर्ष 2021-22 में एक हजार 11 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं 3 हजार 126 माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं। प्राथमिक शिक्षक के 11 हजार 556 पदों की पूर्ति के लिए पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए भी कार्यवाही प्रचलित है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के 3 हजार 677 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के 8 हजार 318 पदों पर नियुक्तियों की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 13 हजार शिक्षकों की नियुक्तियों की कार्यवाही की जाना लक्षित है। इसके अतिरिक्त गृह विभाग के अंतर्गत 6 हजार आरक्षकों की भती की कार्यवाही प्रचलित है। अन्य शासकीय विभागों में भी रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक

निवेश की अपार संभावनायें हैं। हमारी सरकार का निरन्तर प्रयास है कि ऐसे निवेश से प्रदेश में रोजगार के नये अवसर सृजित हों तथा प्रदेश का संतुलित आर्थिक विकास हो। हमारी सरकार उद्योग स्थापित करने के लिये रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करा रही है एवं प्रक्रियाओं को सहज किया गया है। 30 दिवस में अपना उद्योग प्रारंभ करने की सुविधा प्रदान करने एवं इस सुविधा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम की परिधि में लाए जाने के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

युवाओं के रोजगार के लिये कई

योजनाएं संचालित

श्री देवड़ा ने कहा कि रोजगार के अवसर में वृद्धि के लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना आदि के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का महाअभियान हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये आर्थिक सहायता की नवीन योजनाएं प्रस्तावित हैं।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के लिये योजनाओं को वृहद् स्वरूप में क्रियान्वित करने हेतु एक हजार 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से लगभग 141 प्रतिशत अधिक है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जहां एक ओर औद्योगिक निवेश को आकर्षित कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कई विधाओं में कुशल जनशक्ति को तैयार करने की कार्यवाही कर रही है। इस दिशा में हमारी सरकार भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क तैयार कर रही है, तथा संभाग स्तर पर 10 मॉडल आई.टी.आई. को सुदृढ़ कर रही है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण के उद्देश्य से हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश के ऐसे 46 विकासखण्ड जहां वर्तमान में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित नहीं हैं, वहां ऐसी संस्थायें चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जायें।

सिंगरौली में माइनिंग विधा का इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत इस वर्ष 26 करोड़ 64 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। मनरेगा से प्रति परिवार औसत रोजगार लगभग 55 दिवस रहा है। मनरेगा का बजट अनुमान वर्ष 2021-22 की तुलना में लगभग 75 प्रतिशत बढ़ाकर 3 हजार 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

श्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन में खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। खनिजों के संरक्षण, अन्वेषण एवं दोहन हेतु आवश्यक संस्थागत व्यवस्थायें बनाई गई हैं। इसी का परिणाम है कि रोजगार के नये अवसरों के सृजन के साथ-साथ राजस्व वृद्धि में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न शहरों से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, जम्मू तथा हैदराबाद मार्गों पर हवाई सेवायें संचालित हो रही हैं। अन्य स्थानों को भी वायु सेवा से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट की दर को अधिकतम 25 प्रतिशत के स्तर से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया है, जिससे वायु सेवा के विस्तार में मदद मिलेगी। प्रदेश के इंदौर विमानतल को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इंदौर विमानतल से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा भी चालू है।

श्री देवड़ा ने कहा कि जनजाति वर्ग को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है इसके लिए जनजातीय

वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जायेगा। इस बजट में एक नई योजना - अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिये रोजगारमूलक आर्थिक सहायता के लिये 60 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को दिये जाने वाले लाभोश की राशि 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की जाये। हमारी सरकार ने पेसा अधिनियम के अनुरूप वनों का पारंपरिक प्रबंधन ग्राम सभा को सौंपने का निर्णय लिया है। वन समितियों को काष्ठ से होने वाली आय का 20 प्रतिशत उपलब्ध कराये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में 15 जनजाति कन्या महाविद्यालयीन छात्रावासों को नवीन भवनों में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 6 विशिष्ट क्रीड़ा परिसर संचालित किये जाने का भी लक्ष्य है।

वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम हमारी सरकार की प्राथमिकता हैं। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जायेगा। इस बजट में एक नई योजना - अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिये रोजगारमूलक आर्थिक सहायता के लिये 40 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति कल्याण के लिये विभिन्न विभागों की योजनाओं में वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 17 हजार 980 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिये 19 हजार 20 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिये रोजगार के नये अवसर सृजित करने की दिशा में अग्रसर हैं। इस हेतु पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जायेगा। इस बजट में एक नई योजना - पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिये रोजगारमूलक आर्थिक सहायता के लिये 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

संबल योजना बृहद स्वरूप

में होगी क्रियान्वित

वित्त मंत्री ने कहा कि संगठित एवं अंसंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा आवश्यक पहल की गई है। श्रम कानूनों में श्रमिक हितैषी प्रावधान किये गए हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत अब तक 3 लाख 29 हजार से अधिक हितग्राहियों को 2 हजार 742 करोड़ रुपये से अधिक के लाभ दिये गये हैं। अब योजना को और वृहद स्वरूप देते हुये क्रियान्वित किया जायेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा और सभी के पास अपना पक्का मकान होगा। इस संकल्प की सिद्धि के लिये हमारी सरकार दिन-रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 23 लाख 50 हजार से भी अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर मध्यप्रदेश, देश में अग्रणी है। प्रदेश के ऐसे गरीब, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता तो रखते थे किन्तु किसी कारण से उनके नाम पात्रता सूची में नहीं जुड़ पाये, ऐसे लगभग 31 लाख हितग्राहियों को अगले 3 साल में आवास प्लस सूची अनुसार योजना का लाभ दिलाया जायेगा।

श्री देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि हर शहर में मूलभूत सेवायें जैसे, घर-घर तक पीने का पानी, सीवेज की व्यवस्था, विजली, अच्छी सड़कें तथा स्वच्छ वातावरण हो। साथ ही रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। सरकार द्वारा किये जा रहे निरंतर प्रयासों से प्रदेश के शहरी स्वच्छता परिदृश्य में आमूल-चूल बदलाव आया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हमारे प्रदेश को देश में तीसरा स्थान तथा इंदौर शहर को लगातार पांचवीं बार देश के स्वच्छतम शहर का पुरस्कार तथा 5 स्टार रेटिंग के साथ देश के पहले वाटरप्लस शहर होने का समान भी प्राप्त हुआ है।

इसके अतिरिक्त 9 शहरों को 3 स्टार, 17 शहरों को 1 स्टार प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता योजना, मुद्रा योजना आदि अनेक योजनायें संचालित की जा रही हैं। स्थानीय प्रतिभाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर देने के लिये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तथा उज्जैन में स्टार्ट-अप इंक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के भीतर स्थित ग्रामों को एक समयबद्ध रूप से ग्रामीणों की सहमति से अन्यत्र विस्थापित किया जाता है। इस हेतु विस्थापन पैकेज की राशि को हमारी सरकार द्वारा प्रति परिवार रुपये 10 लाख से बढ़ाकर रुपये 15 लाख किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में बिगड़े वनों के सुधार के लिए सरकार सतत् प्रयत्नशील है। हमारी सरकार ने वर्षा ऋतु 2021 में 24 हजार 792 हेक्टेयर बिगड़े वनक्षेत्रों में वृक्षारोपण किया है, जिसे डेढ़ गुणा बढ़ाकर वर्षा ऋतु 2022 में 37 हजार 783 हेक्टेयर वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे वनों की बेहतरी के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के और अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

स्कूल शिक्षा के लिये बजट में

1157 करोड़ रुपये का प्रावधान

वित्त मंत्री ने कहा कि सी.एम. राज्ज योजना के तहत प्रथम चरण में 360 स्कूल प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है। इन विद्यालयों की लागत 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक होना अनुमानित हैं। इन विद्यालयों में सभी मूलभूत सुविधायें, पर्याप्त शैक्षणिक अमला, खेल-कूद तथा ललित कलाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा विद्यार्थियों को विद्यालय तक आने-जाने के लिये परिवहन सुविधा आदि उपलब्ध कराई जायेंगी। इस बजट में एक हजार 157 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

श्री देवड़ा ने कहा कि सरकार शैक्षणिक संस्थाओं के उन्नयन तथा उनमें गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। वर्तमान में 104 शासकीय महाविद्यालय एवं 30 निजी महाविद्यालय नैक द्वारा प्रत्यापित हैं। सत्र 2021-22 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के किये गये नैक मूल्यांकन में शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन को A+ ग्रेड प्राप्त हुआ। उच्च शिक्षा का प्रदेश में विस्तार करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश की निजी विश्वविद्यालयों की संख्या अब 40 हो गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संस्थाओं में निरंतर वृद्धि कर उपयुक्त स्वास्थ्य सेवायें प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। यह प्रयास है कि मूलभूत अधोसंरचना के दीर्घकालीन कार्य किये जायें, जिनका लंबे समय तक प्रदेश को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में 10 जिला चिकित्सालय, 33 सिविल अस्पताल, 55 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 119 उप स्वास्थ्य केन्द्र, कुल 417 स्वास्थ्य संस्थायें स्वीकृति की गई हैं। वर्ष 2021-22 में 3 हजार 800 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण तथा 150 जीर्ण-शीर्ण उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 तक 10 हजार उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 1 हजार 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध 2 हजार 3 एम.बी.बी.एस. सीट को बढ़ाकर 3 हजार 250, एम.एस.सी. नर्सिंग में 50 सीट बढ़ाकर 320 तथा बी.एस.सी नर्सिंग में 390 सीट बढ़ाकर 810 की जायेंगी।

श्री देवड़ा ने कहा कि समाज और सरकार के साझा प्रयासों से बेटियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन आया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना बेटियों के लिये वरदान साबित हुई है। मुझे सदन को यह बताते हुए गर्व और खुशी है

कि आज प्रदेश में हमारी 41 लाख से भी अधिक लाड़ली लक्ष्मियां हैं। NHFS-5 सर्वे के अनुसार मध्यप्रदेश में जन्म के समय प्रति हजार बेटों पर बेटियों की संख्या बढ़कर 956 हो गई है। बेटियों के सपने साकार करने के लिये तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल और सुरक्षित बनाने के लिये राज्य सरकार लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार कर लाड़लियों को उच्च शिक्षा के लिये भी सहायता देगी। केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 42 जिलों में ‘बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ योजना’ संचालित है। ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ के क्रियान्वयन में हमारा प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की गई थी जो काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई। इस योजना की अन्य प्रदेशों में एवं राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। हमने निर्णय लिया है कि इस योजना को आगामी वित्तीय वर्ष में पुनः क्रियान्वित किया जायेगा।

श्री देवड़ा ने कहा कि ‘सुशासन’ रीढ़ हैं, शासकीय कार्यालय व शासकीय सेवक। हमारी सरकार ने इस आवश्यकता को पूरी शिद्धत से समझा है। शासकीय कार्यालयों में उपयुक्त सुविधायें उपलब्ध होना आवश्यक है। अतः वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्तावों में सभी शासकीय भवनों के संधारण तथा रख-रखाव के लिए पृथक से प्रावधान प्रस्तावित किए हैं।

उन्होंने कहा कि कोविड काल की कठिन आर्थिक स्थितियों में भी हमारी सरकार ने शासकीय सेवकों व उनके परिवार के हितों को सुरक्षित करने के लिए कोविड योद्धा अनुग्रह राशि योजना, अनुकम्पा नियुक्ति की विशेष योजना, जैसी योजनाओं को लागू किया। कोविड विशेष अनुग्रह योजना के अंतर्गत अब तक 694 प्रकरण स्वीकृत कर रुपये 22 करोड़ 35 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड की परिस्थितियों में वार्षिक वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ते की वृद्धि प्रदान करने में कठिनाई थी। परिस्थितियां अब धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं। अतः विगत वर्ष की स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत की गई है तथा संबंधित एरियर्स के भुगतान के लिये आदेश भी जारी किए गए हैं। महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 20 प्रतिशत को बढ़ाकर 31 प्रतिशत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सेवकों को वर्तमान में प्राप्त चिकित्सा सुविधा को और अधिक सरल सुविधाजनक बनाने के लिये सुसंगत नियमों के पुनरीक्षण पर विचार किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान 1 लाख 95 हजार 180 करोड़ रुपये हैं। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर एवं गैर कर संसाधनों से 86 हजार 478 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां 64 हजार 107 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां 44 हजार 595 करोड़ रुपये अनुमानित है।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न प्रतिकूल आर्थिक वातावरण में भी हमारी सरकार के प्रयासों से वर्ष 2021-22 के राज्य के स्वयं के कर एवं कर भिन्न राजस्व के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार लगभग बजट अनुमान ही प्राप्त होना संभावित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व में वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक अनुमान है।

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिये कुल विनियोग की राशि 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपये व्यय अंतर्गत 1 लाख 98 हजार 916 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय अंतर्गत 48 हजार 800 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिये वर्ष 2022-23 के लिये समग्र रूप से बजट अनुमान 1 लाख 17 हजार 36 करोड़ रुपये हैं।

मध्यप्रदेश की जनजातियां - सामान्य परिचय

व्यक्तित्व

किसी भी व्यक्ति की पहचान उसका चेहरा होता है। जिन तत्वों से मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। चेहरा उनमें प्रमुख है। चेहरे की बनावट के अलावा रंग, शरीर का गठन, चाल-ढाल और आचार-व्यवहार मनुष्य के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। शरीर की बाह्य संरचना के ये विम्ब भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु और वातावरण पर अधिक निर्भर करते हैं।

मध्यप्रदेश की आदिम जनजातियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर वर्गीकृत रूप में पहचाना जा सकता है, उदाहरण के तौर पर, गोंड जनजाति के लोगों का चेहरा थोड़ा चपटा होता है। इनका माथा चौड़ा, नाक कुछ दबी और नथुने फैले हुये होते हैं। इनकी आंखें काली, पलकें पुष्ट तथा बाहर की ओर उठी हुई दिखाई देती हैं। मध्यम कद और सुगठित शरीर वाले गोंड जनजाति के लोग सामान्यतः श्यामवर्णी होते हैं। स्त्रियां भी सांवली, पुष्ट एवं चुस्त होती हैं। गोंड प्रायः लजीले स्वभाव के, किन्तु परिश्रमी होते हैं। तीखे नाक-नक्श वाले भील अपने सुरुचिपूर्ण परिधान और विशिष्ट प्रकार के आभूषणों से अलग दिखते हैं।

छिन्दवाड़ा जिले की तामिया तहसील अंतर्गत पातालकोट के भारिया छरहरे वदन के होते हैं। इनकी आंखें कुछ छोटी, नाक चौड़ी किन्तु सुडौल होती है। होठ पतले, करीने की दंत पंक्तियां अपनी चाल, ढाल और उठने-बैठने के विशेष अंदाज के कारण भारिया जनजाति के लोग गोंड और कोरकू जनजाति से अलग पहचान रखते हैं। कोरकू जनजाति के लोग चेहरे-मोहरे से गोंड जनजाति के जैसे होते हैं, परन्तु ये अपने ऊंचे कद तथा घुंघराले वालों की वजह से अलग दिखते हैं। पुरुषों की दाढ़ी में बाल कम होते हैं। स्त्रियां सुन्दर होती हैं।

सामान्य नाक-नक्श और औसत शरीर वाले श्यामवर्णी सहरिया जनजाति के लोगों के बाल प्रायः उलझे होते हैं फिर भी इन्हें अलग से पहचान पाना थोड़ा कठिन होता है। परन्तु वैगा जनजाति के सदस्य अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण दूर से ही पहचाने जा सकते हैं। सिर्फ लंगोटी पहने हाथों में तीर-कमान या कंधे पर छोटी

मध्यप्रदेश जनजाति बाहुल्य प्रदेश है। प्रदेश में 43 जनजातियां पाई जाती हैं। धार, झाबुआ और अलीराजपुर भील जनजाति बाहुल्य जिले हैं। मण्डला, डिंडौरी, शहडोल और अनूपपुर वैगा विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिले हैं। सीधी, सिंगरौली, सतना, रीवा और उमरिया जिले में कोल जनजाति पाई जाती है। छिन्दवाड़ा जिले के तामिया तहसील में विशेषकर पातालकोट में भारिया नामक विशेष पिछड़ी जनजाति पाई जाती है। अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर मुरैना और ग्वालियर जिलों में सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त रतलाम, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, होशंगाबाद, बैतूल, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, बुरहानपुर जिले में भी जनजाति बहुतायत संख्या में पाई जाती है। गोंड जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है, जो सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में पाई जाती है। रोज़गार और निर्माण के इस अंक में मध्यप्रदेश की जनजातियों से संबंधित विभिन्न उपयोगी जानकारीयां प्रकाशित की जा रही हैं।

कुल्हाड़ी लिये अपने उलझे काले बालों में वेपरवाह श्यामवर्णी वैगा जनजाति के सदस्य हंसमुख और मस्तमौला होते हैं। ये अपने व्यवहार से तुरंत प्रभावित कर लेते हैं, जो कि इनके व्यक्तित्व का विशेष गुण है। यह विशेषता प्रत्येक जनजाति समुदाय में अलग-अलग ढंग से पाई जाती है।

परिधान

प्रदेश में भिन्न-भिन्न जनजातियों के परिधान में अंतर पाया जाता है। गौर से देखें तो पहनावे में यह अंतर सीमाओं के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण अधिक पाया जाता है, इसलिये समान जनजाति के भिन्न स्थानों के लोगों में भी यह अंतर परिलक्षित किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश में सामान्यतः गोंड जनजाति के व्यक्ति घुटनों तक अधोःवस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती और बंडी पहनते हैं। कंधे पर पिछौरा डाल कर सिर पर मुरैठा बांधते हैं। स्त्रियां घुटने तक साड़ी काँछ लगा कर पहनती हैं। पोलका पहने बिना वे बाहर नहीं निकलतीं। गोंड जनजाति को गहरे रंग पसन्द हैं। श्रृंगार प्रिय भील जनजाति के व्यक्तियों को भी चटक रंग भाते हैं। पुरुष सिर पर रंगीन साफ़ा पहनते हैं। उस पर गोफन लिपटा रहता है। भील जनजाति के लोग घुटनों तक धोती और उस पर बंडी भी पहनते हैं। स्त्रियां गहरे लाल, पीले, कथई और काले रंग के बेल बूटे वाले भिलौंडी लहंगें अथवा घुटनों तक घाघरा पहनती हैं, ऊपर झुलडी (पोलका) अथवा काँचली कुर्ती पहनना उन्हें अच्छा लगता है।

कोरकू जनजाति साधारण पोषाक पसंद करते हैं। कोरकू जनजाति के व्यक्ति घुटनों तक सफेद धोती और उसके ऊपर सूती बंडी या कुर्ता पहनना पसंद करते हैं एवं सिर पर पगड़ी अथवा अंगोछा बांधते हैं। कोरकू जनजाति की स्त्रियां रंग-विरंगे लुगड़े और चोली ही प्रायः पहना करती

हैं। भारिया जनजाति भी पहनावे के मामले में कोरकू जैसे ही हैं। पुरुष धोती पर कुर्ता और बंडी तथा सिर पर पगड़ी पहनते हैं। भारिया जनजाति की स्त्रियां लाल रंग की सेंदरी साड़ी और पोलका पहनना अधिक पसंद करती हैं। वृद्ध महिलाएं साड़ी को घुटने तक लपेट कर पहनती हैं।

सहरिया जनजाति के व्यक्ति धोती के साथ रंगीन कमीज और साफ़ा धारण करते हैं। स्त्रियां लहंगा, घाघरा, लुगड़ा और सलूखा पसंद के रंगों से चुनती हैं। वैगा जनजाति के पुरुष पहनावे के प्रति अधिक उत्साहित दिखाई नहीं देते हैं। मात्र लंगोटी अथवा कभी-कभी उस पर बंडी वैगा पुरुषों का परिधान है। वैगा जनजाति की स्त्रियां भी घुटनों तक ही लुगड़ा पहनती हैं। अन्य जनजातियों की वेश-भूषा की भी अपनी-अपनी अलग पहचान है।

अलंकार

मध्यप्रदेश में गोंड जनजातियों की स्त्रियों को आभूषणों से गहरा लगाव है। वे हाथों में सौभाग्य का प्रतीक चूड़ियां धारण करती हैं। चूड़ियां, पटा बहूआ, चुटकी तोड़ा, पेरी सतुवा, हमैल, ढार, ढरका, तरकी बारी और टिकुसी आदि गोंड जनजाति की स्त्रियों के पारम्परिक अलंकरण हैं। गोंड जनजाति के पुरुष भी कलाई में चांदी का चूड़ा, गले में मोहर तथा कान में बूँदा चाव से पहनते हैं। अंगूठी का प्रचलन स्त्री और पुरुष दोनों में है।

भील जनजाति में सर्वाधिक पारंपरिक आभूषण पाये जाते हैं। भील जनजाति की स्त्रियां सिर से पांच तक गहने से लदी रहती हैं। वे मस्तक पर बोर गुंथ कर लड़ियां झुलाती हैं। लड़ियां कानों में अलग से झूलती हैं। वे गले में हंसली और हार, हाथ-पांव में कोहनी तथा घुटनों तक कथिर के कड़ों से अलंकृत रहती हैं। नाक में चांदी का कांटा और कमर में कंदौरा सुशोभित होता है। कमर के साथ-साथ इनके माथे,

कान और बाजूओं में भी रंग-विरंगे मोती के लड़ झूलते रहते हैं। पावों में बंधे घुंघरू वातावरण को झंकृत कर भील जनजाति की स्त्रियों की उपस्थिति का अहसास कराते रहते हैं। भील जनजाति के पुरुष भी आभूषणों के कम शौकीन नहीं होते हैं। कानों में चांदी की लड़ें, कलाईयों में कड़े और कमर में चांदी के ही कंदौरे भीलों को एक अलग व्यक्तित्व और शोभा से अलंकृत करते हैं। ये भी कमर और पांवों में घुंघरू बांधने से परहेज नहीं करते हैं।

कोरकू जनजाति के पुरुष गले में ताबीज व माला, कानों में लाल-पीले या सफेद जंरूंग (बेलफूल) तथा मुरकी, हाथ में कड़ा और कमर में कंदौरा पहनते हैं। स्त्रियां गले में तागली, हंसली तथा रंग विरंगे मोती-मूंगा पोत और सिक्कों की मालाएं पहनती हैं। पैरों में चांदी, पीतल या कांसे के ठोस छल्ले-पाजेव एवं कंकर वाले छल्ले पहनना कोरकू जनजाति की महिलाओं को भाता है। वे मछली के आकार की विछियां अधिक पसंद करती हैं। भुजाओं में बावटया भी उनका प्रिय अलंकरण हैं।

मध्यप्रदेश की प्रायः सभी जनजातियों में गोदने का प्रचलन है। गोदने को वे ऐसा अंकरण मानते हैं, जो शरीर छूटने के बाद भी आत्मा का श्रृंगार करता है। सभी जनजातियों की केश-विन्यास की अपनी-अपनी शैली है। काजल का प्रयोग लगभग सभी आदिवासी समुदाय करते हैं। पारम्परिक आभरण तो सबके अपने-अपने हैं ही, केवल वैगा जनजाति में अलंकार के प्रति उत्साह अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है।

नृत्य संगीत

जनजातीय संसार में नृत्य और संगीत उनकी अनुठी किन्तु सहज जीवनशैली के अभिन्न अंग हैं। दिन भर के श्रम की

थकान को आनंद में संतरित करने का उनका अपना नियमित विधान है। गोंड जनजाति के लोग जब करमा, शैला, भड़ैनी, विरहा, कहरवा तथा सुआ आदि नृत्य में तल्लीन होते हैं तो थकान, दुख और अपना अस्तित्व भूलकर आनंदोत्सव में शामिल हो जाते हैं। गोंड जनजाति के लोगों का ‘सजनी’ गीत-नृत्य की भाव-मुद्राएं तो चमत्कृत करने वाली होती हैं। उनका दीवाली-नृत्य भी अद्भुत होता है। मांदल, टिमकी, सिंगवाजा, नगाड़ा, मंजीरा, खरताल, ठिसकी, चुटकी, झांझ, बांसुरी, शहनाई, अलगोझा, तमुरा, चिकारा और किंदरी आदि वाद्य गोंड नर्तकों के मन में उत्साह, पांवों में थिरकन तथा कंठ में नाद का संचार करते हैं।

कोरकू जनजाति के नृत्य प्रायः पर्वों के प्रसंग में तथा मिथकों पर आश्रित अधिक होते हैं। ये नृत्य वर्ष भर चलते रहते हैं। चैत्र में देव दशहरा, चाचरी और गोंगोल्या, वैशाख में थापटी, ज्येष्ठ में ढांढल और डोडबली, श्रावण में डंडा नाच, कवार में होरोरया और चिल्लडी, कार्तिक की पड़वा पर ठाटया तथा वैवाहिक अवसरों पर स्त्रियों का गादली नृत्य प्रचलित है। कोरकू आदिवासी विभिन्न नृत्यों के साथ ढोल, ढोलक, मृदंग, टिमकी, डफ, अलगोझा, बांसुरी, भूगडू, पवई, चिटकोरा और झांझ आदि वाद्यों का प्रयोग करते हैं। ये नृत्य के लिये विशेष सज्जा और वेशभूषा को महत्व नहीं देते हैं।

भारिया जनजाति के लोग भडम, सैतम और करत-सैला नृत्य में अधिक रुचि लेते हैं। वे नृत्य के समय ढोल, टिमकी, झांझ, ढोलक व बांसुरी आदि वाद्यों का प्रयोग करते हैं। भारिया जनजाति की युवतियां मंजीरा और चिटकुला के साथ अपने उल्लास को व्यक्त करती हैं। भील जनजाति के नृत्य को सोलो कहते हैं। लाहरी, डांग सोलो, पाली, चलावणी, दौडावणी और घोड़ी भील आदिवासियों के प्रिय नृत्य रूप हैं। ढोल, मांदल, कुण्डी, कांसे की धाली और बाहली (बांसुरी) के अलावा चपटे मुंह वाला अलगुंजा तथा वांस की चिपलियों से बने केन्द्रिया भील जनजातियों के मनपसंद वाद्य हैं।

- लालजीराम मीना

(लेखक, आदिवासी अनुसंधान विशेषज्ञ हैं)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये सामान्य ज्ञान - खेल

- आईसीसी ने वर्ष 2021 के लिए किस खिलाड़ी को वूमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है।
(अ) एलिस पेरी (ब) स्मृति मंधाना (स) लिजेल ली (द) टैमी ब्यूमॉट
- शीतकालीन ओलिंपिक खेल-2022 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं।
(अ) नॉर्वे (ब) डेनमार्क (स) कनाडा (द) अमेरिका
- लुईस हैमिल्टन ने फॉर्मूला-वन चैम्पियनशिप-2021 में कितनी रेस जीती हैं।
(अ) चार (ब) पांच (स) सात (द) आठ
- वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी को ग्लोब सॉकर अवॉर्ड में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है।
(अ) किलियन एम्बापे (ब) रॉबर्ट लेवानडोवस्की (स) इकेर कैसिलास (द) फिलिप कोटिन्हो
- इनमें से किस भारतीय बल्लेबाज ने 100 टेस्ट मैच नहीं खेले हैं।
(अ) सुनील गावस्कर (ब) मोहम्मद अजहरुदीन (स) सौरव गांगुली (द) राहुल द्रविड
- वर्ष 2023 में वर्ल्ड बाॅक्सिंग

- चैम्पियनशिप किस देश में आयोजित की जायेगी।
(अ) अजरबैजान (ब) कजाकिस्तान (स) उज्बेकिस्तान (द) कतर
- इनमें से कौन-सा देश एफआईएच प्रो लीग-2022 का हिस्सा नहीं है।
(अ) दक्षिण अफ्रीका (ब) पाकिस्तान (स) अर्जेंटीना (द) जर्मनी
- अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी पीट सैम्प्रास ने कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं।
(अ) 10 (ब) 12 (स) 14 (द) 16
- मर्डेका स्टेडियम किस देश का एक प्रसिद्ध स्टेडियम है।
(अ) मलेशिया (ब) इटली (स) ब्राजील (द) न्यूजीलैंड
- रंगास्वामी कप भारत में किस खेल की एक प्रतियोगिता है।
(अ) क्रिकेट (ब) बैडमिंटन (स) निशानेबाजी (द) हॉकी
- भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में किस वर्ष हिस्सा लिया था।
(अ) वर्ष 1934 (ब) वर्ष 1938 (स) वर्ष 1954 (द) वर्ष 1958

- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् की अध्यक्षता करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति हैं।
(अ) इमरान ख्वाजा (ब) जगमोहन डालमिया (स) शशांक मनोहर (द) जहीर अब्बास
- सोमदेव देववर्मन किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(अ) बैडमिंटन (ब) मुक्केबाजी (स) टेनिस (द) नौकायन
- टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं।
(अ) जसप्रीत बुमराह (ब) युजवेंद्र चहल (स) हरभजन सिंह (द) आर.पी. सिंह
- महिला क्रिकेटर एमी हंटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश के लिए खेलती हैं।
(अ) ऑस्ट्रेलिया (ब) वेस्टइंडीज (स) आयरलैंड (द) नीदरलैंड
- वर्ष 2011 में किस देश ने फीफा महिला वर्ल्डकप का खिताब जीता है।
(अ) अमेरिका (ब) स्वीडन (स) कनाडा (द) जापान
- भारत ने हाल ही में किस देश को

- हराकर आईसीसी अंडर-19 वर्ल्डकप जीता है।
(अ) इंग्लैंड (ब) बांग्लादेश (स) न्यूजीलैंड (द) दक्षिण अफ्रीका
- वर्ष 2008 में आईपीएल का पहला सीजन किस टीम ने जीता था।
(अ) मुंबई इंडियंस (ब) राजस्थान रॉयल्स (स) डेक्कन चार्जर्स (द) कोलकाता नाइटराइडर्स
- वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी ने मलेशिया ओपन स्क्वाॅश टूर्नामेंट जीता है।
(अ) सौरव घोषाल (ब) मिगुएल रोड्रिगेज (स) अब्दुल्ला अल तमीमी (द) निकोलास मुलर
- वर्ष 2018-19 में किस क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता था।
(अ) लिवरपूल (ब) आर्सेनल (स) चेल्सी (द) मैनचेस्टर सिटी
- खा-खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं।
(अ) सात (ब) आठ (स) नौ (द) ग्यारह
- वेस्टइंडीज ने कितने बार आईसीसी टी-20 क्रिकेट वर्ल्डकप जीता है।

- (अ) एक बार (ब) दो बार (स) तीन बार (द) इनमें से कोई नहीं
- गैम्बिट और स्टेल्मेट टर्म किस खेल से संबंधित हैं।
(अ) हॉकी (ब) टेनिस (स) गोल्फ (द) शतरंज
- ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ष एशेज सीरीज में इंग्लैंड को किस अंतर से हराया है।
(अ) 2-0 (ब) 3-0 (स) 4-0 (द) 4-1
- राफेल नडाल ने कितने बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है।
(अ) एक बार (ब) दो बार (स) तीन बार (द) पांच बार

उत्तर

- (ब), 2. (अ), 3. (द), 4. (अ), 5. (ब), 6. (स), 7. (ब), 8. (स), 9. (अ), 10. (द), 11 (अ), 12. (ब), 13. (स), 14. (ब), 15. (स), 16. (द), 17. (अ), 18. (ब), 19. (अ), 20. (द), 21. (स), 22. (ब), 23. (द), 24. (स), 25. (ब)

- पुष्पेंद्र कुमार सविता

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)

डिजिटल दुनिया में बढ़ते करियर के मौके

‘रोज़गार और निर्माण’ के पाठकों के लिये ‘करियर की राहें’ नाम से उपयोगी स्तंभ लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। अच्छे करियर के लिये जरूरी है कि युवा करियर की विभिन्न विधाओं से परिचित हों और अपनी रुचि, योग्यता और क्षमताओं के अनुरूप अपने लिये उपयुक्त करियर का निर्धारण करें। पिछले 40 वर्षों से नई पीढ़ी के लिये करियर संबंधी विषयों पर नियमित लेखन कर रहे, डॉ. जयंतीलाल भंडारी युवाओं को करियर के विभिन्न अवसरों से परिचित कराते हुये आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दे रहे हैं।



निःसंदेह इस समय आगे बढ़ रही डिजिटल इकोनॉमी में भारत की नई पीढ़ी के लिए देश व दुनिया में करियर के सुनहरे मौके तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते व्यापक रोज़गार के अवसर पैदा हो सकते हैं, वहीं इसकी वजह से परंपरागत नौकरियां समाप्त हो सकती हैं। ऐसे में 2025 तक डिजिटलीकरण से करोड़ों नई नौकरियां निर्मित होते हुए दिखाई देंगी। इसमें कई ऐसी डिजिटल नौकरियां होंगी जिनके नाम तक हमने नहीं सुने हैं।

डिजिटलीकरण से बढ़ रही है डिजिटल इकोनॉमी

गौरतलब है कि डिजिटल इकोनॉमी का अर्थ है कम्प्यूटर और इंटरनेट पर आधारित इकोनॉमी। डिजिटलीकरण बढ़ने के साथ-साथ डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है। देश में सरकारी सेवाओं के लिए डिजिटलीकरण को अधिकतम प्रोत्साहन और 44 करोड़ से अधिक जनधन खातों में कोरोनाकाल में धन हस्तांतरण से डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला है। मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रेफिक (एमबीट) इंडेक्स 2021 के मुताबिक डेटा खपत बढ़ने की

रफ़्तार पूरी दुनिया में सबसे अधिक भारत में है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक भारत में ब्रॉडबैंड उपयोग करने वालों की संख्या मार्च 2014 के 6.1 करोड़ से बढ़कर जून 2021 में 79 करोड़ पहुंच चुकी है। कोरोनाकाल के कारण वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) और आउटसोर्सिंग को व्यापक तौर पर बढ़ावा मिलने से भारत की डिजिटल कारोबार अहमियत बढ़ी है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ तथा विभिन्न डिजिटल आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं।

वर्ष 2022-23 के बजट से बढ़ेंगे डिजिटल रोज़गार के मौके

गौरतलब है कि एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए 2022-23 के बजट प्रावधानों में विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सुनहरा अध्याय लिखा गया है और इससे रोज़गार के मौके तेजी से बढ़ेंगे। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे। देश के डाकघर भी ऑनलाइन सेवाएं मुहैया कराएंगे। 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे। इसके साथ ही बैंक से पोस्ट ऑफिस के खातों में



ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकेगा। यही नहीं डाकघर के लिए भी एटीएम सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 5जी मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इसके बाद से निजी दूरसंचार कंपनियां देश में 5जी सेवाओं की शुरुआत कर पाएंगी। 5जी सुविधा प्रारंभ होने के बाद उपयोगकर्ता अपने 5जी स्मार्टफोन का और बेहतर तरीके से उपयोग कर सकेंगे। इसके साथ ही 5जी के आने से देशभर में इंटरनेट यूजर्स को हाई-स्पीड नेट सर्फिंग और फास्ट वीडियो स्ट्रीमिंग का विल्कुल नया लाभ मिलेगा। पीएम ई-विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जायेगी।

डिजिटल इकोनॉमी में इन क्षेत्रों में हैं रोज़गार और स्वरोज़गार के अच्छे अवसर

डिजिटल इकोनॉमी के तहत कॉमर्स, बैंकिंग, मार्केटिंग, ट्रांजैक्शन, डेटा एनालिसिस, सायबर सिक्योरिटी, आईटी, टूरिज्म, रिटेल ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी आदि क्षेत्रों में रोज़गार और स्वरोज़गार के मौके हैं। उल्लेखनीय है कि डिजिटलीकरण के कारण ई-कॉमर्स तेजी से आगे बढ़ा है। विश्व प्रसिद्ध ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म अलवारेज एंड मार्शल इंडिया और सीआईआई इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स द्वारा तैयार रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत में ई-कॉमर्स का जो कारोबार वर्ष 2010 में एक अरब डॉलर से भी कम था, वह वर्ष 2019 में 30 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया और अब 2024 तक 100 अरब डॉलर के पार पहुंच सकता है। डिजिटल रोज़गार के लिए समय, दूरी और कार्यस्थल संबंधी कोई सीमाएं नहीं हैं।

डिजिटल इकोनॉमी में करियर के लिए जरूरी स्किल्स

डिजिटल इकोनॉमी में करियर के लिए कुछ विशेष स्किल्स जरूरी हैं। इनमें अच्छी अंग्रेजी, कम्प्यूटर-आईटी दक्षता, कम्प्युनिकेशन स्किल्स, जनसंचार, वेब

डिजाइन, वेब संबंधित सॉफ्टवेयर का अच्छा ज्ञान, विश्लेषणात्मक कौशल, बाजार अनुसंधान, ईमेल, यू-ट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट्स, गूगल एड, सर्व रिजल्ट आदि के बारे में अच्छी जानकारी शामिल है।

डिजिटल इकोनॉमी से संबंधित विभिन्न कोर्स

डिजिटल इकोनॉमी में अच्छा करियर बनाने के लिए इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स, मार्केटिंग, कम्प्यूटर एवं आईटी क्षेत्र की डिग्रियां लाभप्रद होती हैं। देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों और कई निजी संस्थानों में डिजिटल इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टरों से संबंधित सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स संचालित हैं। यदि आप डिजिटल इकोनॉमी में करियर बनाना चाहते हैं तो अपनी उपयुक्तता के अनुसार डिजिटल इकोनॉमी से सम्बद्ध किसी कोर्स के लिए अच्छे संस्थान का चयन करके करियर की राह पर आगे बढ़ सकते हैं।

- डॉ. जयंतीलाल भंडारी

(लेखक करियर मार्गदर्शन के लिये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रतिष्ठित हैं।)

मनरेगा से ग्रामीण भारत हो रहा है सशक्त

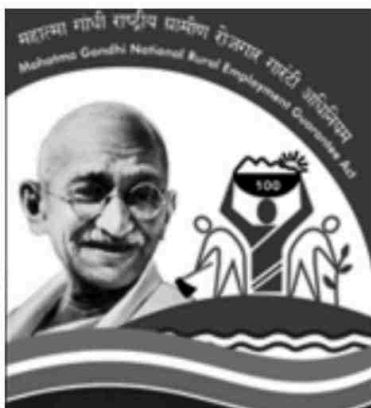
देश ही नहीं विश्व के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)। यह एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, वर्तमान में इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से शहरों की श्रेणी में आने वाले कुछ जिलों को छोड़कर देश के सभी जिले शामिल हैं। मनरेगा के तहत मिलने वाले वेतन के निर्धारण का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास है। महात्मा गांधी नरेगा या मनरेगा का साथ पाकर आज रूरल इंडिया यानि ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल गई है। मनरेगा सबसे बड़ी रोज़गार सृजन योजनाओं में से एक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैकल्पिक रोज़गार प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने इसके माध्यम से करोड़ों इच्छुक ग्रामीण कामगारों को सुनिश्चित रोज़गार मुहैया कराया है। मनरेगा ने ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मज़दूरों के लिये एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है। आज मनरेगा के अंतर्गत देशभर के 29 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 6,50,244 गांवों, 2,62,380 ग्राम पंचायतों, 686 जिलों और 6,888 ब्लॉक को कवर किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का गारंटीशुदा रोज़गार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण करना, जिससे आजीविका में वृद्धि हो। गांवों के जंगल, जल एवं पर्यावरण की रक्षा करना। महिलाओं का सशक्तिकरण। गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाना और सामाजिक समरसता एवं समानता सुनिश्चित करना भी इसके प्रमुख उद्देश्यों में से हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों

के अनुसार मनरेगा लाभार्थियों में एक-तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य है। साथ ही दिव्यांग एवं अकेली महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी एक मांग प्रेरित अधिनियम है। यानि यह कानून कहता है कि हितग्राही के काम मांगने पर 15 दिनों के भीतर रोज़गार दिया जाएगा। नहीं दिया तो 16वें दिन से बेरोज़गारी भत्ता पाने का कानूनी अधिकार होगा। कार्य की अन्य सभी मांगें जहां लाभार्थी ने चालू वित्तीय वर्ष में 100 दिन पहले ही पूरे कर लिए हैं या लाभार्थी जिसने काम की मांग की है, लेकिन काम की मांग की तारीख से 15 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई है, तो वह बेरोज़गारी भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा। मनरेगा भारत के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है और पानी के विकराल होते संकट के असर को कम करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके तहत कामगारों के लिए ग्राम सभा और पंचायत खुद तय करेंगी कि उनसे कौन से काम कराए जाने हैं जो गांव के विकास में सहयोगी बनें। उनसे क्या लाभ होगा और वे ही कामों का सोशल ऑडिट करने के लिए भी अधिकृत हैं। 2021-22 में इसके द्वारा लाभार्थियों द्वारा की गई मांग के अनुसार 310.01 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवसों का सृजन किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत 30.12 करोड़ कामगार कार्य कर रहे हैं। वहीं 15.81 करोड़ को जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने में मनरेगा का योगदान

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायतों को अपने गांवों में स्वच्छता के महत्व की ओर ध्यान देने तथा ऐसे काम करने के लिए शिक्षित और



प्रोत्साहित करने के बारे में विभिन्न कदम उठाए हैं, जिससे लोगों की आजीविका में सुधार हो सके। मंत्रालय ने सोक पिट्स के निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (वर्मी/एनएडोईपी कम्पोस्ट पिट) और एसएलडब्ल्यूएम कार्य (ड्रेनेज चैनल, तरल जैव खाद, रिचार्ज पिट, स्कूल और आंगनवाड़ी शौचालय, सोकेज चैनल, ग्राम नाली और स्थिरीकरण तालाब) जैसे स्वीकृति योग्य कार्य करने पर जोर दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर देश भर में 29 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2021 तक महात्मा गांधी नरेगा के तहत एक सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छ हरित ग्राम पहल का आयोजन किया गया था। स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह के दौरान वर्मी कम्पोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण, अकार्बनिक कचरे के प्रसंस्करण और जल निकासी गड्ढों के निर्माण, वर्मी कम्पोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थों के दोबारा उपयोग, गैर-वायोडिग्रेडेबल कचरे की रीसाइक्लिंग जैसी 'वेस्ट टू वेल्थ' पहलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

कोरोनाकाल में मनरेगा ने निभाई अहम भूमिका

आपको याद होगा कोविड संकट के दौरान जब बहुत से लोगों को शहरों से

काम छोड़कर अपने गांव वापस लौटना पड़ा था तो ऐसे ग्रामीणों की मदद के लिए भी केंद्र सरकार ने जिम्मा संभाला था। उस दौरान केंद्र सरकार ने इन ग्रामीणों को उनके गांव में या गांव के नजदीक ही हो रहे सरकारी निर्माण कार्यों में रोज़गार उपलब्ध कराया था। केवल इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से देश में महिलाओं के सशक्तिकरण में भी बड़ी भूमिका अदा की है। अब जब लोगों को अपने ही गांवों में कार्य मिल रहा है तो इससे ग्रामीणों का शहरों की ओर होने वाला पलायन घट रहा है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर राज्य सरकारों के साथ करीबी सहयोग में कई कदम उठाए हैं। 'पीएम गरीब कल्याण योजना' के तहत 1 अप्रैल, 2020 को मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की औसत राष्ट्रीय वृद्धि की गई थी। वहीं सरकार ने निर्देश दिए थे कि लॉकडाउन की अवधि में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन न होने पाए और सामाजिक दूरी के मानदंडों का गंभीरतापूर्वक पालन किया जाए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ा मनरेगा का बजट : 2022-23 में 73,000 करोड़ रुपये

इस बार केंद्र सरकार ने मनरेगा का 2022-23 का बजट 73,000 करोड़ रुपये रखा है। इसके अलावा जब भी अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होती है तो वित्त मंत्रालय से फंड जारी किए जाने का अनुरोध किया जा सकता है। इससे साफ होता है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मनरेगा अधिनियम ग्रामीण कामगारों को अधिक रोज़गार मुहैया कराने में सक्षम रहा है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2021-22 के बीच 2,092 करोड़ रुपये सृजित मानव श्रम दिवस रहा। केवल इतना

ही नहीं 2014 से अब तक कुल 592.32 लाख कार्य भी पूरे हुए हैं और 6.13 करोड़ परिसंपत्तियां भी सृजित की जा चुकी हैं। 2021-22 में 15.3 करोड़ सक्रिय कामगारों ने महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्य किया। इससे उन्हें इस योजना का लाभ मिला और रोज़गार के साथ अपने गांव में ही आजीविका कमाने का अवसर प्राप्त हुआ। साल 2021-22 के दौरान डीबीटी लेनदेन 46.02 करोड़ रुपये रहा है। वहीं इस योजना से लाभित परिवारों की संख्या कुल 6.84 करोड़ रही। यह तमाम आंकड़े दर्शाते हैं कि केंद्र सरकार गांव में लोगों को 100 दिन का गारंटीशुदा रोज़गार किस प्रकार मुहैया कराती है।

मध्यप्रदेश मनरेगा के

क्रियान्वयन में देश में सबसे आगे

प्रदेश में योजना में निर्धारित लेबर बजट 25 करोड़ मानव दिवस के विरुद्ध 23 करोड़ 95 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जो उपलब्धि का 92 प्रतिशत है। योजना अंतर्गत निर्माण कार्य की संख्या में मध्यप्रदेश पूरे देश में चौथे स्थान पर है। योजना के प्रारंभ होने से दिसंबर 2021 तक पूरे देश में 6 करोड़ से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण हुए हैं, इनमें से 56 लाख से अधिक निर्माण कार्य मात्र मध्यप्रदेश में हुए थे। मनरेगा अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत कार्यों में देश में पहली बार अनाज भण्डारण के लिए संरचना निर्माण का प्रावधान किया गया है। राज्य में मार्कफेड द्वारा सुझाए गए डिजाइन के आधार पर पक्का चबूतरा (CAP) का निर्माण मनरेगा से किया गया।

- रश्मि रंजन

(लेखिका, समसामयिक मुद्दों पर लेखन करती हैं।)

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

सामान्य ज्ञान

- (1) राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -
1. क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 213 में वर्णित है।
2. अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 161 में वर्णित है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों।
D. न तो 1 और न ही 2।
उत्तर- विकल्प D सही है।
व्याख्या- उपर्युक्त में से कथन-1 और 2 गलत हैं।
● राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद-161 के तहत क्षमादान की शक्ति एवं अनुच्छेद-213 के तहत अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
- (2) मध्यप्रदेश के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे:-
1. श्री पट्टाभि सीतारामैया
2. श्री के.सी. रेड्डी
3. श्री पी.वी. दीक्षित
कूट:-
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. उपर्युक्त सभी।
उत्तर- विकल्प A सही है।
व्याख्या- मध्यप्रदेश के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे:-
● श्री पट्टाभि सीतारामैया जी
● श्री के.सी. रेड्डी जी
● श्री हरि विनायक जी
● श्री सी.एम. पुनाचा जी
- (3) निम्न में से किसने मध्यप्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य नहीं किया है?
A. श्री कृष्ण मोहन सेठ
B. श्री पी.वी. दीक्षित
C. श्री भगवत दयाल शर्मा
D. श्री जे.पी. सिंह
उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या- मध्यप्रदेश में अब तक पांच बार कार्यवाहक राज्यपाल ने कुर्सी संभाली हैं :-
● श्री कृष्ण मोहन सेठ
● श्री एन.डी. ओझा
● श्री जे.पी. सिंह (2 बार)
● श्री पी.वी. दीक्षित
- (4) भोपाल गैस कांड के समय मध्यप्रदेश का राज्यपाल कौन था?
A. श्री आनंदीबेन पटेल
B. श्री एन.डी. ओझा
C. श्री के.एम. चांडी
D. श्री भगवत दयाल शर्मा
उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या- भोपाल गैस कांड 2-3 दिसंबर, 1984 की मध्यरात्रि में हुआ उस समय मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री के.एम. चांडी (15 मई, 1984 से 30 नवंबर, 1987 तक) थे।
- (5) मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे?
A. अर्जुन सिंह
B. दिग्विजय सिंह
C. सुंदर लाल पटवा
D. वीरेंद्र कुमार सकलेचा
उत्तर- विकल्प B सही है।
व्याख्या- मध्यप्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (1998 से 8 दिसंबर, 2003 तक) थे।
- (6) निम्न में से मध्यप्रदेश का उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं?
1. श्रीमती जमुना देवी
2. श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा
3. श्री कैलाश चंद्र जोशी
कूट:-
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. इनमें से कोई नहीं।
उत्तर- विकल्प A सही है।
व्याख्या- अब तक मध्यप्रदेश में चार व्यक्ति उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हो चुके हैं:-
● श्रीमती जमुना देवी
● श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा
● श्री शिवभानु सोलंकी
● श्री सुभाष यादव
- (7) निम्नलिखित संस्थाओं में मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है?
1. मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद
2. राज्य योजना मंडल
3. मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद
4. महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान
कूट:-
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 3 और 4
D. उपर्युक्त सभी।
उत्तर- विकल्प D सही है।
व्याख्या- उपर्युक्त सभी संस्थाओं में मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है।
- (8) मध्यप्रदेश की नई विधानसभा 'इंदिरा गांधी विधान भवन' का उद्घाटन कब हुआ?
A. 3 अगस्त, 1996
B. 15 अगस्त, 1996
C. 20 जनवरी, 1996
D. 26 जनवरी, 1996
उत्तर- विकल्प A सही है।
व्याख्या- नई विधानसभा इंदिरा गांधी विधान भवन का उद्घाटन 3 अगस्त, 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया।
- (9) नई विधानसभा 'इंदिरा गांधी विधान भवन' के निर्माण कार्य को तीव्र गति से करने हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी?
A. बी.के. सिन्हा समिति
B. के.एल. झा समिति
C. साधिकार समिति
D. इनमें से कोई नहीं।
उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या- नई विधानसभा 'इंदिरा गांधी विधान भवन' के निर्माण कार्य को तीव्र गति से करने हेतु तत्कालीन सरकार ने साधिकार समिति (1994) गठित की गई, जिसे तेजी से कार्य को पूर्ण कराने का दायित्व सौंपा गया।
- (10) मध्यप्रदेश में लोक लेखा समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
A. श्री कमलनाथ
B. श्री पी.सी. शर्मा
C. श्री जीतू पटवारी
D. श्री जयवर्धन सिंह
उत्तर- विकल्प B सही है।
व्याख्या- विधानसभा की लोक लेखा समिति का सभापति पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा को नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने वृजेंद्र सिंह राठौर के निधन से रिक्त सभापति के स्थान पर यह नियुक्ति की है।
- (11) मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए?
1. यह राज्य का प्रथम नागरिक सेवक होता है।
2. इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
3. वर्तमान में श्री एम गोपाल रेड्डी मुख्य सचिव हैं।
उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. उपर्युक्त सभी।
उत्तर- विकल्प A सही है।
व्याख्या- कथन 3 गलत है, क्योंकि वर्तमान मुख्य सचिव श्री इकवाल सिंह वैस हैं।
- (12) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं?
A. जस्टिस संजय यादव
B. जस्टिस वी.पी. शुक्ला
C. जस्टिस रवि मल्लिमठ
D. इनमें से कोई नहीं।
उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या- मध्यप्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि मल्लिमठ हैं।
- (13) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए?
1. इसकी स्थापना 1 नवंबर, 1956 को जबलपुर में की गई और उसी समय इंदौर एवं ग्वालियर में खंडपीठ की स्थापना की गई।
2. मध्यप्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजिनी सक्सेना थीं।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों।
D. न तो 1 और न ही 2।
उत्तर- विकल्प B सही है।
व्याख्या- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर, 1956 को जबलपुर में की गई थी किंतु खंडपीठ की स्थापना वर्ष 1968 में इंदौर एवं ग्वालियर में की गई थी। अतः कथन 1 गलत है।
- (14) मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है?
A. जबलपुर
B. इंदौर
C. भोपाल
D. ग्वालियर
उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या- राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित है, जबकि मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में स्थित है।
- (15) निम्नलिखित में से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं?
1. जस्टिस जे.एस. वर्मा
2. जस्टिस रमेश चंद्र लाहोटी
3. जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह
कूट:-
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. उपर्युक्त सभी।
उत्तर- विकल्प D सही है।
व्याख्या- उपर्युक्त सभी।
● जस्टिस जेएस वर्मा
● जस्टिस रमेश चंद्र लाहोटी
● जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह
● जस्टिस शरद अरविंद बोबडे
- (16) किस समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया?
A. अशोक मेहता समिति
B. बलवंत राय मेहता समिति
C. एल.एम. सिंघवी समिति
D. काशी प्रसाद पांडे समिति
उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या- एल एम सिंघवी समिति (1986) की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
- (17) संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है?
A. अनुच्छेद 243 (K)
B. अनुच्छेद 243 (I)
C. अनुच्छेद 243 (E)
D. अनुच्छेद 243 (B)
उत्तर- विकल्प B सही है।
व्याख्या-
● अनुच्छेद 243 (I) राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 243 (K) राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है।
● अनुच्छेद 243 (E) पंचायतों की अवधि आदि का प्रावधान किया गया है।
● अनुच्छेद 243 (B) पंचायतों के गठन का प्रावधान।
- (18) मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम कब बना था?
A. 1992
B. 1982
C. 1972
D. 1962
उत्तर- विकल्प D सही है।
व्याख्या- काशी प्रसाद पांडे समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1962 में पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था।
- (19) पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए?
1. जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है।
2. ग्राम पंचायत के उपसरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों।
D. न तो 1 और न ही 2।
उत्तर- विकल्प B सही है।
व्याख्या-
● 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एवं उसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, अतः कथन 1 गलत है।
● ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि उपसरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, कथन सत्य है।
- (20) 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 'जिला योजना समिति' का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है?
A. अनुच्छेद 243(ZA)
B. अनुच्छेद 243(ZD)
C. अनुच्छेद 243(ZB)
D. अनुच्छेद 243(U)
उत्तर- विकल्प B सही है।
व्याख्या- 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुच्छेद 243(ZD) में प्रत्येक जिले के लिए जिला योजना समिति का प्रावधान किया गया है।
- (21) नगरीय निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :-
1. नगर पंचायत के अध्यक्ष और नगर निगम के महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
2. नगरीय निकाय में एक चौथाई महिला सदस्यों कि आरक्षण का प्रावधान है।
उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों।
D. न तो 1 और न ही 2।
उत्तर- विकल्प A सही है।
व्याख्या-
● 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत तीनों स्तरों पर नगर पंचायत नगर पालिका और नगर निगम के प्रमुख या अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा।
● कुछ राज्यों में नगरीय निकाय में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, हालांकि अधिनियम में एक तिहाई सदस्यों का प्रावधान किया गया है।
- (22) राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है?
1. बोरगांव (छिंदवाड़ा)
2. इंडस फूड पार्क (खरगोन)
3. बावई (होशंगाबाद)
4. दलोदा फूड पार्क (मंदसौर)
कूट:-
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 3 और 4
D. केवल 1 और 3।
उत्तर- विकल्प D सही है।
व्याख्या -
● राज्य सरकार द्वारा बावई (होशंगाबाद), बोरगांव (छिंदवाड़ा), और मनेरी (मंडला) मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है।
● केंद्र सरकार द्वारा:-
1. इंडस फूड पार्क (खरगोन)
2. अवंति फूड पार्क देवास
3. दलोदा फूड पार्क (मंदसौर)
● भारत का पहला मेगा फूड पार्क पतंजलि फूड पार्क हरिद्वार में बनाया गया है।
- (23) मध्यप्रदेश में मृगनयनी एंपोरियम केंद्र कहाँ स्थित नहीं है?
A. भोपाल
B. इंदौर
C. उज्जैन
D. सतना
उत्तर- विकल्प D सही है।
व्याख्या- लघु उद्योग के विकास के लिए वर्ष 1961 में मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। मध्यप्रदेश में मृगनयनी एंपोरियम के केंद्र निम्न जिलों में हैं।
1. इंदौर, 2. भोपाल, 3. ग्वालियर
4. जबलपुर, 5. रीवा।
- (24) निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोका कोला कंपनी का 750 करोड़ लागत का प्लांट प्रस्तावित है?
A. मेघनगर (झाबुआ)
B. सिद्धगवा (सागर)
C. बावई (होशंगाबाद)
D. मनेरी (मंडला)
उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या- मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई में कोको कोला कंपनी द्वारा 750 करोड़ लागत का प्लांट प्रस्तावित है।
- (25) मध्यप्रदेश की प्रथम शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई?
A. जीवाजी शुगर मिल (मंदसौर)
B. सेठ गोविंद दास शुगर मिल (उज्जैन)
C. जावरा शुगर मिल (रतलाम)
D. इनमें से कोई नहीं।
उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या -
● मध्यप्रदेश की पहली शुगर मिल वर्ष 1934 में रतलाम जिले में जावरा शुगर मिल है।
● मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल बरलाई शुगर मिल है।
- (26) मध्यप्रदेश के उद्योग केंद्र सुमेलित नहीं है?
1. पीथमपुर - धार
2. मंडीदीप - भोपाल
3. प्रतापपुरा - निवाड़ी
4. मालनपुर - मुरैना
कूट:-
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 3 और 4
D. केवल 2 और 4।
उत्तर- विकल्प D सही है।
व्याख्या -
● पीथमपुर - धार
● मंडीदीप - रायसेन
● प्रतापपुरा - निवाड़ी
● मालनपुर - भिंड
- श्री वसंत (के.एल.) जाटव (लेखक- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विषयों पर लिखते हैं)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

सामान्य ज्ञान, अंक गणित और तर्कशक्ति

1. अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है -

- (अ) साहित्य (ब) ललित कला
(स) विज्ञान (द) पत्रकारिता

उत्तर- (ब) ललित कला

2. प्रसिद्ध उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा ने उपन्यास "मृगनयनी" में किस राजा का चरित्र-चित्रण किया -

- (अ) छत्रसाल (ब) राजा मानसिंह
(स) बाज बहादुर (द) धंग

उत्तर- (ब) राजा मानसिंह

3. अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केन्द्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है -

- (अ) बौद्ध मत (ब) जैन मत
(स) सिक्ख मत (द) वैष्णव मत

उत्तर- (ब) जैन मत

4. भारतीय रंगमंच में यवनिका (पर्दा) का शुभारंभ किसने किया था -

- (अ) शकों ने (ब) पार्थियनों ने
(स) यूनानियों ने (द) कुषाणों ने

उत्तर- (स) यूनानियों ने

5. कौन सुमेलित नहीं है -

- (अ) प्रयाग प्रशस्ति - रविकीर्ति
(ब) किरातजुनीयम - भारवि
(स) दशकुमार चरित - दंडिन
(द) मृच्छकटिकम् - शूद्रक

उत्तर- (अ) प्रयाग प्रशस्ति - रविकीर्ति

6. महाबलिपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था -

- (अ) चोलों द्वारा (ब) पल्लवों द्वारा
(स) चेदियों द्वारा (द) चालुक्यों द्वारा

उत्तर- (ब) पल्लवों द्वारा

7. निम्न में से कौन-सा सुमेलित नहीं है -

- प्रदूषक होने वाली बीमारी
(अ) पारा - मिनमाटा बीमारी
(ब) कैडमियम - ईटाई-ईटाई
(स) नाइट्रेट आयन - ब्लू बेबी सिंड्रोम
(द) फ्लोराइड आयन - अपच

उत्तर- (द) फ्लोराइड आयन - अपच

8. एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन-सी प्रक्रिया होती है -

- (अ) किण्वन
(ब) अपचयन
(स) हाइड्रोजनीकरण
(द) बहुलकीकरण

उत्तर- (अ) किण्वन

9. निम्नांकित में से 'हंसा-2' किसका नाम है -

- (अ) एक उपग्रह (ब) प्रशिक्षण यान
(स) पनडुब्बी (द) प्रक्षेपास्त्र

उत्तर- (ब) प्रशिक्षण यान

10. राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशांसा से प्रस्तुत किया जा सकता है -

- (अ) अध्यक्ष (ब) वित्त मंत्री
(स) मुख्यमंत्री (द) राज्यपाल

उत्तर- (द) राज्यपाल

11. संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था -

- (अ) शाह आयोग
(ब) प्रशासनिक सुधार आयोग
(स) संथानम समिति
(द) स्वर्णसिंह समिति

उत्तर- (द) स्वर्णसिंह समिति

12. मध्यप्रदेश के किस क्षेत्र से 'हरदोल की मनौती' नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है -

- (अ) मालवा (ब) निमाड़
(स) बुंदेलखण्ड (द) वघेलखण्ड

उत्तर- (स) बुंदेलखण्ड

13. भारत में बिना मिनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्न में से किस राज्य में है -

- (अ) मध्यप्रदेश (ब) उत्तरप्रदेश
(स) तमिलनाडु (द) कर्नाटक

उत्तर- (अ) मध्यप्रदेश

14. किस राजा के बारे में यह कहा गया है कि उसकी मृत्यु से 'विद्या और विद्वान' दोनों निराश्रित हो गये -

- (अ) सिन्धुराज (ब) राजा भोज
(स) मुन्ज (द) यशोवर्मन

उत्तर- (ब) राजा भोज

15. 1930 के 'दुरिया जंगल सत्याग्रह' का नेतृत्व किसने किया था -

- (अ) दुर्गाशंकर मेहता
(ब) गंजन सिंह
(स) सुजान सिंह
(द) कोई नहीं

उत्तर- (ब) गंजन सिंह

16. भारत में इंग्लैंड का कौन-सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था -

- (अ) क्लाइव (ब) थॉमस-रो
(स) लार्ड एस्टर (द) क्लाइड

उत्तर- (ब) थॉमस-रो

17. 'ग्रेन फॉर ग्रीन' योजना क्या है -

- (अ) बीज भंडारण योजना
(ब) शैक्षणिक योजना
(स) वानिकी योजना
(द) जंगल कटाई प्रतिबंध हेतु योजना

उत्तर- (स) वानिकी योजना

18. 'नंदी शाला योजना' का क्या उद्देश्य है -

- (अ) नस्ल सुधार के लिए बेहतर आनुवांशिक क्षमता के सांड का उपयोग करना।
(ब) किसी अन्य राज्य से अच्छी नस्लें खरीदना।
(स) किसानों को निःशुल्क बैल प्रदान करना।
(द) अच्छी नस्ल के बैलों को बाजार में बेचना।

उत्तर- (अ) नस्ल सुधार के लिए बेहतर आनुवांशिक क्षमता के सांड का उपयोग करना।

19. पुरातत्व स्थल 'कायथा' किस नगर के समीप स्थित है -

- (अ) उज्जैन (ब) भोपाल
(स) जबलपुर (द) रीवा

उत्तर- (अ) उज्जैन

20. माडा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ स्थित हैं -

- (अ) सीधी-सिंगरौली
(ब) शिवपुरी
(स) धार
(द) मण्डला

उत्तर- (अ) सीधी-सिंगरौली

21. मध्यप्रदेश के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजाति को प्राप्त आरक्षित सीटों की संख्या है -

- (अ) 04 (ब) 05
(स) 06 (द) 07

उत्तर- (स) 06

22. तैमूर लंग के आक्रमण के समय तुगलक वंश का शासक कौन था -

- (अ) सिकंदर लोदी
(ब) शाहजादा मुहम्मद
(स) फिरोज तुगलक
(द) नासिरुद्दीन महमूद

उत्तर- (द) नासिरुद्दीन महमूद

23. नाथपा-झाकड़ी परियोजना कौन सी नदी पर अवस्थित है -

- (अ) सतलज नदी (ब) कृष्णा नदी
(स) दामोदर नदी (द) गण्डक नदी

उत्तर- (अ) सतलज नदी

24. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की स्थापना कब की गई थी-

- (अ) 1860 (ब) 1875
(स) 1975 (द) 1988

उत्तर- (ब) 1875 में

25. 'नारंग कप' किस खेल से संबंधित है -

- (अ) बैडमिंटन (ब) टेबल टेनिस
(स) शतरंज (द) हॉकी

उत्तर- (अ) बैडमिंटन

26. जंगली सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है -

- (अ) एरैकिस हाइपोजिया
(ब) कैनेबिस सटाइवा
(स) ग्लाइसिन सोजा
(द) साइसर एरिटिनम

उत्तर- (स) ग्लाइसिन सोजा

27. 'स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत' की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है -

- (अ) नीति आयोग
(ब) ICMR
(स) ICAR
(द) कोई नहीं

उत्तर- (अ) नीति आयोग

28. भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली निम्न में से किस शॉर्ट रेंज, बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के तट से किया है -

- (अ) शक्ति (ब) निर्भय
(स) पूर्णिमा (द) प्रलय

उत्तर- (द) प्रलय

29. निम्न में से किसने टोक्यो पैरालिंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है -

- (अ) ज्योति बालियान
(ब) अवनि लखेरा
(स) भाग्यश्री जाधव
(द) कशिश लकड़ा

उत्तर- (ब) अवनि लखेरा

अंक गणित

1. यदि $\frac{a}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{7}$ हो, तो

- $\frac{a+b+c}{c} = ?$
(अ) 2 (ब) $\sqrt{2}$
(स) 3 (द) 7

उत्तर- (अ) 2

हल- माना $\frac{a}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{7} = K$

तब $a=3K$, $b=4K$, $c=7K$

$$\frac{a+b+c}{c} = \frac{3K+4K+7K}{7K}$$

$$= \frac{14K}{7K} = 2$$

2. एक 80 मीटर ऊंचे खम्बे पर एक बंदर एक मिनट में 5 मीटर चढ़ता है परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खम्बे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा -

- (अ) 51 मिनट (ब) 54 मिनट
(स) 58 मिनट (द) 61 मिनट

उत्तर- (अ) 51 मिनट

हल- 2 मिनट में बंदर द्वारा चढ़ी गई दूरी = 3 मीटर

∴ 3 मीटर चढ़ने में लगा समय = 2 मिनट

75 मीटर चढ़ने में लिया गया समय

$$= \left(\frac{2}{3} \times 75\right) \text{ मिनट} = 50 \text{ मिनट}$$

शेष 5 मीटर वह 1 मिनट में चढ़कर खम्बे पर बैठ जाएगा अतः बंदर द्वारा लिया गया कुल समय - 51 मिनट

3. दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है -

- (अ) 90% (ब) 87.5%
(स) 25% (द) 12.5%

उत्तर- (अ) 90%

हल- माना तीसरी संख्या 100 है।

तब पहली संख्या = 112.5 तथा दूसरी संख्या = 125

माना $112.5 = 125$ का $x\%$ है।

$$\text{तब } 125 \times \frac{x}{100} = \frac{225}{2}$$

$$= \frac{225}{2} \times \frac{4}{5} = 90$$

∴ पहली संख्या दूसरी संख्या का 90% है।

4. एक मशीन 120000 रु. में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, दो वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा -

- (अ) 12997 (ब) 97200
(स) 98230 (द) कोई नहीं

उत्तर- (ब) 97200 रु.

हल- 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य

$$= 120000 \times \left(1 - \frac{10}{100}\right)^2$$

$$(\therefore t \text{ वर्ष बाद अवमूल्यन} = \text{क्रय मूल्य} \times \left(1 - \frac{R}{100}\right)^t)$$

$$= 120000 \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} = 97200 \text{ रु.}$$

5. यदि $\frac{3a-4b}{3a+4b} = \frac{2}{5}$ हो तो a:b का मान ज्ञात कीजिए -

- (अ) 28:9 (ब) 30:9
(स) 9:28 (द) 10:28

उत्तर- (अ) 28:9

हल- $\frac{3a-4b}{3a+4b} = \frac{2}{5}$

$$\Rightarrow 5(3a-4b) = 2(3a+4b)$$

$$15a-6a = 8b+20b$$

$$9a = 28b$$

$$\frac{a}{b} = \frac{28}{9} \Rightarrow a:b = 28:9$$

6. (980 का 12%) - (450 का $x\%$) = 227 का 30% तब x का मान क्या होगा -

- (अ) 14 (ब) 17
(स) 11 (द) 8

उत्तर- (स) 11

हल-

$$450 \times \frac{x}{100} = \left(980 \times \frac{12}{100}\right) - \left(227 \times \frac{30}{100}\right)$$

$$= \frac{9x}{2} = (117.6 - 68.1) = 49.5$$

$$= x = (49.5 \times \frac{2}{9}) = 11$$

7. यदि $\frac{1}{N} = \left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{5}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}\right)$ है तो N का मान क्या होगा -

- (अ) $6-\sqrt{30}$ (ब) $6+\sqrt{30}$
(स) $11-2\sqrt{30}$ (द) $11+2\sqrt{5}$

उत्तर- (स) $11-2\sqrt{30}$

हल- $N = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5}}{\sqrt{6}+\sqrt{5}}$

$$N = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5}}{\sqrt{6}+\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$$

$$= \frac{(\sqrt{6}-\sqrt{5})^2}{(\sqrt{6}+\sqrt{5})(\sqrt{6}-\sqrt{5})}$$

$$= \frac{6+5-2(\sqrt{6})(\sqrt{5})}{6-5}$$

$$= N = 11-2\sqrt{30}$$

8. पहली 29 सम संख्याओं का औसत क्या है -

- (अ) 30 (ब) 31
(स) 32 (द) 33

उत्तर- (अ) 30

हल-

$$\therefore \text{प्रथम सम संख्याओं का योग} = n(n+1)$$

$$\therefore \text{पहली 29 सम संख्याओं का योग} = 29(29+1) = 29 \times 30$$

$$\therefore \text{अतः आवश्यक औसत} = \frac{29 \times 30}{29} = 30$$

9. यदि $x+x^{-1}=2$, तब x^3+x^{-3} का मान क्या होगा -

- (अ) 1 (ब) $\frac{1}{2}$
(स) 2 (द) 3

उत्तर- (अ) 1

हल-

$$\therefore \text{प्रथम सम संख्याओं का योग} = n(n+1)$$

$$\therefore \text{पहली 29 सम संख्याओं का योग} = 29(29+1) = 29 \times 30$$

$$\therefore \text{अतः आवश्यक औसत} = \frac{29 \times 30}{29} = 30$$

उत्तर- (अ) 1

हल-

$$\therefore \text{प्रथम सम संख्याओं का योग} = n(n+1)$$

$$\therefore \text{पहली 29 सम संख्याओं का योग} = 29(29+1) = 29 \times 30$$

$$\therefore \text{अतः आवश्यक औसत} = \frac{29 \times 30}{29} = 30$$

उत्तर- (स) 2

$$\text{हल- } x+x^{-1}=2 \Rightarrow x+\frac{1}{x}=2$$

$$\Rightarrow \left(x+\frac{1}{x}\right)^3 = 2^3 \Rightarrow x^3+\frac{1}{x^3}+6=8$$

$$\Rightarrow x^3+\frac{1}{x^3}=2$$

तार्किक क्षमता

1. किसी कोड भाषा में 'RIP' को 42 और 'MOL' को 39 लिखा जाता है। उसी समान कोड भाषा में 'GAN' के लिए क्या लिखा जाएगा -

- (अ) 21 (ब) 22
(स) 23 (द) 20

उत्तर- (अ) 21

हल- $RIP = 18+9+16 = 43-1 = 42$
 $MOL = 13+15+12 = 40-1 = 39$
 $GAN = 7+1+14 = 22-1 = 21$

2. अगला पद ज्ञात कीजिए -

- 279, 277, 273, 267, ?
(अ) 259 (ब) 261
(स) 257 (द) 263

उत्तर- (अ) 259

हल- -2, -4, -6, -8

निर्देश (3-4) नीचे दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।

3. (1) Rangle (2) Regal
(3) Royal (4) Room
(5) Rested

- (अ) 15432 (ब) 45312
(स) 12543 (द) 13542

उत्तर- (स) 12543

4. (1) Soul (2) Strain
(3) Syrup (4) Sand
(5) Strained

- (अ) 41253 (ब) 42153
(स) 54312 (द) 45312

उत्तर- (अ) 41253

5. नीचे दी गई आकृति में कौन सा अंक स्टील बॉटल को प्रदर्शित करता है जो कि कप है -

- (अ) 2 (ब) 4
(स) 3 (द) 6

उत्तर- (स) 3

6. एक घन की दो स्थितियों को नीचे दिखाया गया है। '1' वाले फलक के विपरीत फलक में कौन-सा अंक आयेगा -

- (अ) 4 या 5 (ब) 5
(स)



सूजी बेट्स

विश्वकप में सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाली खिलाड़ी बनीं

डुनेडिन, न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सूजी बेट्स ने आईसीसी महिला विश्वकप में बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। बेट्स महिला वन-डे विश्वकप में सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। बेट्स ने यह उपलब्धि बांग्लादेश के खिलाफ लीग मैच के दौरान हासिल की। बेट्स ने इस मैच में 68 गेंदों में 79 रनों की नाबाद पारी खेली। बेट्स के इस प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को सात विकेट से हराया। सूजी बेट्स ने आईसीसी महिला वन-डे विश्वकप में सबसे तेज एक हजार रन बनाने के लिये 21 पारियां खेलीं। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की वेलिंडा क्लार्क (22 पारी) के नाम था। बेट्स महिला वन-डे वर्ल्डकप में एक हजार रन बनाने वाली दुनिया की पांचवीं बल्लेबाज हैं।

विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों से हटीं मैरी कॉम

नई दिल्ली, भारत की अनुभवी महिला मुक्केबाज एम.सी. मैरी कॉम ने आगामी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और एशियाई खेल-2022 के लिये होने वाले ट्रायल से हटने का फैसला किया है। मैरी कॉम ने कहा कि उन्होंने यह फैसला युवा मुक्केबाजों को अधिक से अधिक मौके देने और राष्ट्रमंडल खेलों के लिये तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये लिया है। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि मैरी कॉम पिछले दो दशकों से भारतीय मुक्केबाजों के लिये मार्गदर्शक रही हैं। इस वर्ष महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 6 से 21 मई तक इस्तांबुल में आयोजित होगी। वहीं राष्ट्रमंडल खेल वर्मिंघम में 28 जुलाई से आयोजित किये जायेंगे। उल्लेखनीय है कि मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। मैरी कॉम ने एशियन चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं।

मध्यप्रदेश के पैराफेंसिंग खिलाड़ियों ने जीता कांस्य पदक

भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय पैराफेंसिंग चैंपियनशिप (व्हील चेयर तलवारबाजी) में मध्यप्रदेश के दीपक शर्मा, अरविन्द रजक और संजीव कोटिया ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। गुना जिले के दीपक शर्मा ने इंडिविजुअल ईपी इवेंट में कांस्य पदक जीता। दीपक पूर्व में भी कांस्य पदक अर्जित कर चुके हैं। साथ ही व्हील चेयर फेंसिंग वर्ल्डकप में भी देश का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश को गौरवान्वित कर चुके हैं। ईपी टीम इवेंट में दीपक शर्मा और ग्वालियर से अरविंद रजक एवं संजीव कोटिया ने संयुक्त कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता की तैयारी में मध्यप्रदेश के फेंसिंग कोच भूपेंद्र सिंह चौहान का सराहनीय योगदान रहा।

श्रीसंत ने क्रिकेट से लिया संन्यास

मुंबई, भारत के तेज गेंदबाज शांताकुमारन श्रीसंत ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। श्रीसंत ने सोशल मीडिया के जरिये क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। श्रीसंत रणजी ट्रॉफी में केरल की ओर से खेल रहे थे। श्रीसंत ने मेघालय के खिलाफ मैच में 2 विकेट लिये थे। श्रीसंत वर्ष 2007 में आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्वकप तथा वर्ष 2011 में आईसीसी वन-डे विश्वकप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे हैं।

भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज

भारत ने श्रीलंका को पारी और 222 रनों से हराया



दिमुथ करुणारत्ने और लाहिरू थिरिमाने ने श्रीलंका को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिये 48 रन जोड़े। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद श्रीलंका की पारी बिखर गई। हालांकि युवा बल्लेबाज पथुम निसांका (61) एक छोर पर डटे रहे, लेकिन दूसरे छोर पर कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाया। श्रीलंका की टीम ने पहली पारी में 174 रन बनाये।

भारत ने 400 रनों की विशाल बढ़त हासिल करने के बाद श्रीलंका को फॉलोऑन दिया। फॉलोऑन खेलने उतरी श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन एक बार फिर स्तरहीन नजर आया। दूसरी पारी में श्रीलंका की टीम 178 रन बनाकर आउट हो गई।

जडेजा बने नंबर वन ऑलराउंडर

मैच में रविंद्र जडेजा ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी में शतक बनाने वाले जडेजा गेंदबाजी में भी छाए रहे। जडेजा ने पहली पारी में 5 तथा दूसरी पारी में 4 सहित कुल 9 विकेट लिये। जडेजा अगर मैच में एक और विकेट झटक

भारत ने डेविस कप में विश्व ग्रुप-वन में बनाई जगह

नई दिल्ली, भारतीय टेनिस खिलाड़ियों ने डेविस कप में शानदार प्रदर्शन करते हुये विश्व ग्रुप-वन में जगह बना ली है। भारत ने डेविस कप में वर्ल्ड ग्रुप प्ले ऑफ मुकाबले में डेनमार्क को 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया।

रामनाथन और भांबरी ने जीते एकल मुकाबले

भारत और डेनमार्क के बीच डेविस कप का पहला एकल मुकाबला रामकुमार रामनाथन और क्रिस्टियन सिग्मार्ड के बीच खेला गया। रामनाथन ने यह मुकाबला सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से आसानी से जीता, इसके बाद दूसरे एकल मुकाबले में युकी भांबरी ने मिकेल टोर्पेगाई को 6-4, 6-4 से हराकर भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया।

इसके बाद युगल मुकाबले में रोहन बोपन्ना और दिविज शरण की भारतीय जोड़ी

का सामना फ्रेडरिक नील्सन और मिकेल टोर्पेगाई की जोड़ी से हुआ। भारत की इस जोड़ी को डेनिस जोड़ी से कड़ी टक्कर मिली। डेनिस जोड़ी ने पहला टाईब्रेकर में 7-6 से जीता। इसके बाद दूसरे सेट में भारतीय जोड़ी ने जबरदस्त वापसी करते हुये 6-4 से सेट जीता। मैच के तीसरे और निर्णायक सेट में भारतीय जोड़ी ने बेहतरीन खेल दिखाया और टाईब्रेकर में 7-6 से सेट जीतकर भारत की बढ़त 3-0 कर दी।

इस जीत के बाद भारत की जीत सुनिश्चित हो गई। इसके बाद पहले रिवर्स एकल मुकाबले में रामकुमार रामनाथन ने जोहानेस इंगिल्डसन को 5-7, 7-5, 10-7 से हराकर डेनमार्क को क्लीन स्वीप कर दिया। इसके बाद दूसरे रिवर्स एकल मुकाबले की जरूरत ही नहीं पड़ी। विश्व ग्रुप-वन के मुकाबले 16 से 18 सितम्बर तक खेले जायेंगे।

एमसीसी ने

क्रिकेट के नियमों में किया बदलाव

लंदन, विश्व क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने क्रिकेट के नियमों में बदलाव किये हैं। एमसीसी ने कहा कि नये नियम एक अक्टूबर, 2022 से लागू होंगे।

कैच आउट नियम में बदलाव

नये नियम के तहत अब किसी खिलाड़ी के आउट होने के बाद मैदान में आया बल्लेबाज ही स्ट्राइक पर रहेगा। पहले कैच आउट के दौरान अगर दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट कर लेते हैं, तो नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर छोर पर रहता है। लेकिन अब कैच आउट पर नया बल्लेबाज ही अगली गेंद खेलेगा। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर कैच आउट होता है, तो स्ट्राइक रोटेट होगी।

गेंद पर लार का इस्तेमाल होगा प्रतिबंधित

एमसीसी ने मैच के दौरान गेंद को



चमकाने के लिये लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। एमसीसी ने कोरोना काल में संक्रमण की संभावना को देखते हुये लार पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन यह देखा गया कि लार के उपयोग न करने से गेंद के स्विंग होने पर कोई फर्क नहीं है, तो इस प्रतिबंध को स्थायी बनाया गया है।

मांकडिंग को माना जायेगा रन आउट

एमसीसी ने मांकडिंग को वैध माना है। पहले मांकडिंग को खेल भावना के विपरीत माना जाता था, लेकिन अब इसे

- यह पूर्व कप्तान विराट कोहली के टेस्ट कैरियर का 100वां टेस्ट मैच था।
- विराट 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं।
- टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिये सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में रविचंद्रन अश्विन दूसरे स्थान पर आ गये हैं।
- अश्विन ने भारत के लिये 436 टेस्ट विकेट लिये हैं, उन्होंने कपिल देव (434) को पीछे छोड़ दिया है।
- टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिये सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले (619) के नाम है।
- अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में नौवें स्थान पर हैं।
- रोहित शर्मा बतौर कप्तान अपने पहले टेस्ट मैच में जीत दर्ज करने वाले 10वें भारतीय कप्तान हैं।

लेते तो वे विश्व के पहले खिलाड़ी बन जाते जिसने एक मैच में शतक और 10 विकेट लेने का कारनामा किया हो। जडेजा महज एक विकेट से विश्व रिकॉर्ड बनाने से चूक गये। हालांकि जडेजा को इस बेहतरीन प्रदर्शन का इनाम मिला है। जडेजा आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गये हैं। ऑलराउंडर रैंकिंग में जडेजा 406 अंक लेकर पहले स्थान पर है। वहीं वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर दूसरे तथा अश्विन तीसरे स्थान पर हैं।

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न का निधन

बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया है। 52 वर्षीय वॉर्न की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। शेन वॉर्न के प्रबंधन का काम देखने वाली कंपनी ने उनकी मृत्यु की जानकारी देते हुये बताया कि वॉर्न थाईलैंड के कोह समुई स्थित अपने विला में बेहोश पाये गये। इसके बाद वॉर्न को तुरंत मेडिकल सहायता पहुंचाई गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ लेग स्पिनरों में से एक माने जाते हैं। अपने 15 साल के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में वॉर्न ने 708 टेस्ट विकेट लिये थे। वॉर्न ने 4 जून 1993 में एशेज सीरीज के दौरान इंग्लैंड के माड्रिग गेटिंग को एक अद्भुत गेंद पर बोल्ट किया। इस गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। वॉर्न ने यह गेंद लेग स्टंप के बाहर फेंकी जो 90 डिग्री टर्न लेते हुये ऑफ स्टंप

सरदार सिंह बने भारतीय पुरुष-ए हॉकी टीम के कोच

नई दिल्ली, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह भारतीय पुरुष-ए हॉकी टीम के कोच नियुक्त किये गये हैं। वहीं सरदार सिंह के टीम साथी दीपक ठाकुर को महिला-ए हॉकी टीम का कोच बनाया गया है। ये दोनों खिलाड़ी वर्मिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाली भारतीय टीम को प्रशिक्षित करेंगे। हॉकी इंडिया ने बताया कि राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के बीच काफी कम समय है। ऐसे में राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी मुख्य टीमों की जगह ए टीमों भेजने का फैसला किया है। हॉकी इंडिया ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिये भारत-ए पुरुष और महिला टीम के लिये 33-33 संभावित खिलाड़ियों का चयन भी किया है। हॉकी इंडिया एशियाई खेलों में महिला एवं पुरुष वर्ग में मुख्य टीम भेजेगा।

दक्षिण अफ्रीका से पांच मैचों की ट्वेंटी-20 सीरीज खेलेगा भारत

मुंबई, भारतीय क्रिकेट टीम इस वर्ष जून में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की ट्वेंटी-20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज का आयोजन आईपीएल-2022 के तुरंत बाद किया जायेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस सीरीज का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। बीसीसीआई के अनुसार सीरीज का पहला मैच 9 जून को चेन्नई में, दूसरा मैच 12 जून को बेंगलुरु में, तीसरा मैच 14 जून को नागपुर में, चौथा मैच 17 जून को राजकोट में और सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच 19 जून को दिल्ली में खेला जायेगा। इस सीरीज के बाद भारत जून के आखिर में दो मैचों की ट्वेंटी-20 सीरीज के लिये आयरलैंड का दौरा करेगा।



उड़ा ले गई और गेटिंग देखते रह गये। शेन वॉर्न का क्रिकेट कैरियर बेहद शानदार रहा है। वॉर्न ने जनवरी 1992 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था। वहीं पहला वन-डे 24 मार्च 1993 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। वॉर्न ने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट तथा 3154 रन बनाये हैं। वहीं 194 वन-डे मैचों में वॉर्न ने 293 विकेट लिये हैं।

बीसीसीआई ने जारी की खिलाड़ियों की अनुबंध सूची

मुंबई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम इंडिया के लिये नया केंद्रीय अनुबंध जारी कर दिया है। नई अनुबंध सूची में कई दिग्गज खिलाड़ियों को डिमोट किया गया है। नई अनुबंध सूची में अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को ए ग्रेड से हटाकर बी ग्रेड में रखा गया है, वहीं हार्दिक पंड्या ए ग्रेड से सी ग्रेड में आ गये हैं। बीसीसीआई ने ए प्लस ग्रेड में तीन, ए ग्रेड में पांच, बी ग्रेड में सात और सी ग्रेड में 10 खिलाड़ियों को रखा है। ए प्लस ग्रेड के खिलाड़ियों को सात करोड़, ए ग्रेड के खिलाड़ियों को पांच करोड़, बी ग्रेड के खिलाड़ियों को तीन करोड़ तथा सी ग्रेड के खिलाड़ियों को एक करोड़ रुपये सालाना मिलेंगे।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गुगल से साभार)



सामयिकी

पांच राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित

भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड, मणिपुर और गोवा में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित कर दिए हैं।



उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। इन तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनायेगी। गोवा में भारतीय जनता पार्टी को 40 सदस्यीय सदन में 20 सीटें मिली हैं। यहां भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनायेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) ने बड़ी सफलता हासिल की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी।

(अमेरिका और 10 देशों ने)

उत्तर कोरिया मिसाइल प्रक्षेपण की निंदा की

अमेरिका और 10 अन्य देशों ने उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में

- उत्तर कोरिया ने समुद्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। यह जानकारी उसके पड़ोसी देश ने दी। यह इस साल की शुरुआत से उत्तर कोरिया का 11वां बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण है।

कार्रवाई करने का आग्रह किया। इन देशों ने कहा कि इस मामले में निष्क्रियता से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की विश्वसनीयता को नुकसान होता है और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के वैश्विक प्रयास कमजोर होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने इस मामले में सुरक्षा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'वित्त और आकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण' विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सदी में एक बार आने वाली महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर गति पकड़ रही है और यह हमारे आर्थिक निर्णयों और अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार ने तेज़ गति के मोमेंटम को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, 'फॉरेन कैपिटल फ्लो को प्रोत्साहित करके, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कम करके, एनआईआईएफ, गिफ्ट सिटी, नए डीएफआईएस जैसे संस्थान बनाकर हमने फाइनेंसियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज गति देने का प्रयास किया है।' प्रधानमंत्री ने कहा 'वित्त में डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के लिए देश की प्रतिबद्धता अब अगले स्तर पर पहुंच रही है। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां हों या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी), वे हमारी दृष्टि को दर्शाते हैं।'।

प्रधानमंत्री ने भारत की आकांक्षाओं और एमएसएमई की ताकत के बीच की कड़ी पर जोर दिया। उन्होंने कहा,



“एमएसएमई को मजबूत बनाने के लिए हमने बहुत से फंडामेंटल रिफॉर्म किए हैं और नई योजनाएं बनाई हैं। इन रिफॉर्म की सक्सेस, इनकी फाइनेंसिंग को मजबूत करने पर निर्भर है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक देश फिनटेक, एग्रीटेक, मेडिटेक और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ता, तब तक उद्योग 4.0 संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में वित्तीय संस्थानों की मदद से भारत उद्योग 4.0 में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।

उन्होंने ने पूछा कि क्या भारत निर्माण, स्टार्टअप, हाल ही में खोले गए क्षेत्रों जैसे

चीन ने की रूस पर प्रतिबंधों की आलोचना

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ लगाए जा रहे प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए कहा कि इसका सभी को नुकसान होगा। चीन के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी ने बताया कि जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुएल मैक्रों व जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ट्ज के साथ रूस-यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की। इस दौरान जिनपिंग ने युद्ध को लेकर गहरी चिंता व दुःख जताते हुए दोनों पक्षों से वार्ता शुरू करने का आग्रह किया और कहा कि चीन इसमें भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सीसीटीवी ने जिनपिंग के हवाले से कहा, 'हम इस संकट के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए एक साथ प्रयास करना चाहते हैं। प्रतिबंधों का वैश्विक वित्त, ऊर्जा संसाधनों, परिवहन व आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव पड़ेगा।

(विश्व बैंक ने)

यूक्रेन के लिए कर्ज और अनुदान को दी मंजूरी

विश्व बैंक ने कहा कि उसके कार्यकारी बोर्ड ने यूक्रेन के लिए कर्ज व अनुदान के रूप 72.3 करोड़ डॉलर के पैकेज को मंजूरी

- बैंक ने एक बयान में कहा कि फाइनेंसिंग ऑफ रिकवरी फ्रॉम इकोनॉमिक इमरजेंसी इन यूक्रेन (फ्री यूक्रेन) नामक पैकेज में 48.9 करोड़ डॉलर के पूरक बजट का प्रावधान किया गया है।

दे दी है। बयान के अनुसार, 'पैकेज में 35 करोड़ डॉलर का पूरक कर्ज, 13.9 करोड़ डॉलर की गारंटी, 13.4 करोड़ डॉलर की मोबलाइजिंग ग्रांट (निर्गत राशि) व 10 करोड़ डॉलर की पैरलल ग्रांट (आरक्षित राशि) समेत कुल 72.3 करोड़ डॉलर सहायता शामिल है।

बैंक ने कहा कि यह राशि यूक्रेन सरकार को अहम सेवाओं को जारी रखने, अस्पताल के कर्मचारियों व पेंशनधारियों को भुगतान तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के संचालन में मदद करेगी। उसने बताया कि नीदरलैंड्स (8.9 करोड़ डॉलर) व स्वीडन (पांच करोड़ डॉलर) की गारंटी पर विश्व बैंक ने प्रारंभिक सहायता राशि में इजाफा



किया है। बैंक ने यूक्रेन के लिए मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड की स्थापना की है, जिसमें ब्रिटेन, डेनमार्क, लातविया, लिथुआनिया व आइसलैंड 13.4 करोड़ डॉलर दान कर चुके हैं। इसके अलावा जापान ने 10 करोड़ डॉलर की पैरलल ग्रांट उपलब्ध कराई है।

क्वाड नेताओं ने यूक्रेन संकट पर चर्चा की

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड के नेताओं के साथ सकारात्मक बातचीत की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक क्वाड नेता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापानी प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक वर्चुअल बैठक में यूक्रेन पर रूस के हमले

पर गहन विचार-विमर्श किया। साथ ही इस पूर्वी यूरोपीय देश पर छाप मानवाधिकार संकट को लेकर चिंता जताई। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति मानते हैं कि बातचीत काफी सकारात्मक रही है। क्वाड नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला रखने की जरूरत है। साथ ही सभी ने इस बात की सहमति जताई की सभी सदस्य अगले साल जापान में व्यक्तिगत रूप से शामिल होकर बैठक करेंगे। बैठक के बाद बाइडेन ने ट्वीट करके बताया कि वह क्वाड नेताओं के अपने साथियों पीएम स्कॉट मॉरिसन, प्रधानमंत्री मोदी और पीएम किशिदा से मिले। साथ ही यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध छेड़ने के मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि हम सभी हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र समेत विश्व के सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। बाइडेन ने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के बाद सदस्य देशों के एनएसए की भी बैठक होनी चाहिए।

बजट उपरांत वेबिनार

भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार है ग्रामीण अर्थव्यवस्था - प्रधानमंत्री

अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। सरकार एसएचजी, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान उत्पादक संगठन और कॉमन सर्विस सेंटर को मजबूत करने जैसे कदम उठा रही है। उन्होंने उपस्थित लोगों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपनी नीतियों के केंद्र में रखने के लिए कहा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एस्पिरेशंस, नेचुरल फार्मिंग से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी है और “अगर कोई इनमें नया काम करने के लिए आगे आ रहा है, तो हमारे फाइनेंसियल इस्टिम्ब्यूशन उसे कैसे मदद करें, इसके बारे में सोचा जाना आवश्यक है।” उन्होंने ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक चिकित्सा संस्थानों का होना जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने बजट के पर्यावरण और सिस्टम के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। देश में इसके लिए काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, इन कार्यों को गति देने के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट को गति देना आवश्यक है। ग्रीन फाइनेंसिंग और ऐसे नए आस्पेक्ट की स्टडी और इंप्लीमेंटेशन समय की मांग है।

(भारत सरकार के)

आठ मंत्रालयों में ई-बिल लागू हुआ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि नई इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रसंस्करण प्रणाली से सरकारी विभागों के

- वित्त मंत्री ने कहा कि ई-बिल आने से खास लाभ उठाने की छोटी सी गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी।
- उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दावा पेश करने के बाद ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता को सरकारी दफ्तर आने की जरूरत नहीं रहेगी।

ठेकेदारों या आपूर्तिकर्ताओं को बकाया राशि जारी करने में किसी भी खास लाभ की मांग होनी बंद हो जाएगी।

बजट में घोषित ई-बिल प्रणाली की पायलट स्तर पर आठ मंत्रालयों में शुरुआत की गई। अगले वित्त वर्ष में इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में लागू किया

(मेराज 504 आत्मघाती ड्रोन)

ईरान ने दुनिया को पहली बार दिखाया

रूस-यूक्रेन जंग के बीच ईरान ने शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ईरान के इस्लामिक रिवाल्व्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक

- ईरान ने अपने नये ड्रोन को पहली बार किया प्रदर्शित।
- मेराज 504 नाम का यह ड्रोन 100 कि.मी. तक उड़ान भरने में सक्षम।
- यह 2.5 किलोग्राम विस्फोटकों के साथ लक्ष्य पर कर सकता है आत्मघाती हमला।

नये कामिकेज ड्रोन को पहली बार दुनिया के सामने रखा है। यह ड्रोन 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला और रेकी करने में सक्षम है। इस ड्रोन के अंदर विस्फोटक लगे होते हैं, जो लक्ष्य से खुद को टकराकर उसे बर्बाद कर देते हैं। कई साल की अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के कारण ईरान विदेशों से हथियार नहीं खरीद पाया है। जिसके बाद उसने स्वदेशी तौर पर बड़ी संख्या में हल्के ड्रोन की सीरीज को विकसित करने का काम किया है। इनमें से कई छोटे और धीमी गति से उड़ने वाले टोही ड्रोन से लेकर लंबी दूरी तक उड़ान



जाएगा। इसकी मदद से सरकार के ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता अपने दावे ऑनलाइन ही जमा कर पाएंगे। इन दावों के निस्तारण की प्रक्रिया पर ऑनलाइन नजर भी रखी जा सकेगी। वित्त मंत्री ने 46वें सिविल अकाउंट दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ई-बिल प्रणाली से हर स्तर पर डिजिटलीकरण सुनिश्चित हो जाएगा और भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी होगी। उन्होंने कहा कि इसे आगे चलकर सरकारी विभागों के अलावा नागरिक सेवाओं में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।



भरने में सक्षम जेट इंजनों से लैस हैं। इस ड्रोन की पहली तस्वीर को ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तसनीम ने जारी किया है। ड्रोन को तेहरान में एक डिफेंस एक्सपोजे के दौरान प्रदर्शित किया गया था। दावा किया गया है कि यह ड्रोन 2.5 किलोग्राम तक के विस्फोटकों को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। यह ड्रोन एक बार में 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक उड़ान भर सकता है। आकार में छोटा और कम लागत वाला यह ड्रोन एक पिस्टन इंजन से संचालित है। इसे दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गुगल से साभार)